R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 । अंक : 15
01 से 15 मई 2025
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

पहलगाम आतंकी हमला

नहीं सुधरेगा आतंकिस्तान...
सबक सिखाएगा हिंदुस्तान

पाकिस्तान को मिलेगा धरती, समंदर, आसमान से करारा जवाब

न खाने को चावल, न पीने को पानी, जीडीपी का भी बंटाधार

स्वस्थ रहें... मस्त रहें
जनहित में जारी
जीवन हमारा है... तो
जिम्मेदारी भी हमारी
सावधानी बरतें
मच्छरों से बचें।
साफ-सफाई पर ध्यान दें।
घर के आसपास कचरा न करें।
ढंके हुए पानी का उपयोग करें।
बीमारी पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, लापरवाही न करें।
शौच के लिए शौचालय का ही इस्तेमाल करें।
फारूकी ब्रदर्स, इंदौर (मध्यप्रदेश)

इस अंक में

लालफीताशाही

8 | सख्त प्रावधान... फिर भी अवैध...

मप्र में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को लेकर सरकार ने सख्त नियमों और सजा का प्रावधान किया है। उसके बावजूद अवैध कॉलोनियों में अधोसंरचना विकास और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ऐसे में सवाल...

डायरी

10-11 | महीनेभर होंगे तबादले

मप्र में तीन साल बाद तबादलों पर से प्रतिबंध हटा है। मप्र की डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में 1 मई से 30 मई तक तबादले करने को हरी झंडी मिल गई है। जीएडी के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने जो तबादला नीति मंजूर की...

पहल

14 | आईएएस अफसरों...

मप्र आज देश में विकास का आईना बना हुआ है। यहां की जनता अपनी सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर खुशहाल हो रही है। इसके पीछे आईएएस अफसरों के नवाचार का बड़ा योगदान है। प्रदेश के आईएएस अफसरों ने कई...

अपराध

18 | भोपाल में अजमेर 92 जैसा कांड...

मप्र की राजधानी भोपाल में 1992 के कुख्यात अजमेर रेप कांड जैसा एक और संगीन मामला सामने आया है, जिसने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। रायसेन रोड स्थित एक प्राइवेट कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के एक गिरोह ने हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

22 अप्रैल को जिस कायराना तरीके से पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछ-पूछकर 26 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया, उससे यह साबित हो गया कि आतंकिस्तान (पाकिस्तान) सुधरने वाला नहीं है। भारत आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा।

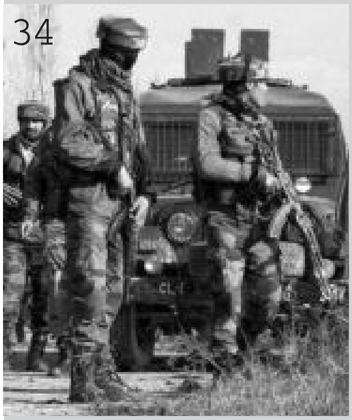
34

36

44

45

राजनीति

30-31 | राहुल के फॉर्मूला...

आने वाले दिनों के लिए कांग्रेस का फ्यूचर प्लान क्या है, ये राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस का फ्यूचर राहुल गांधी के फ्यूचर प्लान पर ही टिका है। कांग्रेस 2014 से सत्ता से बाहर है और अभी उसे 2029 तक सत्ता से बाहर ही रहना है। सत्तारूढ़ होने के...

महाराष्ट्र

35 | तैयार हो रही नई चुनावी पिच

शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की उंगली पकड़कर राज ठाकरे राजनीति में आए थे। राज ठाकरे को एक समय बालासाहेब के सियासी वारिस के तौर पर भी देखा जा रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे के सक्रिय होने के बाद राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना...

बिहार

38 | फॉर्मूला 70... कौन देगा...

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सबसे बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। बिहार के पूर्व...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-15, पृष्ठ-48
1 से 15 मई, 2025

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना अनूप यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

माननीयों को सैल्यूट...हंगामा क्यों है बरपा...?

मुजफ्फर वारसी का एक शेर है...

औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी
और अपने गरेबान में झांका नहीं जाता

लाखों मतदाता मिलकर जिस जनप्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा और विधानसभा में भेजते हैं, उनके मान-सम्मान को देखते हुए मप्र में व्यवस्था की गई है कि पुलिस अब उनको भी सैल्यूट करेगी। इस संदर्भ में पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ शिष्ट व्यवहार में कमी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं अगर सांसद और विधायक मिलने आएं तो पुलिस अफसरों को प्राथमिकता के आधार पर मुलाकात कर उनकी बात सुननी होगी। सुशासन की राह पर चल रही सरकार के इस कदम का कुछ राजनीतिक लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी जनप्रतिनिधि को सम्मान देना कहां गलत है? हमारी सनातन संस्कृति और धर्मों में हर व्यक्ति का मान-सम्मान करने की परंपरा है। धर्म और इतिहास में इस तरह के उदाहरण भरे पड़े हैं। ऐसे में जब हम राम राज्य स्थापित करने की परिकल्पना करते हैं तो राम राज्य के आदर्शों को अपनाने में क्यों हंगामा मचा है। कुछ लोगों द्वारा माननीयों की आपराधिक पृष्ठभूमि का हवाला देकर उनके मान-सम्मान पर सवाल उठाया जा रहा है। भई... जिस व्यक्ति को लाखों मतदाताओं ने अपना बहुमूल्य वोट देकर सदन में भेजा है, उसे सम्मान देना देश के मतदाताओं को सम्मान देने जैसा है। इसलिए मप्र पुलिस के मुखिया ने माननीयों के सम्मान के लिए पुलिस को जो आदेश दिया है, वह भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही एक अंग है। जब हमारी पुलिस के अंदर ऐसे आदर्श समाहित रहेंगे तो वह अपने कर्त्तव्य का पालन अच्छे तरीके से करेगी। इसलिए ऐसे दिशा-निर्देशों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अक्सर हमें सुनने में आता है कि लाखों लोगों द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि का अमूक जगह पर अपमान हो गया। यह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उन लाखों लोगों का अपमान है, जो उन्हें चुनकर भेजते हैं। इसलिए पुलिस महानिदेशक का यह कदम सराहनीय है। गौरतलब है कि डीजीपी ने यह भी कहा है कि सांसदों, विधायकों द्वारा जब भी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से मोबाइल या फोन पर जनसमस्या को लेकर संपर्क किया जाता है तो अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी कि संवाद के दौरान ध्यान से उनकी बात सुनेंगे और शिष्टता के साथ जवाब देंगे। डीजीपी ने सांसदों-विधायकों के सम्मान को लेकर जारी निर्देश में 8 अलग-अलग परिपत्रों का जिक्र किया है। ये सर्कुलर पुलिस अफसरों के लिए 23 जनवरी 2004, 18 मई 2007, 22 मार्च 2011, 24 अक्टूबर 2017, 19 जुलाई 2019, 11 दिसंबर 2019, 12 नवंबर 2021 और 4 अप्रैल 2022 को शासन की ओर से जारी किए गए हैं। चार महीने पहले पूर्व डीजीपी सुधीर सक्सेना के रिटायरमेंट से ठीक पहले एक सर्कुलर स्पेशल डीजी शैलेष सिंह की ओर से जारी किया गया था। इसमें 2007 के सर्कुलर का जिक्र कर कहा गया था कि मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य पुलिस अफसरों को सलामी परेड देने की परंपरा खत्म कर दी गई है। सिर्फ राज्यपाल को ही सलामी दी जा सकती है। यह पत्र सभी रेंज आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया था। इसके चलते पूर्व डीजीपी की सेवानिवृत्ति पर बगैर सलामी परेड के ही विदाई हुई थी। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए वर्तमान पुलिस महानिदेशक ने सम्मान की परंपरा को कायम रखते हुए जनप्रतिनिधियों को पुलिस द्वारा सम्मान स्वरूप सैल्यूट करने का जो निर्देश जारी किया है, उससे पूरे विश्वभर में भारत की सुशासन व्यवस्था की एक बेहतर तस्वीर उभरकर सामने आएगी। इससे लोगों में पुलिस के प्रति भी सम्मान का भाव जागृत होगा।

- राजेन्द्र आगाल

भारत के लिए गर्व की बात

भारत ने जीडीपी के ग्रोथ रेट के मामले में मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 9 वर्षों के दौरान पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ा है। दुनिया के अर्थव्यवस्था में भारत की योगदान की चर्चा करें तो 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में 15 फीसदी का योगदान करेगा। यह भारत के लिए गर्व की बात है।

● **मंजू साहू,** रायसेन (म.प्र.)

कब खत्म होगा भ्रष्टाचार ?

आज के समय में भ्रष्टाचार दीमक की तरह फैला हुआ है। प्रदेश ही नहीं देशभर में नेताओं और सरकारी अफसरों पर कई केस भी हुए हैं। लेकिन अभी तक इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

● **प्रियंका दांगी,** ब्यावरा (म.प्र.)

मजबूत हो विपक्ष

मप्र में पिछले दो दशकों में कांग्रेस की चुनावी हार का एक बड़ा कारण यह रहा है कि प्रदेश संगठन का संपर्क सिर्फ जिला और ब्लॉक स्तर तक सीमित रहा, जबकि बूथ इकाइयों को मजबूत करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस को प्रदेश में खुद को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।

● **राकेश सिंह,** बैतूल (म.प्र.)

किसानों की समस्या का समाधान निकाले सरकार

मप्र के अन्नदाता पर कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी प्रशासनिक लापरवाही की मार पड़ रही है। इस समय प्रदेश में गेहूं की कटाई का मौसम है, लेकिन किसानों की खड़ी फसल पर एक बड़े संकट के रूप में आग का संकट मंडरा रहा है। प्रदेशभर में खड़ी फसल में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और किसानों के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। मप्र का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां आग लगने की घटनाएं सामने नहीं आई हैं। प्रदेश में पिछले एक माह के दौरान आगजनी की करीब 5,430 घटनाओं से किसानों की हजारों एकड़ फसल खाक हो गई है। इससे किसानों को करोड़ों रुपए की हानि हुई है। सरकार को किसानों के बारे कुछ सोचना चाहिए और इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए।

● **वर्षा नागरे,** नीमच (म.प्र.)

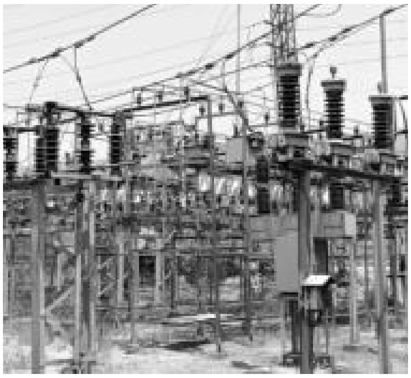

बिजली चोरी पर रोक लगे

प्रदेशभर के कई क्षेत्रों में आए दिन बिजली चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। दरअसल शहर हो या गांव सभी जगह झुग्गियों में जमकर अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में ही दो दर्जन से अधिक ऐसी बस्तियां हैं, जहां पर खंभों या फिर ट्रांसफार्मर से सीधे बिजली के तार डालकर दिन-रात बिजली चोरी की जाती है। सरकार को इस मामले में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।

● **भालेंद्र राजपूत,** मंदसौर (म.प्र.)

मोदी सरकार से न्याय की आस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के मामले में बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के 17 साल बाद आखिरकार वो वक्त मोदी सरकार के दौरान ही आया, जबकि हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया है। अब देशभर की जनता मोदी सरकार से उम्मीद लगाकर बैठी है कि भारत के अन्य दुश्मनों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलाई जाए।

● **पुनीत कुमार,** भोपाल (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

सोशल मीडिया के सहारे मायावती

बहुजन समाज पार्टी, जो कभी 2007 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, अब राजनीति के हाशिए पर खड़ी दिखती है। लेकिन मायावती, जो अपनी चुप्पी के लिए प्रसिद्ध हैं, इस बार तकनीक और युवाओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब जिलावार युवा सोशल नेटवर्क्स की सूची बना रही है जिन्हें अगले चुनाव में रणनीतिक रूप से मैदान में उतारा जा सकता है। 1990 के दशक में कांशीराम के नेतृत्व में बसपा ने जिस जमीनी आंदोलन से राजनीतिक ताकत पाई थी, उस ऊर्जा को मायावती अब डिजिटल माध्यम से दोहराना चाहती हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या एकदम शांत पड़ी बसपा, केवल डिजिटल उपस्थिति से फिर से मैदान में वापसी कर सकती है? राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो अब बसपा अपना खोया रुतबा वापस नहीं ला पाएगी, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी प्रमुख मायावती स्पष्ट तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दबाव में हैं और खुलकर भाजपा का विरोध नहीं कर पा रही हैं।

दोहराया जाएगा आडवाणी युग का अंतकाल?

भारतीय जनता पार्टी के भीतर इन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर गहरी सरगर्मी है। नड्डा युग अपने समापन की ओर बढ़ रहा है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की पटकथा लगभग तैयार मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, जो संगठनात्मक संतुलन और भविष्य की चुनावी रणनीतियों को लेकर बेहद सजग रहते हैं, अब दक्षिण भारत से एक प्रभावशाली और अनुशासित नेता को यह पद सौंप सकते हैं। इससे पहले भी 2005 में जब अटल-आडवाणी युग का धीरे-धीरे पटाक्षेप हो रहा था, तब भाजपा ने नितिन गडकरी जैसे अपेक्षाकृत कम चर्चित पर कुशल संगठनकर्ता को अध्यक्ष बनाकर चौंकाया था। आज फिर पार्टी ऐसा ही कुछ कर सकती है, प्रहलाद जोशी, बीएल संतोष या भूपेंद्र यादव जैसे नाम हवा में तैर रहे हैं। संकेत यही हैं कि भाजपा अब भावनाओं से अधिक संगठन कौशल और सांस्कृतिक सामंजस्य को तरजीह देगी।

ठीक चुनाव से पहले हटेंगे नीतीश?

बिहार की राजनीति कभी स्थिर नहीं रही और शायद यही इसकी जीवंतता है। नीतीश कुमार, जो 2005 से समय-समय पर एनडीए और महागठबंधन के बीच राजनीतिक पेंडुलम बनकर झूलते रहे हैं, अब खुद ही असहज महसूस कर रहे हैं। अंदरूनी सूत्रों की मानें तो भाजपा के कुछ रणनीतिकार महाराष्ट्र मॉडल को बिहार में दोहराने की संभावनाएं टटोल रहे हैं। 2005 में जिस नीतीश ने लालू प्रसाद की सत्ता को उखाड़ फेंका था, आज उसी नीतीश को गठबंधन में खुद की उपयोगिता पर सफाई देनी पड़ रही है। सम्राट चौधरी, जो भाजपा में आक्रामक भाषण शैली और सामाजिक समीकरणों के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं, धीरे-धीरे भाजपा के चेहरे के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट बदलती है या नहीं।

महाराष्ट्र में गठबंधनों की नई बिसात

महाराष्ट्र की राजनीति में रिश्ते जितनी तेजी से बनते हैं, उतनी ही तेजी से बिगड़ भी जाते हैं। एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की हालिया डिनर डिप्लोमेसी ने राजनीतिक विश्लेषकों को फिर से 2006 की याद दिला दी, जब एमएनएस का गठन हुआ था और ठाकरे परिवार दो खेमों में बंट गया था। एक समय था जब राज ठाकरे बाल ठाकरे के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाते थे, लेकिन बाद में अलग होकर उन्होंने नया मोर्चा खोला। आज जब शिंदे ठाकरे शिवसेना से अलग होकर सत्ता में हैं और राज ठाकरे की पार्टी संघर्षरत है तो यह समीकरण दोनों को लाभकारी लग सकता है। बीएमसी चुनाव सिर पर हैं और दोनों पार्टियों के लिए एक-दूसरे का साथ, मराठी वोटबैंक को फिर से साधने का हथियार बन सकता है। सवाल ये है कि क्या जनता इस दोबारा जोड़ी गई जोड़ी पर फिर से भरोसा करेगी?

केजरीवाल का अवसानकाल

वर्ष 2012 में जो आंदोलन से उपजी थी, वही आम आदमी पार्टी अब धीरे-धीरे चुनावी परिपक्वता की राह पर है, लेकिन शायद थकी हुई भी। दिल्ली नगर निगम चुनाव में हार के बाद पार्टी न केवल राजनीतिक मोर्चे पर, बल्कि नेतृत्व संरचना को लेकर भी पसोपेश में है। अतीत में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी ने पार्टी को उभार दिया था, लेकिन अब दोनों ही कानूनी मामलों और जन असंतोष से घिरे हैं। 2015 और 2020 की जीत के बाद आत्ममुग्धता ने पार्टी को विचारधारा से दूर कर दिया और अब वही शून्यता उसे अंदर से खा रही है। गोपाल राय, आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे नेता भले जुझारू हों, लेकिन उनका जनाधार सीमित है। पार्टी अब इस बात को लेकर असमंजस में है कि संस्थापक नेतृत्व पर भरोसा बनाए रखे या बदलाव को स्वीकार करे।

अभी नहीं होगा साय मंत्रिमंडल विस्तार!

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार में पिछले कुछ दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तरह-तरह की अटकलें थीं। साय भी गाहे-बगाहे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शीघ्र होगा कहकर बयान भी आते रहे हैं। अब चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जून तक के लिए टल गया है। क्योंकि साय सरकार का सुशासन त्यौहार शुरू हो गया है। इसमें मंत्री से लेकर भाजपा के पदाधिकारी और विभागों के आला अधिकारी से लेकर निचले स्तर के कर्मचारी तक व्यस्त रहेंगे। सुशासन त्यौहार में फिलहाल लोगों से समस्याओं और मांगों के आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके बाद एक माह में आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री साय शिविर लगाकर 10 से 15 गांवों के लोगों की एक साथ समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ऐसे में फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना कम दिख रही है। पार्टी सूत्रों की मानें तो साय को अभी शीर्ष नेतृत्व से ही हरी झंडी नहीं मिली है। इस कारण से मामला लटक गया है।

दिल के अरमां आंसुओं में बह गए

राजनीति में ऊंचा पद और ऊंची कुर्सी पाने के लिए नेता शतरंज के खेल से भी बड़ी-बड़ी चालें चलते हैं। लेकिन नौकरशाह भी ऐसे मामलों में किसी से कम नहीं होते हैं। इस बात को सिद्ध कर दिया है 2015 बैच के एक प्रमोटी आईएएस अधिकारी ने। साहब का रिटायरमेंट नजदीक आ गया है, लेकिन उन्हें अभी तक कलेक्टरी का सुख नहीं मिला है। सूत्रों का कहना है कि कलेक्टरी का सुख पाने के लिए साहब ने अपनी धार्मिक सीमाएं लांघने में भी गुरेज नहीं किया। अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले उक्त आईएएस अधिकारी ने ब्राह्मणों पर जहां किताब लिखी है, वहीं उन्होंने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को लेकर तरह-तरह के कसीदे भी गढ़े हैं। अक्सर वे सोशल मीडिया पर सनातन को सबसे अच्छा मानते हैं और हिंदू धर्म की पैरवी करते थकते नहीं है। जानकारों का कहना है कि साहब यह सब एक सोची-समझी रणनीति के तहत कर रहे हैं। क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह हिंदुत्ववादी सरकार है। उनकी कोशिश रही है कि वे कुछ ऐसा करें, जिससे सरकार की गुड बुक में वे आ सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और कलेक्टर बनने का उनका सपना अधूरा रह गया। गौरतलब है कि वे सात नॉवेल लिख चुके हैं। इन पर भी खूब विवाद हुआ है। वे फिल्म कश्मीर फाइल्स पर अपनी टिप्पणी और हिजाब विवाद पर अपने विचार रखकर चर्चाओं में रह चुके हैं।

नियामक आयोग की कुर्सी खाली

जब भी कोई आईएएस अधिकारी रिटायर होता है तो उसकी कोशिश रहती है कि वह विद्युत नियामक आयोग या इस जैसे किसी अन्य संस्थान की बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए ताकि सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता रहे। लेकिन विद्युत नियामक आयोग की कुर्सी काफी समय से खाली है। इस कुर्सी को पाने के लिए कई पूर्व आईएएस अधिकारी हाथ-पांव मार रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं 1989 बैच के एक पूर्व आईएएस अधिकारी। साहब करीब दो माह पहले रिटायर हुए हैं। उनके कई वीडियो वायरल हुए, जिसको लेकर मामला ईओडब्ल्यू तक पहुंचा। यही नहीं उनकी शिकायत पीएमओ तक भी की गई। इस कारण साहब को

अभी तक विद्युत नियामक आयोग की बड़ी कुर्सी नहीं मिल पाई थी। लेकिन सूत्रों का कहना है कि साहब को कुर्सी तक पहुंचाने के लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में उन्हें विजिलेंस क्लीयरेंस मिल गया है। क्योंकि उनके खिलाफ कोई एफआईआर या चालान नहीं लगा था।

जलवे हों तो मैडम जैसे

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में एक महिला अधिकारी का जलवा सिर चढ़कर बोल रहा है। मैडम का जलवा ऐसा है कि उसे देखकर लोग अचरज में पड़ गए हैं कि आखिरकार मंत्रालय में सबसे बड़ा ओहदेदार कौन है। दरअसल, मैडम ने अपने चारों तरफ एक ऐसा कॉकस बुन रखा है जो शायद ही कभी मंत्रालय में देखने को मिला हो। सूत्र बताते हैं कि मैडम जबसे यहां सचिव की कुर्सी पर बैठी हैं, वे अपने आप को सबसे पावरफुल दिखाने की जुगत में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक महिला गार्ड को तैनात करवा लिया है, जो उन्हें नीचे से उनके कमरे तक और कमरे से नीचे तक स्कॉट करके लाती, ले जाती है। यही नहीं घड़ी की सुई में जैसे ही दो-सवा दो बजता है, मैडम मंत्रालय से रवानगी के लिए तैयार हो जाती हैं। इससे 20-25 मिनट पहले इसकी उद्घोषणा होती है और तत्काल सुरक्षाकर्मी नीचे तैनात हो जाते हैं। इसके साथ ही लिफ्ट को भी मैडम के लिए रोककर रखा जाता है। जब यह पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि सारी व्यवस्था चाक-चौबंद हो गई है, तब मैडम कमरे से निकलती हैं और गाड़ी में बैठकर बंगले के लिए रवाना होती हैं। मैडम के इस रुतबे को देखकर अब लोग कहने लगे हैं कि मैडम अकेले गाड़ी में घर जाती हैं, अच्छा होता कि वे आगे-पीछे फॉलो गाड़ी भी लगवा लेतीं। मैडम के इस जलवे को देखकर कुछ अफसर जल-भुन भी रहे हैं।

जुगाड़बाज एएसआई

घपले-घोटालों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले विभाग में एक एएसआई की प्रतिनियुक्ति चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बताया जाता है कि उक्त एएसआई अपनी जुगाड़ तकनीक के लिए जाना जाता है। उक्त एएसआई एसएफ में है, लेकिन उसके बावजूद उसने प्रदेश के सबसे कमाऊ विभाग में अपनी पदस्थापना करा ली है। बताया जाता है कि उक्त एएसआई विभागीय मंत्री का चहेता है। सूत्रों का कहना है कि इस कारण मंत्री के पीए और उक्त एएसआई में विगत दिनों झड़प हो गई। यह झड़प भी कहीं ओर नहीं बल्कि मंत्रीजी के बंगले पर ही हुई है। दरअसल, एएसआई और पीए में इस बात की ठनी है कि मंत्री का सबसे विश्वसनीय और करीबी मैं हूं। यहां बता दें कि मंत्री की एकाधिकारिता का क्षेत्र ग्वालियर-चंबल अंचल है। इस क्षेत्र के लिए मंत्रीजी कुछ भी कर सकते हैं। यहां बता दें कि हाल ही में यह विभाग अपने एक पूर्व कॉन्स्टेबल की अकूत काली कमाई के कारण चर्चा में हैं। यही नहीं मंत्रीजी के पीए पर भी विभाग में अवैध गतिविधियां संचालित करने के आरोप लग रहे हैं और उनको मंत्री का भरपूर संरक्षण है।

मंत्री पर भारी चेला

आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी- गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी बन गया। कुछ ऐसी ही स्थिति किसानों से संबंधित एक विभाग की है। विभाग के मंत्री के इर्द-गिर्द ऐसे अफसरों ने कुंडली मार ली है, जो मंत्री के नाम पर जमकर लक्ष्मी बटोर रहे हैं। इन्हीं में से एक किसानों से खरीदी-बिक्री वाले बोर्ड से संबंधित है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये तो मंत्री पर भी भारी पड़ रहे हैं। दरअसल, मंत्रीजी को जबसे विभाग की जिम्मेदारी मिली है, उनके परिजनों के साथ ही उनके करीबी बिना मेहनत किए हुए कमाने की जुगत में जुट गए हैं। इसी कड़ी में उक्त अधिकारी सबसे आगे निकल गए हैं। बताया जाता है कि विभाग के अफसरों और विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों से वे मंत्री के नाम पर जमकर वसूली कर रहे हैं। आलम यह है कि मंत्री के नाम पर 10 प्रतिशत की वसूली करते हैं और उन्हें देते हैं मात्र 3 प्रतिशत। इस तरह उक्त अधिकारी जमकर काली कमाई कर रहे हैं। उनकी कमाई के तरीके को देखकर लोग कहने लगे हैं कि मंत्री का चेला मंत्री से बड़ा हो गया।

सख्त प्रावधान... फिर भी अवैध निर्माण

कानून में संशोधन क्यों कर रही मौजूदा सरकार

मप्र सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का कानून तो बना दिया है लेकिन इसका प्रभावी पालन नहीं हो सका है। पूर्व की शिवराज सरकार ने साल 2016 से पहले बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया था। उस समय नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने पूरे प्रदेश में सर्वे कर ऐसी 6077 अवैध कॉलोनियां चिह्नित की थीं। मोहन सरकार ने पिछले साल जब अवैध कॉलोनियों का डेटा जिलों से मंगाया तो पाया गया कि अवैध कॉलोनियों की संख्या 6077 से बढ़कर 7981 हो चुकी है यानी 1908 नई अवैध कॉलोनियां बन चुकी हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा के पिछले सत्र में कहा था कि प्रदेश में बन रही अवैध कॉलोनियों को सरकार वैध नहीं करेगी। इनमें रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें, बिल्डिंग परमिशन मिल जाए, यह काम जरूर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियां एक गंभीर मुद्दा बन गई हैं। इसके लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा। बता दें कि मप्र नगरपालिका अधिनियम 2021 की धारा 292 और 339 की उप धाराओं में अवैध कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

मप्र में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को लेकर सरकार ने सख्त नियमों और सजा का प्रावधान किया है। उसके बावजूद अवैध कॉलोनियों में अधोसंरचना विकास और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ये सख्त प्रावधान किसलिए किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, डॉ. मोहन यादव सरकार नगरपालिका एक्ट में बदलाव करने जा रही है। संशोधित कानून में अवैध कॉलोनी बनाने पर 10 साल की सजा और 50 लाख जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के मौजूदा कानून में सजा और जुर्माने के प्रावधान में बदलाव के साथ ये भी तय किया जा रहा है कि 2016 से पहले बनी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है।

नगरपालिका एक्ट के अनुसार, अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड के कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें एक है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, धारा 339ग। इसके तहत कॉलोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति, जो कॉलोनी स्थापित करने के उद्देश्य से, अपनी भूमि को या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को, इस अधिनियम या इस निमित्त बनाए गए नियमों में अनुध्यात् अपेक्षाओं को भंग करके भू-खंडों में विभाजित करता है, वह अवैध कॉलोनी निर्माण का अपराध करता है। जो कोई अवैध व्यपवर्तन का या अवैध कॉलोनी निर्माण का कोई अपराध करेगा या उसके किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक सात वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और ऐसे किसी अपराध के संबंध में निर्णय पारित करने में न्यायालय, अभियुक्त को, परिषद को प्रतिकर की ऐसी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकेगा जैसी कि वह ऐसी अवैध कॉलोनी के विकास के लिए उपगत होने वाली अपेक्षित राशि पर विचार कर लेने के पश्चात् निर्णय में विनिर्दिष्ट करे, और ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध होगा। जो कोई अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में कोई भवन सन्निर्मित करता है, वह अवैध संनिर्माण का अपराध करता है।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, धारा 339-घ के तहत भूमि के अवैध व्यपवर्तन या अवैध कॉलोनी निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड- जो कोई अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में भवन के सन्निर्माण के लिए अभिन्यास (ले-आउट) मंजूर करने या नक्शा मंजूर करने की शक्ति रखने वाला अधिकारी होते हुए, ऐसा अभिन्यास या नक्शा मंजूर या अनुमोदित करेगा वह दंडनीय है। वहीं विद्युत या जलप्रदाय संयोजन (कनेक्शन) मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी होते हुए, ऐसे किसी भवन के संबंध में ऐसे संयोजन की मंजूरी देगा, या ऐसा अधिकारी होते हुए, जिसका प्राथमिक कर्त्तव्य ऐसा करना हो, ऐसे किसी क्षेत्र में भूमि के अवैध व्यपवर्तन की रिपोर्ट करने का जानबूझकर लोप करेगा, या ऐसा अधिकारी या ऐसा कर्मचारी होते हुए भी जो भूमि के अवैध व्यपवर्तन के विरुद्ध कार्रवाई करेगा वह नियम विरुद्ध है।

धारा 339-घक के अनुसार अवैध कॉलोनी निर्माण या भूमि के अवैध व्यपवर्तन के कृत्य में सहयुक्त व्यक्तियों के उत्तरदायित्व- समस्त निदेशक, संप्रवर्तक तथा वित्तपोषक (फाइनेंसर), जो अवैध कॉलोनी निर्माण या भूमि के अवैध व्यपवर्तन के कृत्य में ऐसे व्यक्ति के साथ सहयुक्त हैं, जो ऐसे अवैध कॉलोनी निर्माण या अवैध व्यपवर्तन का अपराध करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है, ऐसे अपराध को कारित करने के लिए समान रूप से दायित्वाधीन होंगे तथा धारा 339-ग के उपबंधों के अधीन दंडित किए जाएंगे। धारा 339-ङ के अनुसार अवैध कॉलोनी निर्माण की भूमि का प्रबंध सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्रहण किया जाना, जैसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार, नगरपालिका क्षेत्र में भूखंडों या भवनों के समस्त अंतरणों या अंतरण के करार के ब्यौरे, प्रत्येक माह की समाप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी को, ऐसी रीति में संसूचित करेगा, जैसी कि निहित की जाए। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया ऐसा सक्षम प्राधिकारी अवैध कॉलोनी निर्माण की भूमिका प्रबंध ग्रहण करने के प्रयोजन के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में तीन बार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाएगा। ऐसी सूचना के प्रकाशन के पश्चात् यदि किसी कॉलोनी निर्माण करने वाले व्यक्ति या भूखंड धारक से कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया जाएगा और यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो सक्षम प्राधिकारी ऐसी भूमि का प्रबंध ग्रहण करेगा और उस क्षेत्र की योजना बनवाएगा तथा उसे ऐसी रीति में विकसित करवाएगा, जैसी कि विहित की जाए तथा भूखंडों को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाए, आवंटित करेगा। यह नियम विरुद्ध है और ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य को अवैध माना जाएगा।

● **धर्मेंद्र कथूरिया**

इंदौर-भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी का खाका तैयार

इंदौर और भोपाल के महानगर बनने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने मप्र मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार करने की नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग को मंजूरी दे दी है। एक हफ्ते के भीतर ये ड्राफ्ट तैयार कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को भेजा जाएगा। समिति की मंजूरी के बाद एक्ट के मसौदे को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मेट्रोपॉलिटन एरिया के गठन के प्रस्ताव पर समीक्षा बैठक हुई। नगरीय आवास एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला ने प्रेजेंटेशन में बताया कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया के प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी गई है। दोनों शहरों के विकास का जिम्मा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का होगा।

इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में पांच जिले इंदौर, देवास, उज्जैन, धार और शाजापुर को शामिल किया गया है। कुल क्षेत्रफल करीब 9 हजार वर्ग किमी का होगा। इस एरिया की आबादी 55 लाख के करीब होगी। इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया को डेवलप करने का काम तेजी से हो रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) को नोडल एजेंसी बनाया है। आईडीए ने डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्त कर ली है। मेट्रोपॉलिटन एरिया को 4 चरणों में डेवलप किया जाना है, जिसमें इंसेप्शन, सिचुएशन एनालिसिस, रीजनल एवं इन्वेस्टमेंट प्लान और डीपीआर शामिल है। इसके पहले चरण यानी इंसेप्शन का काम पूरा हो चुका है यानी ये तय हो गया है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? इनमें कौन-कौन से जिले शामिल होंगे, तहसील और गांवों की संख्या कितनी होगी? अब सिचुएशन एनालिसिस का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, यानी इसमें शामिल जिलों की अलग-अलग तहसील, निकायों का डेटा, वहां की जनसंख्या, स्थापित उद्योग, क्षेत्र की विशेषता की स्टडी होगी। इसके बाद वहां की भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक-सामाजिक स्थिति का आंकलन होगा। कहां कौनसी इंडस्ट्री है, किस तरह की जरूरतें हैं, इसका भी खाका तैयार होगा। इसके बाद रीजनल एवं इन्वेस्टमेंट प्लान बनेगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया का समान रूप से विकास हो सके। इसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी की जाएगी। समीक्षा बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया कि दोनों महानगरों का नाम क्या होगा? इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए तीन नामों का विकल्प रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में तीसरे विकल्प यानी अवंतिका महानगरीय क्षेत्र पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। हालांकि, अंतिम फैसला मेट्रोपॉलिटन एक्ट बनने के बाद लिया जाएगा। इंदौर मेट्रोपॉलिटन के तेजी से हो रहे काम की वजह है सिंहस्थ 2028। दरअसल, इंदौर का जो एरिया तय हुआ है उसमें दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जोड़ा गया है। सरकार की कोशिश है कि इससे उद्योगों और व्यापार को नई गति मिले। इससे देवास, पीथमपुर, उज्जैन और बदनावर जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इंदौर, देवास और अन्य शहरों को मजबूत सड़क, रेल और हवाई मार्गों से जोड़ा जाएगा, जिससे सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।

भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ जिले के ब्यावरा को शामिल किया गया है। भोपाल विकास प्राधिकरण को मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलप करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। हालांकि अभी तय नहीं है कि इन जिलों का कितना क्षेत्रफल भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया में शामिल होगा। साल 2022 में शिवराज सरकार ने भोपाल में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंडीदीप तक विस्तार करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी थी। उस वक्त भोपाल मेट्रोपॉलिटन का प्रारंभिक एरिया डिफाइन किया था, जिसमें भोपाल की 59 ग्राम पंचायतें और मंडीदीप निवेश क्षेत्र (रायसेन) की 9 ग्राम पंचायतें शामिल की गई थी। समीक्षा बैठक में बताया गया कि कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी किया गया है, जो जून में ओपन होगा। इंदौर की तरह भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए भी तीन नाम सुझाए गए हैं...भोपाल महानगरीय क्षेत्र, मप्र राज्य राजधानी क्षेत्र और भोजपाल महानगरीय क्षेत्र। बैठक में मौजूद सूत्र बताते हैं कि भोजपाल महानगरीय क्षेत्र के नाम पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है। दोनों शहरों को मेट्रोपॉलिटन रीजन में डेवलप करने के लिए सरकार को नया कानून बनाना पड़ेगा। बैठक में मप्र मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग को निर्देश दिए गए हैं।

● सुनील सिंह

मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने से फायदे

योजना में शामिल होने से नए उद्योगों और निवेशकों को आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। नई टाउनशिप, सड़कें, पुल, लॉजिस्टिक पार्क और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्वच्छता, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। नए उद्योगों और व्यापारिक विस्तार से स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मा और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। योजना में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए हरे क्षेत्रों और जल स्रोतों को संरक्षित करने पर ध्यान दिया गया है। झीलों, तालाबों और छोटी नदियों के संरक्षण की योजना बनाई जा रही है। योजना के तहत भोपाल-इंदौर में शहरी क्षेत्र से लगे इलाकों में नई आवासीय योजनाएं और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स विकसित किए जाएंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल आएगा और निवेशकों के लिए नए अवसर बनेंगे। दोनों क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है। योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी। कृषि उत्पादों को बड़े बाजारों में बेचने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा।

म प्र में तीन साल बाद तबादलों पर से प्रतिबंध हटा है। मप्र की डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में 1 मई से 30 मई तक तबादले करने को हरी झंडी मिल गई है। जीएडी के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने जो तबादला नीति मंजूर की है, उसमें कुल तबादलों में स्वैच्छिक तबादलों को भी जोड़ा जाएगा। विभाग खुद भी तबादला नीति बना सकेंगे और इसके लिए जीएडी से अनुमति लेंगे। 30 मई तक ई-आफिस में सारे ट्रांसफर लागू होंगे। इसके बाद तबादले नहीं हो सकेंगे। इसलिए मंत्रियों से कहा गया है कि वे 30 मई के पहले सभी तबादला आदेश जारी कर दें। इसके लिए तबादला प्रस्तावों में भी बदलाव किया गया है।

तबादला नीति में तय किया गया है कि यदि कोई विभाग अपनी ट्रांसफर नीति बनाना चाहे तो बना सकता है। इसके लिए विभाग को अपनी ट्रांसफर नीति बनाकर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजना होगी। हालांकि इसमें तबादले का अनुपात नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि यदि स्वैच्छिक आधार पर तबादले ज्यादा हुए तो प्रशासनिक आधार पर तबादले की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

मंत्रियों को अधिकार

राज्य सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों में मंत्री और प्रभारी मंत्रियों की ही चलेगी। जिले के अंदर तबादले के लिए प्रभारी मंत्री अपनी अनुशंसा देंगे और इसके बाद ही ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में तबादले के लिए पहले प्रभारी मंत्री द्वारा अनुशंसा की जाएगी। इसके बाद मंत्री तबादले करेंगे। मंत्री प्रशासनिक आधार पर सीधी तबादले कर सकेंगे। ट्रांसफर प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर हो सकेंगे। सीनियर अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री समन्वय की अनुमति से किए जा सकेंगे। उधर एक ही जिले में तीन साल या उससे अधिक समय से जमे अधिकारी-कर्मचारियों को दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा। जिले के अंदर तबादले की सूची कलेक्टर, जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जारी की जाएगी। इसके अलावा जिन अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के मामले हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा।

महीनेभर होंगे तबादले

यह है ट्रांसफर का फॉर्मूला

कैबिनेट ने तबादला नीति में जो प्रस्ताव तय किए हैं उसके अनुसार मंत्री और प्रभारी मंत्री तबादले कर सकेंगे। इसके लिए विभागों में पदवार तबादलों का प्रतिशत भी तय किया गया है। 200 पदों में 20 प्रतिशत ही ट्रांसफर होंगे। 201 से लेकर 1000 तक 15 प्रतिशत ट्रांसफर होंगे। 1001 से लेकर 2000 तक 10 प्रतिशत ट्रांसफर होंगे। वहीं 2001 से अधिक पर 5 प्रतिशत तबादले होंगे। स्वैच्छिक आवेदन को भी स्वीकार किया जाएगा। विभाग भी ट्रांसफर पॉलिसी बना सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग को जानकारी देनी होगी। मंत्री ने कहा कि सरकार ने तबादलों की प्रतिशत सीमा में स्वैच्छिक तबादलों को इसलिए जोड़ा है ताकि कुल पदों के हिसाब से तबादले का प्रतिशत बना रहे। अगर स्वैच्छिक तबादलों को अलग रखा जाएगा तो कुल पदों की संख्या के प्रतिशत से यह अधिक हो जाएगा। इसलिए कैबिनेट ने तय किया है कि स्वैच्छिक तबादलों को भी पदों के आधार पर तय तबादला संख्या और प्रतिशत में जोड़ा जाएगा।

अभी मैं यहीं रहूंगी

प्रदेश की साढ़े 8 करोड़ आबादी के स्वास्थ्य की चिंता करने वाले विभाग में इन दिनों जंग छिड़ी हुई है। दरअसल, एनएचएम में 2014 बैच की एक महिला आईएएस अधिकारी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। मैडम जबसे विभाग में आई हैं, उन्होंने वहां के अफसरों और कर्मचारियों पर इस कदर नकेल कस रखी है कि हर कोई उनकी विदाई की कामना कर रहा है। दरअसल, एक तो मैडम अपने वरिष्ठ अफसरों के निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं, वहीं विभाग में पदस्थ एक महिला अधिकारी से उनकी तनिक भी नहीं पट रही है। उक्त महिला अधिकारी एक अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की पत्नी हैं। ऐसे में विगत दिनों जब पहले मुख्य सचिव और उसके बाद मुख्यमंत्री ने विभाग की समीक्षा की तो कयास लगाए जाने लगे कि मैडम का ट्रांसफर होना तय है, लेकिन अगले ही दिन जब मैडम ने विभागीय अफसरों के साथ बैठक की तो उन्होंने पूरे दम और आत्मविश्वास से कहा कि मैं कहीं जाने वाली नहीं। अभी मैं यहीं रहूंगी।

बाल भी बांका नहीं हुआ

प्रदेश में नर्सिंग घोटाले के बाद कई कॉलेजों के संचालक, प्राचार्य और नर्सिंग काउंसिल के कई अधिकारी जांच की भेंट चढ़ गए। लेकिन एक रजिस्ट्रार ऐसे भी हैं, जिनका बाल भी बांका नहीं हुआ। जबकि साहब की नर्सिंग में पदस्थापना नियमों को ताक पर रखकर की गई थी। दरअसल, साहब एक पीएस की श्रीमती के काफी खास हैं। बताया जाता है कि रजिस्ट्रार साहब को नर्सिंग में प्रतिनियुक्ति पर लाने के लिए पहले एक पोस्ट निकाली गई ताकि अस्पताल से उन्हें नर्सिंग में लाया जाए। साहब नियमों को ताक पर रखकर नर्सिंग में पदस्थ रहे, वहीं नर्सिंग घोटाले में जब कईयों पर गाज गिरी तब भी साहब पाक साफ निकल गए। जबकि इनकी शिकायत पीएमओ तक गई थी। सूत्रों का दावा है कि प्रमुख सचिव की मैडम के खास होने के कारण उक्त रजिस्ट्रार का बाल बांका नहीं हुआ। यहां बता दें कि पहले इनकी नियुक्ति जबलपुर में हुई थी फिर ये एमवाय अस्पताल इंदौर में पदस्थ रहे। प्रमुख सचिव भी इंदौर में पदस्थ रह चुके हैं। यहीं से दोनों के संबंध प्रगाढ़ हुए थे।

इनको आईपीएस अवॉर्ड

राज्य पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा अवॉर्ड हुआ है। राज्य पुलिस सेवा के 1995 और 1997 बैच के अधिकारियों को आईपीएस का 2016 बैच आवंटित हुआ है। जिन अधिकारियों को आईपीएस अवॉर्ड हुआ है, उनमें प्रकाश चंद्र परिहार, दिलीप कुमार सोनी, अवधेश प्रताप सिंह और राजेंद्र कुमार वर्मा के नाम शामिल हैं।

कहां अटक गई तबादलों की सूची

मप्र में मंत्रालय, पीएचक्यू से लेकर मैदानी स्तर तक आईएएस-आईपीएस अफसरों के तबादले होने हैं। खासकर पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस मुख्यालय ने तबादले का मसौदा तैयार कर गृह विभाग को भेज दिया है। जैसे ही सूची को हरी झंडी मिलेगी, पुलिस विभाग में एसपी, डीएसपी और सीएसपी से लेकर अन्य पुलिस अधिकारियों के तबादले होंगे। लेकिन तबादलों की सूची कहां अटक गई है, इसको लेकर हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी बदला जाना है। जिलों में एसपी बदलने की अटकले एक जनवरी से लगातार चल रही हैं, लेकिन किसे कहां पर पोस्ट करना है, इसे लेकर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसके चलते जनवरी से लेकर अब तक पुलिस अधीक्षकों के तबादले नहीं हो पा रहे है। पुलिस अधीक्षकों के साथ ही कुछ रेंज के आईजी और डीआईजी भी बदले जाने हैं। हालात यह हो गए हैं कि डीआईजी बनने के बाद भी तीन अफसर तीन महीने से पुलिस अधीक्षक का ही काम देख रहे हैं। जबकि आईजी हो चुके दो अफसर अब भी डीआईजी का कामकाज संभाल रहे हैं।

राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के 65 के लगभग अफसरों के तबादले होने हैं। इस संबंध में एक महीने से प्रस्ताव गृह विभाग में लंबित है। इधर लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के भी कुछ पुलिस अधीक्षकों को बदला जा सकता है। दोनों ही लिस्ट फिलहाल गृह विभाग के पास अटकी हुई हैं। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को भी बदला जा सकता है। वहीं जिलों में पुलिस अधीक्षकों को बदलने की कवायद चल रही है। इधर, इस सूची के अटकने से कई अफसर अपनी मनचाही जगह पर जाने के प्रयास में लग गए हैं, जबकि कुछ तबादला न हो इस प्रयास में लग गए हैं। दोनों ही तरह के प्रयासों में लगे अफसरों की दौड़, मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर पुलिस मुख्यालय तक लगी हुई है।

पारिवारिक झगड़ा, बदनाम पुलिस

एक आईपीएस दंपति का आपसी झगड़ा पिछले कई महीनों से सुर्खियों में बना हुआ है। आलम यह है कि महिला आईपीएस अधिकारी अपने पति पर दूसरी औरत के साथ रहने का आरोप लगाते हुए पुलिस महानिदेशक से कई बार शिकायत कर चुकी हैं। उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी ने डीआईजी रेंज जबलपुर को मामले की जांच करने की जिम्मेदारी दी थी। जांच रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि मामला पारिवारिक था और इससे बदनाम पुलिस हो रही थी। जांच अधिकारी ने जो रिपोर्ट डीजीपी को सौंपी है, उसके अनुसार आईपीएस दंपति में विवाद बढ़ने के बाद दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी लगाई थी। इस बीच महिला आईपीएस अधिकारी ने अर्जी चुपके से वापस ले ली। लेकिन जब पुरुष को पता लगा तो उन्होंने फिर से आवेदन दे दिया। उधर, पुरुष आईपीएस अधिकारी ने जांच अधिकारी को बताया कि जबसे उक्त महिला से मेरी शादी हुई है, वह मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी और मेरे माता-पिता को भी प्रताड़ित किया जा रहा था। इससे हमारा घर का माहौल खराब हो गया था, जिसके बाद दोनों ने तलाक लेने का निर्णय किया। अब वह मुझ पर चारित्रिक आरोप लगाने लगी है। हालांकि डीआईजी जबलपुर ने दोनों पक्षों से बातचीत के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर पुलिस मुख्यालय को सौंप दी है। यहां बता दें कि पुरुष आईपीएस अधिकारी बालाघाट में एसपी हैं, वहीं महिला आईपीएस अधिकारी डिंडोरी में।

ईओडब्ल्यू की सक्रियता

प्रदेश सरकार का थाना कहे जाने वाले ईओडब्ल्यू की सक्रियता चर्चा में है। यह संस्थान आए दिन कोई न कोई बड़ी कार्रवाई करता रहता है। अभी हाल ही में एक मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी अभिलेख तैयार कर धोखाधड़ी कर भूमि विक्रय करने वाले भूमाफिया के विरूद्ध ईओडब्ल्यू रीवा में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है। उक्त 30 एकड़ जमीन रीवा शहर के नए बस स्टैंड के पास है। अब तक 5 एकड़ जमीन बेची जा चुकी है, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है। वहीं आधार रियल्टी फर्म द्वारा नगर निगम के पक्ष में बंधक रखी गई जमीन का नियमों के विरुद्ध विक्रय किया गया है। ईओडब्ल्यू भोपाल द्वारा जांच में खुलासा होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल द्वारा की जांच में यह सामने आया है कि आधार रियल्टी फर्म के संचालकों ने नगर निगम कोलार, भोपाल के पक्ष में बंधक रखे गए फ्लैट्स को बिना अनुमति के बेच दिया। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

● **राजेन्द्र आगाल**

पहल अच्छी, लेकिन हमसे तो पूछ लेते

अभी हाल ही में पुलिस मुख्यालय से एक निर्देश जारी किया गया कि सांसदों, विधायकों को अब पुलिस वाले सैल्यूट मारेंगे। इस आदेश के बाद प्रदेश की राजनीतिक वीथिका में विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया है। जिस तरह इस आदेश को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उससे सरकार के मुखिया भी आहत हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार के मुखिया ने पुलिस मुखिया को इस पहल के लिए धन्यवाद तो दिया है, साथ ही यह भी कह दिया है कि कम से कम हमें तो सूचित कर देते। वहीं सूत्रों का कहना है कि इस आदेश के खिलाफ कई अफसरों ने भी आवाज उठाई थी, लेकिन उसके बाद भी उसे अमली जामा पहना दिया गया। हालांकि पुलिस मुख्यालय के इस कदम पूर्व डीजीपी एससी त्रिपाठी भी सही ठहरा रहे हैं। इसका कहना है कि पैर छूने और हाथ जोड़ने से तो सैल्यूट मारना कहीं बेहतर है। इससे पुलिस का मान-सम्मान भी बचा रहेगा और जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी हो जाएगा।

अधर में लटक सकते हैं सहकारिता चुनाव

हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मप्र में तकरीबन 12 साल बाद सहकारी समितियों के चुनाव कराने की घोषणा हुई है। सरकार ने चुनावी कार्यक्रम भी तय कर दिए हैं। लेकिन अभी तक चुनावी तैयारी शून्य है। अभी तक सदस्यता भी पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर सहकारी समितियों के चुनाव अधर में लटक सकते हैं। हालांकि अपर मुख्य सचिव सहकारिता अशोक वर्णवाल का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सहकारी समितियों का चुनाव कराने के लिए हम बाध्य हैं। हमारी तैयारी चल रही है, जैसे ही तैयारी पूरी हो जाएगी, उसी तारीख पर चुनाव करा लिया जाएगा।

प्रदेश में अभी तक की जो स्थिति नजर आ रही है उससे लग रहा है कि 4,553 सहकारी समितियों का चुनाव अभी नहीं हो पाएगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने 24 मार्च की पांच चरणों में चुनाव कराने का कार्यक्रम जारी किया है। यह चुनाव एक मई से 4 सितंबर तक होना है, पर तैयारी के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मेंबरशिप पूरी नहीं करा पाए। दूसरी तरफ, मप्र सरकार केंद्र सरकार के सहकार योजना के पुनर्गठन स्कीम की बांट जोह रही है। हाईकोर्ट में भी वही दलील देने की तैयारी है कि पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी होने से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है। ऐसे में 2025 में चुनाव करा पाना बेहद मुश्किल है।

प्रदेश की सहकारी समितियों में पिछले 12 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। जबकि एक्ट में साफ लिखा है कि चुनी हुई समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष ही होगा। किंतु सरकार ने 2017 में चुनाव के बजाय प्रशासक की नियुक्ति कर दी। इसमें भी धांधली की शिकायतें हुई थी, किंतु मामला दब गया। 2018 में विधानसभा चुनाव होने से चुनाव टल गए। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने भी चुनाव कराने की जहमत नहीं उठाई। सवा साल बाद वह सरकार भी गिर गई और कोरोना व अन्य कारणों से चुनाव टलता रहा। यह मामला अभी हाईकोर्ट में उठा तो कोर्ट ने सरकार से चुनाव कराने तथा कार्यक्रम जारी करने का सख्त निर्देश दिया। सरकार ने भी उसी अंदाज में चुनाव कार्यक्रम जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस बीच भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों से कहा कि उनके यहां चूंकि संख्या के अनुपात में खेसायटियों की संख्या कम है, ऐसे में इसका पुनर्गठन कराएं। मप्र सरकार को इस स्कीम का बहाना मिल गया। इस पुनर्गठन के लिए तीन महीने का समय तय किया गया है। इस पुनर्गठन के बाद प्रदेश में समितियों की संख्या बढ़कर करीब 12 हजार हो जाएगी। दरअसल, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सेसायटी बनना है, अभी कई-कई पचायतों को मिलाकर सोसायटी है। दिलचस्प यह है कि इस पुनर्गठन स्कीम की वजह से 2025 में चुनाव हो पाना मुश्किल है।

गौरतलब है कि प्रदेश की सहकारी समितियों में चुनाव नहीं होने की वजह से सहकारिता का पूरा सिस्टम ठप पड़ गया है। समितियों में किसानों से जुड़ी गतिविधियों के नाम पर महज बानापूर्ति हो रही है। बताते हैं कि प्रशासक उन सोसाटियों में जमकर मनमानी करते हैं, पर पंचायत का कोई प्रतिनिधि नहीं होने से ये कुछ नहीं कर पाते। सहकारिता विभाग में ही हजारों की संख्या में शिकायतें लंबित है। राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से कार्रवाई तो दूर उन शिकायतों की जांच नहीं हो पाती। सरकार की जिम्मेदारी का अहसास इससे किया जा सकता है कि पहले साल 2012 में समितियों के चुनाव हुए ये तब से लेकर आज तक नहीं हुए। समितियों में इस वक्त मेंबरशिप भी नहीं है। सबसे पहले नियमों के अनुसार समितियों में मेंबर बनते हैं। इसके लिए एक मापदंड तय है कि अमुक किसान को ही सदस्य बनाया जा सकता है। यदि अभी मेंबरशिप की प्रक्रिया शुरू होती है तो कम से कम 60 दिन का समय लगना तय है। चूंकि पहले समितियां मेंबरशिप की सूची देती हैं। फिर उसका प्रकाशन होता है। इसके बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति होती है। मेंबरशिप का प्रकाशन स्थानीय स्तर पर होता है। इसके बाद यदि सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो अपीलीय अधिकारी नियुक्त कर उसका निराकरण कराया जाता है। अपीलीय अधिकारी की ओर से फाइनल सूची का प्रकाशन होता है। इसके बाद ही चुनाव आदि कराया जा सकता है।

● जितेंद्र तिवारी

सहकारी आंदोलन में शामिल व्यक्ति भी बन सकेगा सदस्य

राज्य सहकारी अधिकरण में नियुक्ति के लिए भी अधिनियम की धारा में संशोधन किया जा रहा है। इसमें प्रावधान किया जा रहा है कि अभिकरण में संयुक्त रजिस्ट्रार स्तर से रिटायर अफसर इसमें सदस्य बनाया जा सकेगा। इसके अलावा वह व्यक्ति भी सदस्य बन सकेगा, जो सहकारिता आंदोलन से जुड़ा रहा हो। हालांकि, 65 साल तक की उम्र का बंधन किया गया है। प्रदेश में सहकारी समितियों से जुड़े निर्णयों के खिलाफ सुनवाई राज्य सहकारी अधिकरण करता है। इसमें अध्यक्ष, सदस्य और रजिस्ट्रार पदस्थ रहते हैं, जो सहायक, उप, संयुक्त और पंजीयक द्वारा समितियों के संबंध में दिए गए निर्णयों की अपील सुनते हैं। वर्तमान में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश चन्द्रेश कुमार खरे अभिकरण में अध्यक्ष हैं। अब कोई भी सहकारी समिति अपने व्यवसाय या क्षेत्र विशेष में सहकारी निजी-सार्वजनिक भागीदारी (प्राइवेट पार्टनरशिप) कर सकेगी। इसके लिए अधिनियम में नई धारा जोड़ी जा रही है। इसमें प्रावधान किया गया है कि प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए समिति को प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसमें पूंजी लगाने और लाभांश की हिस्सेदारी का फॉर्मूला भी तय करना होगा। सहकारिता विभाग के सूत्रों का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सहकारी क्षेत्र में 2,305 करोड़ रुपए के 15 से अधिक एमओयू साइन हुए हैं। सहकारी क्षेत्र में निजी भागीदारी से कंपनियों को कच्चा माल आसानी से मिलेगा। कंपनियां सहकारी समितियों के माध्यम से अंतिम उत्पाद भी बेच सकती हैं।

फ्लैगशिप योजनाओं की सोशल ऑडिट

मप्र में समाज कल्याण के लिए संचालित की जा रही फ्लैगशिप योजनाओं का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। समाज कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए यह सोशल ऑडिट किया जाएगा। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि किस फ्लैगशिप योजना से जनता को अधिक लाभ मिला है उसका आंकलन कर उसे बूस्ट किया जाए। ऐसी योजनाओं को सरकार और मजबूती से आगे बढ़ाएगी साथ ही इसके लिए अतिरिक्त फंड भी मुहैया कराया जाएगा।

गौरतलब है कि विकास कार्यों की जांच जब किसी सरकारी एजेंसी से ना करवाकर उस विकास कार्य के लाभार्थी से ही करवाई जाए तो इसे सोशल ऑडिट कहा जाता है। दरअसल, ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं होती हैं। ये शंकाएं काम की गुणवत्ता, कार्यप्रणाली और विकास कार्यों के मानकों से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा सरकारी विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज्यादा शंका लोगों के मन में होती है। अक्सर लोगों को इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है। या यूं कहें कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती कि इस बारे में कहां से जानकारी जुटाई जाए, या कहां शिकायत की जाए। मगर अब सोशल ऑडिट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों की जांच खुद ग्रामीण कर सकते हैं। सोशल ऑडिट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गांव के लाभार्थी से ही गांव की विकास योजनाओं की रिपोर्ट ली जाती है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में लाडली बहना जैसी कई फ्लैगशिप योजनाओं का सोशल ऑडिट करवाया जाएगा। इन योजनाओं से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, इनकी कमियों से लेकर खूबियों तक की रिपोर्ट बनाई जाएगी। यह रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाएगी। इसके आधार पर योजनाओं में सुधार या परिवर्तन जैसे निर्णय लिए जा सकेंगे। इसके लिए शासन स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। स्वीकृति मिलने पर विभागों से समन्वय कर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें, मप्र में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले शुरू हुई लाडली बहना योजना के तहत वर्तमान में एक करोड़ 17 लाख पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना पर हर महीने करीब 1550 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस पर 18,669 करोड़ रुपए बजट का प्रविधान भी किया गया है। यह योजना इतनी लुभावनी साबित हुई कि महाराष्ट्र में भी इसे लागू किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं के लिए भी इसी तरह का वादा किया।

विभागवार तैयार होगा खाका

सोशल ऑडिट के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का विभागवार खाका तैयार किया जाएगा। इनमें प्रधानमंत्री मातृवंदना, पीएम आवास, निशुल्क खाद्यान्न वितरण, पथ विक्रेता योजना, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित तमाम ऐसी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क किया जाएगा। कैग (सीएजी) की तरह ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी, अंतर केवल यह होगा कि वित्तीय ऑडिट की जगह यह एक सोशल ऑडिट होगा। बता दें, सोशल ऑडिट का उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी होता है। फ्लैगशिप योजनाओं के लाभार्थियों के डाटा के आधार पर घर-घर संपर्क किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री के जनसेवा मित्रों की सेवाएं लेने पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश में 9390 जनसेवा मित्र हैं। इनकी सेवाएं पिछले वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं।

प्रदेश में फ्लैगशिप योजनाओं की वर्तमान स्थिति के अनुसार वर्ष 2024-25 में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत 2 लाख 43 हजार 396 बालिकाओं का पंजीयन किया गया है। वहीं लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अब तक 12,932 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 52 लाख माताएं पंजीकृत हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 लाख 75 हजार हितग्राहियों को 264 करोड़ रुपए भुगतान किया गया। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आहार अनुदान योजना में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। 2 लाख 20 हजार से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को निशुल्क खाद्यान्न वितरण करने की योजना में अब तक 32,47,304 टन खाद्यान्न वितरण किया गया है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में प्रतिमाह 55 लाख 60 हजार से अधिक हितग्राहियों को पेंशन दी जा रही है। इस वर्ष 4,066 करोड़ रुपए का बजट प्रविधान किया गया है।

मप्र सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाती है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के मौके पर इस लेख में हम मप्र सरकार की इन्हीं योजनाओं का जिक्र करेंगे, जिनका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उनकी सुरक्षा को पुख्ता करना है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत मप्र की लगभग 1.27 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है। लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने, लिंगानुपात में सुधार और उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत पात्र परिवारों को बेटी के जन्म से लेकर शिक्षा तक विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता दी जाती है। मप्र सरकार ने महिलाओं के लिए राज्य सरकार की सभी सेवाओं (वन विभाग को छोड़कर) में 35 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है। यह कदम महिलाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है। आहार अनुदान योजना योजना गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण सहायता प्रदान करती है, ताकि मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके।

● नवीन रघुवंशी

आईएएस अफसरों का नवाचार

मप्र आज देश में विकास का आईना बना हुआ है। यहां की जनता अपनी सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर खुशहाल हो रही है। इसके पीछे आईएएस अफसरों के नवाचार का बड़ा योगदान है।

प्रदेश के आईएएस अफसरों ने कई ऐसी योजनाओं को मूर्तरूप दिया है, जो देश ही नहीं विदेशों में भी छायी हुई हैं। प्रदेश के आईएएस अफसरों के नवाचार से आज मप्र का देश-दुनिया में मान बढ़ा है।

मप्र के आईएएस अफसरों ने केवल प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसे देश-दुनिया में सराहना मिली। इनमें लाड़ली लक्ष्मी योजना का जिक्र खास है। इस योजना को बाद में 15 राज्यों ने अलग-अलग तरह से कॉपी किया और 12 से अधिक पीएचडी इस पर हुईं। आज इसमें 50 लाख बेटियां पंजीकृत हैं। इन्हें समय-समय पर पैसा मिलता है, जिससे पढ़ाई चलती रहे। 21 साल की होने पर एक लाख रुपए मिलता है। इस स्कीम ने भाजपा को 2008 में दोबारा सत्ता में ला दिया, साथ ही लिंगानुपात सुधारने में भी अहम भूमिका निभाई। इसी तरह पीएम गतिशक्ति ने परियोजनाओं को नई रफ्तार दी है। प्लानिंग और प्रोसेस के लिए शानदार टूल पीएम गतिशक्ति को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आकार दिया था। प्रोजेक्ट लेट होने की बड़ी वजह विभागों में तालमेल की कमी है। सड़क, रेल, मेट्रो, बिजली- हर काम में समन्वय जरूरी है। इसी जरूरत को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पीएम गतिशक्ति पोर्टल को प्लानिंग का टूल बनाया गया। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान अनुराग जैन ने इसमें अहम योगदान दिया। जीआईएस बेस्ड पोर्टल से विभागों और सरकारों को जरूरी डाटा एकसाथ मिलने लगा। इस नवाचार के लिए पीएम एक्सीलेंस अवॉर्ड मिला।

मप्र के अधिकारियों की जनहितकारी पहलों जनसेवा, नवाचार और दूरदर्शिता से प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर में राज्य की सकारात्मक पहचान बनी। महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, कृषि सुधार और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनके नवाचारों ने स्थायी बदलाव की नींव रखी। इन पहलों को जहां राज्य के भीतर सराहा गया, वहीं देश के अन्य राज्यों ने भी इन्हें अपनाकर अपने यहां लागू किया। इन अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में प्रमुख सचिव पी. नरहरि ने 2006 में महिला एवं बाल विकास विभाग में रहते हुए लाड़ली लक्ष्मी योजना की रूपरेखा तैयार की थी। यह योजना आज न केवल मप्र में सफल है, बल्कि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली सहित कई राज्यों ने इसे अपनाया है। वर्तमान में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग में आयुक्त, प्रीति मैथिल को रीवा कलेक्टर रहते लिंगानुपात सुधारने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कृषि संचालक के रूप में उन्होंने फसल बीमा योजना में रिमोट सेंसिंग तकनीक लागू की, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुकी है। मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए कार्यों के लिए उन्हें आईसीएमआर द्वारा सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री के निज सचिव प्रवीण अढायच को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। जल जीवन मिशन के तहत बुरहानपुर को हर घर नल सुविधा वाला पहला जिला बनाने पर उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से सम्मान मिला। वर्तमान में मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में कार्यरत प्रियंका दास ने भोपाल में नगर निगम आयुक्त रहते हुए भानपुर खंती को वैज्ञानिक ढंग से बंद करवाया और पुनर्विकास कराया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्तमान में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में आयुक्त कर्मवीर शर्मा को डिंडोरी और रीवा में बेहतर प्रशासनिक काम के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। बड़वानी कलेक्टर रहते हुए राहुल हरिदास फटिंग ने समग्र विकास के काम किए। दुर्गम स्थानों तक केंद्र की स्कीमें पहुंचाई। वारलू कमांडो, मिशन नीव जैसे नवाचार किए। वे अभी हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर हैं।

● अरविंद नारद

मोटी आई मॉडल की गूंज दिल्ली तक

आदिवासी जिले झाबुआ में कुपोषण से निपटने के लिए कलेक्टर नेहा मीणा द्वारा किए गए प्रयासों को काफी सराहा जा रहा है। इस काम के लिए उन्हें नई दिल्ली में पीएम एक्सीलेंस अवॉर्ड मिला। नेहा ने इस अभियान के जरिए बच्चों को कुपोषण से बचाया। वैक्सीनेशन, गर्भवतियों की जांचें, लड़कियों की शिक्षा और कुपोषण हटाने के प्रयासों के अलावा उनका मोटी आई मॉडल सरकार को भी पसंद आया है और उसे अब दूसरे जिलों में भी अपनाया जाएगा। मोटी आई का मतलब होता है, बड़ी मां। आदिवासी परिवार अपने रीति-रिवाजों, गांव के बड़े बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए नेहा ने इस अभियान को देसी अंदाज में ढाला। भीली बोली में लोक गीत बनाए, गांवों-फलियों तक अभियान की खूबियां बताईं और पोषण आहर को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने गांव में अनुभवी महिलाओं की मदद ली। उन्हें प्रशिक्षित किया। हर गांव में तैयार हुई मोटी आई बच्चों को कुपोषण से दूर रखने में पूरी मदद करती है और मोटी आई कुपोषित बच्चों की मॉलिश भी करती है। झाबुआ जिले में तैयार हुई 1325 मोटी आई ने एक हजार से ज्यादा बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला। कुपोषण से निकलकर बच्चे सामान्य श्रेणी में आ चुके हैं। दरअसल जिले में कई परिवार यह समझ ही नहीं पाते थे कि उनका बच्चा कुपोषित हो चुका है। कुपोषित बच्चों का डेटा भी कलेक्टर नेहा मीणा ने एकत्र किया और यह पाया कि रोजगार की तलाश में जो परिवार बाहर जाते हैं, उनके बच्चे ज्यादा कुपोषित हैं। वे अपने बच्चे को दादा-दादियों के पास छोड़कर जाते हैं। वे उनका ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हैं, इस कारण बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। सबसे पहले पलायन करने वाले परिवारों को जिले में चिन्हित किया गया और उनके बच्चों की देखभाल का जिम्मा मोटी आई को दिया गया और बच्चों का कुपोषण दूर कर उन्हें सामान्य श्रेणी में लाया गया। कलेक्टर नेहा मीणा कहती है कि बच्चों को स्वस्थ देखकर सुकून मिलता है। अब गांव में इसे लेकर जागृति आ चुकी है।

काम आधा भी नहीं...खर्च पूरा

स्मार्ट सिटी मिशन का समापन 31 मार्च को हो गया। यानी स्मार्ट सिटी का बोरिया-बिस्तर पूरी तरह बंद हो गया। भारत सरकार के शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाए गए स्मार्ट सिटी मिशन का समापन 31 मार्च 2025 को हो गया। यह मिशन, जो जून 2015 में शुरू हुआ था, अब 100 शहरों को कवर करने के लिए निर्धारित था, लेकिन 10 सालों में तीन बार डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद केवल 16 शहरों में ही मिशन के तहत सभी प्रोजेक्ट्स पूरे हो पाए हैं। बाकी 84 शहरों में कई प्रोजेक्ट अधूरे रह गए हैं। इस मिशन में 14 हजार करोड़ से अधिक का निवेश किया गया था, लेकिन बड़े हिस्से में काम समय पर पूरा नहीं हो सका। इस प्रोजेक्ट में मप्र की राजधानी भोपाल समेत सात शहरों, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सागर, और उज्जैन शामिल हैं। सरकार का दावा है कि जिन 16 शहरों में स्मार्ट सिटी का काम 100 प्रतिशत पूरा हुआ है उनमें मप्र का जबलपुर शामिल है।

स्मार्ट सिटी मिशन में महाराष्ट्र सबसे प्रभावित राज्य रहा, जहां 1898 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अधूरे रह गए। इसके बाद बिहार में 1138 करोड़ और उप्र में 772 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो सके। बंगाल के कोलकाता शहर में 618 करोड़ रुपए के छह प्रोजेक्ट अधूरे रहे। इसके अतिरिक्त धर्मशाला में 200 करोड़, सतना में 259 करोड़, पटना में 383 करोड़, मुजफ्फरपुर में 340 करोड़ और बिहारशरीफ में 306 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी अधूरे रहे। स्मार्ट सिटी मिशन के समापन के साथ ही यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि अब स्टाफ का भविष्य क्या होगा। गौरतलब है कि मप्र के सातों शहरों में कार्यालय का निर्माण भी कराया गया है। इन कार्यालयों में कई बड़े अधिकारियों के साथ ही निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी भी बड़ी संख्या में नियुक्त हैं और सवाल यह उठ रहा है कि स्मार्ट सिटी में जो लोग काम कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी का जब काम बंद हो जाएगा तो अभी जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा।

स्मार्ट सिटी मिशन का मकसद था कि शहरों में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सुविधाएं विकसित करना। पिछले 10 सालों में भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी ने इस मकसद के लिए मिले करीब 1400 करोड़ रुपए में से 1351.88 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, लेकिन कुछ भी स्मार्ट नहीं हुआ। यहां तक कि 342 एकड़ के टीटी नगर एबीडी (एरिया बेस्ड डेवलपमेंट) में बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी खड़ी नहीं हो पाई हैं। स्मार्ट सिटी कंपनी को केंद्र और राज्य सरकार से 500-500 करोड़ रुपए मिले थे। इसके साथ कंपनी ने एबीडी एरिया में प्लॉट बेचकर 400 करोड़ कमाए। इन 1400 करोड़ रुपयों में से बड़ा हिस्सा यानी 663.27 करोड़ रुपए जिम्मेदारों ने ऐसे कामों पर खर्च कर दिया जो स्मार्ट सिटी के थे ही नहीं। इनमें भी सबसे ज्यादा 471 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए, जबकि स्मार्ट सिटी के मूल प्रोजेक्ट में इसका प्रावधान ही नहीं था। इसके अलावा नगर निगम और बीडीए के हिस्से के प्रोजेक्ट्स पर भी 192.27 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। जिस तरह पैसा खर्च हुआ, उससे साफ है कि बिना किसी विजन के सिर्फ बजट ठिकाने लगाने का काम किया गया। दरअसल, स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए सरकार ने 342 एकड़ जमीन कंपनी को दी। लेकिन इसमें से लगभग 150 एकड़ जमीन स्कूल, अस्पताल, स्टेडियम और कई धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं को आवंटित है। हकीकत में स्मार्ट सिटी कंपनी को 200 एकड़ जमीन ही मिली। जिस इलाके को खाली कराया गया, वहां तेजी से अतिक्रमण हो रहा है। जगह-जगह गुमठियां बन गईं हैं। टूटे-फूटे सरकारी मकानों पर कब्जे हो रहे हैं।

शिवाजी नगर में स्मार्ट सिटी के विरोध के बाद जब टीटी नगर में स्मार्ट सिटी डेवलप करने की प्लानिंग हुई तो वहां भी विरोध और आंदोलन शुरू हो गया। सरकार ने घोषणा कर दी कि स्मार्ट सिटी एरिया में सरकारी मकान बनाकर दिए जाएंगे। वहां 3100 एफ, जी, एच और आई टाइप सरकारी मकान खाली कराए गए थे। उस वादे को पूरा करने के लिए तीन चरणों में 2828 मकान बनाने का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया। फेज-1 में होटल पलाश के सामने 730 फ्लैट के 6 टॉवर 200 करोड़ से बनाने का काम शुरू हुआ। अब तक 220 करोड़ खर्च और छठवां टॉवर निर्माणाधीन है। अब तक सिर्फ 364 फ्लैट आवंटित किए जा सके हैं। फेज-2 में नूतन सुभाष स्कूल के पास 314.14 करोड़ से 12 हाईराइज टॉवर में 1344 सरकारी मकान बनाने का फैसला लिया गया। इस पर 80 करोड़ खर्च हो गए और प्रोजेक्ट बीच में बंद कर दिया गया। वास्तव में पेमेंट की दिक्कत होने के कारण कांट्रेक्टर ने बीच में काम बंद कर दिया। फेज-3 में 228 क्वार्टर के समीप 754 मकान बनाए जाने थे। लेकिन यह जमीन स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के नाम से लीज पर है। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता इस समिति के संचालक हैं। यहां काम शुरू नहीं हुआ है। वहीं बीडीए ने लक्ष्मीगंज गल्लामंडी के स्थान पर महालक्ष्मी परिसर बनाया। बुकिंग कम हुई तो कांट्रेक्टर को भुगतान के लिए बजट नहीं था। ऐसे में 2017-18 में स्मार्ट सिटी कंपनी ने 566 में से 551 फ्लैट खरीदे। 190 करोड़ में से 171 करोड़ का भुगतान किया।

● **लोकेश शर्मा**

काट दिए 3 हजार पेड़

प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट में 3 हजार पेड़ काट दिए। अगर सुप्रीम कोर्ट से इन पेड़ों की कीमत लगाई जाए तो कुल 2160 करोड़ रुपए के पेड़ काट दिए गए हैं। इसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की योजना तो गजब की थी। लेकिन उसकी प्लानिंग ने सब बिगाड़ दिया। सरकारी अधिकारियों ने विदेशी शहरों को देखा और बिना सोचे-समझे उस योजना को यहां लागू कर दिया। जबकि, हर शहर की जरूरत अलग होती है। अधिकारियों ने जनता से राय-मशवरा ही नहीं किया। उसके बाद इसमें नगर निगम के प्रोजेक्ट जुड़ गए। उसने और गड़बड़ कर दी।

हाईटेक होगा सिंहस्थ 2028

महाकाल की नगरी में 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियों में शासन और प्रशासन पूरी तरह जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंहस्थ को हर बार की अपेक्षा इस बार अद्भुत और अलौकिक बनाने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री की मंशानुसार आस्था और भक्ति का समागम सिंहस्थ पूरी तरह हाईटेक होगा। सिंहस्थ 2028 मप्र के विकास का आईना बनेगा। गौरतलब है कि इसी साल प्रयागराज में आयोजित कुंभ का मप्र के अधिकारियों ने पूरी तरह अध्ययन किया है और उसके आधार पर सिंहस्थ की रूपरेखा दी जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि सिंहस्थ केवल एक आयोजन नहीं, यह आस्था, परंपरा और संस्कृति का महाकुंभ है। 2028 में उज्जैन में होने जा रहे सिंहस्थ को लेकर मप्र की डॉ. मोहन यादव सरकार 3 साल पहले ही जोरशोर से तैयारी कर रही है। खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस महापर्व को लेकर इंटरेस्ट ले रहे हैं। अपने गृह क्षेत्र में होने जा रहे सिंहस्थ 2028 के लिए डॉ. मोहन यादव नया मॉडल लाने की तैयारी में हैं, जिससे अगला सिंहस्थ और भी बेमिसाल होगा। हाल ही में प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ लगा था। इस दौरान यहां आस्था की भारी भीड़ देखने को मिली थी। वहीं, अब से ठीक 35 महीने बाद बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होना है।

भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उज्जैन में लगने वाला सिंहस्थ कुंभ 2 महीने तक चलेगा। सिंहस्थ मेला का भव्य आयोजन 27 मार्च, 2028 से शुरू होकर 27 मई, 2028 तक चलेगा। इस दौरान, क्षिप्रा नदी के तट पर तीन अमृत स्नान की महत्वपूर्ण तिथियां होंगी, जो 9 अप्रैल से 8 मई के बीच पड़ेंगी। इसके अतिरिक्त, सात अन्य स्नान पर्व भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि सिंहस्थ महाकुंभ अद्भुत सामाजिक समागम है, इससे समाज की दिशा तय होती है। पहले लोग कुंभ के मेले में तय हुई दिशा को लेकर जाते थे और समाज में बदलाव के लिए काम करते थे। समय के साथ परंपराओं में बदलाव आया है, किंतु हमें अपनी जड़ों और मूल्यों के महत्व को समझना होगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में वर्ष 2028 में आयोजित सिंहस्थ की तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मानना है कि कुंभ केवल एक मेला ही नहीं, अपितु विश्व को परंपराओं के नवोन्मेष की शिक्षा व संदेश देने वाले शानदार प्रबंधन का एक अद्भुत उदाहरण है। दुनिया को इसे केस स्टडी के तौर पर अपनाना चाहिए।

गौरतलब है कि पिछली बार उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन केवल एक महीने के लिए ही हुआ था। वहीं, इस बार इसे दो महीने का किए जाने से श्रद्धालुओं को अधिक समय मिलेगा। हर 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में दुनियाभर से साधु-संत और श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। यह आयोजन धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। इस बार प्रदेश सरकार ने इस दिव्य मेले में लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान लगाया है। हालांकि, इस विशाल आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं- भीड़ का कुशल प्रबंधन और स्वच्छता बनाए रखना। सिंहस्थ में अब लगभग 35 महीने का समय शेष है, लेकिन चिंता की बात यह है कि सड़क, पुल, बिजली जैसी मूलभूत विकास परियोजनाएं अभी भी कागजी कार्रवाई

वैश्विक धार्मिक पर्यटन स्थल बनेगा उज्जैन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार सिंहस्थ महाकुंभ-2028 की तैयारियों में जुटी है, जिसमें विकास और अधोसंरचना के काम शुरू किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संकल्प लिया है कि सिंहस्थ-2028 में श्रद्धालुओं को क्षिप्रा नदी के निर्मल जल में ही स्नान कराया जाए और क्षिप्रा नदी में स्वच्छ एवं शुद्ध जल का प्रवाह सदा के लिए सुनिश्चित कर उसे सही अर्थों में पुण्य-सलिला और सदानीरा बनाया जाए, साथ ही पारिस्थितिकी संतुलन भी बना रहे। संकल्प की पूर्ति के लिए उज्जैन में सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी, कान्ह क्लोज डक्ट एवं हरियाखेड़ी परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं और 18 बैराज एवं स्टॉप डैम बनाए जा रहे हैं। इससे क्षिप्रा नदी में पूरे वर्ष निर्मल जल प्रवहमान रहेगा, साथ ही उज्जैन को शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंहस्थ कुंभ के सफल आयोजन से उज्जैन को एक प्रमुख वैश्विक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भी स्थापित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंहस्थ आयोजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागीय कार्यों को समय-सीमा में पूरा किए जाने पर जोर दिया है।

तक ही सीमित हैं। इतने कम समय में इन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए मोहन सरकार ने कमर कस ली है, जिसमें 15 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इस भव्य आयोजन के लिए 11 विभागों ने 15,751 करोड़ रुपए की 102 परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से 5133 करोड़ रुपए के 75 कार्यों को इस वर्ष पूरा करने की सिफारिश की गई है। सिंहस्थ के लिए उज्जैन शहर की सड़कों को चौड़ा करना, पुलों का विस्तार और क्षिप्रा नदी के घाटों की लंबाई बढ़ाना भीड़ नियंत्रण के लिए आवश्यक है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्रस्तावित रोप-वे और रेलवे ओवरब्रिज जैसी कई योजनाएं अभी भी स्वीकृति के बाद भी शुरू नहीं हो पाई हैं। 35 महीने का समय शेष होने के कारण, सरकार को इन मूलभूत सुविधाओं को तेजी से विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि लाखों श्रद्धालुओं को सुगम और स्वच्छ अनुभव मिल सके।

सिंहस्थ मेला क्षेत्र में नगर विकास योजना की कार्ययोजना तैयार कर कार्य की शुरुआत इस साल जून से युद्ध स्तर पर की जाएगी। मेला क्षेत्र में 200 एमएलडी पेयजल क्षमता का विकास किया जाएगा। सीवर नेटवर्क डिजाइन के अंतर्गत सिंहस्थ के दौरान मेला क्षेत्र में 160 एमएलडी का सीवरेज जनरेशन होगा, जिसमें 100 एमएलडी क्षमता के स्थाई एसटीपी निर्माण किए जाएंगे और अस्थाई रूप से 60 एमएलडी क्षमता के सीवरेज का निष्पादन किया जाएगा। इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने सिंहस्थ मेला क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों की तैयारियों की समीक्षा कर अफसरों को जरूरी निर्देश दिए हैं। सिंहस्थ के दौरान लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए उज्जैन में भवन विकास निगम द्वारा मेडिसिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लागत कुल 592.3 करोड़ रुपए है। इस अस्पताल की क्षमता 550 बिस्तर की होगी। इसके साथ ही मेला क्षेत्र के आसपास 500 अस्थायी अस्पताल बनाए जाएंगे और कैंप लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को सिंहस्थ मेला क्षेत्र के अनुसार 6 जोन में बांटा जाएगा। मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। मेले के दौरान बर्न यूनिट, एंबुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक, ट्रॉमा सेंटर आदि की संपूर्ण तैयारी रखने पर फोकस किया जा रहा है।

उज्जैन सिंहस्थ को सरकार डिजिटल बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए आईटीएमएस जंक्शन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। सिंहस्थ के समय आईटीएमएस पुलिस विभाग को सौंपा जाएगा। सिंहस्थ में फेस रिकग्निशन, अलर्ट सिस्टम, फायर अलार्म के सभी सॉफ्टवेयर एमपीएसईडीसी द्वारा विकसित किए जाएंगे। ऑल इन वन ऐप भी बनाया जाएगा, जिसमें ड्रोन सर्विस, यातायात एवं वाहन प्रबंधन, मानव संसाधन और कार्य प्रगति की जानकारी की सुविधा मिल सकेगी। सिंहस्थ मेला क्षेत्र का वर्चुअल टूर एप के माध्यम से कराया जाएगा। वहीं, सड़क एवं अन्य सफाईकर्मियों को मिलाकर 11 हजार 220 सफाईकर्मियों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा कचरा संग्रहण के लिए लगभग 5 हजार सफाई कर्मियों की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर 16 हजार 220 सफाईकर्मियों की आवश्यकता होगी।

गत दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के रामघाट पर जल गंगा संवर्धन अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने रामघाट पर सफाई की। साथ ही क्षिप्रा में डुबकी भी लगाई। मुख्यमंत्री ने रामघाट पर सफाईकर्मियों और पंचकोशी यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि आने वाले कुंभ में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के अलग-अलग भागों में लोग नौकायन कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। इसके लिए जलमार्ग बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धनाथ से त्रिवेणी तक 29 किमी के नए घाट तैयार होंगे। पहले से 6 किमी के घाट बने हुए हैं। इस तरह से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को 35 किमी के घाट उपलब्ध होंगे। कुंभ में हर घाट रामघाट होगा। श्रद्धालु कहीं भी स्नान करेंगे उन्हें उतना ही पुण्य मिलेगा। इस बार कुंभ में जलमार्ग बनाने जा रहे हैं। शनि मंदिर से रामघाट, गऊघाट से लालपुर, मंगलनाथ से रामघाट तक नौकायन से लोग आना-जाना कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, क्षिप्रा नदी के किनारे पंचकोशी परिक्रमा की एक पुरानी परंपरा रही है। हर साल हजारों-लाखों लोग यहां आकर परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा की शुरुआत में श्रद्धालु जब यहां स्नान करेंगे, तो घाट पर स्वच्छता और जल की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

● श्याम सिंह सिकरवार

स्टार्टअप्स का होगा सम्मेलन

उज्जैन में वर्ष-2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ में लगभग 15 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। तैयारियों के संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज और हरिद्वार में कुंभ की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सिंहस्थ आयोजन में भीड़ और यातायात प्रबंधन के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए उप्र के प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्थाओं में संलग्न कंपनियों और स्टार्टअप्स को बुलाकर उज्जैन में एक सम्मेलन कराया जाएगा। सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की संभावित भारी संख्या में आमद को ध्यान में रखते हुए संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की योजना है कि उज्जैन और इंदौर को सिंहस्थ-2028 के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां परिवहन, जल आपूर्ति, सीवेज सिस्टम और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंहस्थ के प्रत्येक पहलू के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की महत्ता पर जोर दिया है। इसमें धर्मशालाओं का उन्नयन और निर्माण कार्यों के दौरान उज्जैन, इंदौर और देवास जिलों में क्लीनलीनेस के साथ ही ग्रीनरी में सुधार शामिल है। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा निरंतर सिंहस्थ की तैयारियों की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। उनके अनुसार, उज्जैन सिंहस्थ मेला क्षेत्र के विकास के लिए भवन अनुज्ञा का कार्य आगामी 15 जून तक कर लिया जाएगा और 25 जून से कार्य प्रारंभ होगा। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में नगर विकास योजना की कार्ययोजना तैयार कर कार्य की शुरुआत जून 2025 से युद्ध स्तर पर की जाएगी।

भोपाल में अजमेर 92 जैसा कांड...

4 सालों से शहर में सक्रिय था गिरोह

पुलिस जांच में इस बात का खुलासा भी हो चुका है कि गिरोह चार सालों से शहर में सक्रिय था। वे हुक्का लाउंज, पब और कॉलेजों में लड़कियों को टारगेट कर फांसने का काम करते थे। फरहान के बाद गिरोह का दूसरा मुख्य किरदार साहिल खान था। साहिल ने पिछले डेढ़ साल के भीतर दो अलग-अलग ठिकानों पर डांस क्लास का संचालन किया है। ओल्ड सुभाष नगर में डिलाइट नाम से उसकी डांस क्लास थी। आलम खान के घर में आरोपी यह क्लास संचालित करता था। इसके लिए वह 10 हजार रुपए महीने का किराया देता था। आलम के मुताबिक साहिल ने चार महीने पहले अचानक कोचिंग का संचालन बंद कर दिया। इंदौर में रहने वाली दो सगी बहनों में से एक बड़ी बहन ने पुलिस को दिए बयानों में फरहान की बहन की भूमिका संदिग्ध बताई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि फरहान की बहन को भाई की करतूतों की जानकारी थी। वे हमेशा उसे समझाने के बजाय उसकी तरफदारी करती और मुझे बदनामी का डर बताकर धमकाती थी। फरहान ने एक बार बहन की मौजूदगी में घर के एक कमरे में उसके साथ ज्यादती भी की थी।

मप्र की राजधानी भोपाल में 1992 के कुख्यात अजमेर रेप कांड जैसा एक और संगीन मामला सामने आया है, जिसने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। रायसेन रोड स्थित एक प्राइवेट कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के एक गिरोह ने हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर दरिंदों ने पीड़िताओं की सहेलियों को भी अपना शिकार बनाया। पुलिस के मुताबिक, इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बागसेवनिया थाने में 16 अप्रैल को एक युवती ने हिम्मत दिखाकर शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि आरोपी फराज खान ने हिंदू नाम बताकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और संबंध बनाए। इस दौरान उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया, जिसके जरिए ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। बाद में उसे फराज की असल पहचान पता चली। फराज ने उसे दो अन्य युवकों से मिलवाया, जिन्होंने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इस शिकायत के बाद उसी कॉलेज की दो अन्य छात्राओं ने भी इसी तरह की घटनाओं की शिकायत दर्ज कराई। अब तक तीन युवतियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन कई अन्य ने बदनामी के डर से शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि कैसे उसे और उसकी बहन के साथ मारपीट से लेकर गांजा पीने और मांस खाने तक के लिए मजबूर किया गया। एक पीड़िता की ओर से दर्ज एफआईआर को देखा, तो पता चला कि आरोपी फरहान न सिर्फ इस पीड़िता के साथ, बल्कि इसकी सगी छोटी बहन के साथ भी हैवानियत कर रहा था। इसलिए जब सब्र का बांध टूट गया, तो पीड़िता ने मामले की एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में साफ लिखा है कि पहले तो फरहान ने बड़ी बहन से संबंध बनाए, बाद में उसकी छोटी बहन से भी दबाव बनाकर संबंध बनाए। इसमें उसके कई दोस्तों का भी हाथ रहा, जिन्होंने हर तरफ से दबाव बनाकर छोटी बहन को भी फरहान के साथ संबंध बनाने पर मजबूर किया। एफआईआर में पीड़िता ने लिखा है कि वह रायसेन रोड के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी। फर्स्ट ईयर में उसकी दोस्ती फरहान से हुई और धीरे-धीरे दोनों में बहुत बात होने लगी। अप्रैल 2022 में फरहान पीड़िता को जहांगीराबाद स्थित एक घर ले गया, जो उसके दोस्त हामिद का था। यहां उसने दुष्कर्म किया और इसी दौरान वीडियो बना लिया। इसके बाद फरहान ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू किया। उसने और उसके दोस्तों ने पीड़िता पर रोजा रखने का दबाव भी बनाया और जबरदस्ती नॉनवेज खिलाया। यही नहीं, आरोपी इसके बाद पीड़िता को बुर्के में रहने को भी कहने लगा और एक बार पीड़िता ने बुर्के में फोटो भी भेजी थी। पीड़िता ने बकायदा आरोपी और उसके दोस्तों के साथ हुए चैट्स भी पुलिस को सौंपे हैं। आरोपी पीड़िता को लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा, जिसके बाद पिछले साल सितंबर के महीने में पीड़िता आरोपी फरहान के साथ उसके दोस्त अबरार के घर गई, जहां फिर दुष्कर्म किया गया।

पीड़िता ने बताया है कि फरहान ने इसी तरह उसकी बहन के साथ भी दुष्कर्म किया। पीड़िता की बहन (जो खुद भी पीड़िता है और जिसने अलग से एफआईआर कराई है) की फरहान के जरिए उसके दोस्त अली से पहचान हुई, जिसने पिछले साल जून में उसके साथ संबंध बनाए और इसका वीडियो बना लिया। यही वीडियो उसने फरहान को भी भेजा, जिसके बाद फरहान ने भी वीडियो वायरल करने की धमकी दी और फरहान के दोस्तों ने भी उस पर फरहान के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया। पीड़िता की बहन को फिर बहाने से अबरार के घर बुलाया गया, जहां उसे जबरदस्ती नशा करवाया गया और फिर फरहान ने उसके साथ पहले मारपीट करने के बाद दुष्कर्म किया और इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया। इसके बाद दोनों बहनों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को एक युवक के जरिए मिली, जिससे पीड़िता ने एक दिन बात करते हुए अपनी आपबीती साझा की थी। युवक ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने पहले पीड़िता की कई दिनों तक काउंसलिंग की। जब पीड़िता को यकीन हो गया कि उसकी पहचान उजागर नहीं होगी, तब उसने एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने पहले गुपचुप तरीके से सभी आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की, उन पर नजर रखी और मौका मिलते ही उन्हें पकड़कर सबसे पहले उनके फोन जब्त किए, ताकि पकड़े जाने से पहले आरोपी वीडियो वायरल न कर दें।

भोपाल में कॉलेज की हिंदू छात्राओं को टारगेट कर रेप करने के मामले में एक और खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी फरहान ने अपने घर में भी एक छात्रा से रेप किया था। इसकी जानकारी उसकी बड़ी बहन को थी। जबकि अली ने जून 2024 में एक बार नाबालिग छात्रा से अपने घर में ज्यादती की थी। इस समय सुबह के चार बजे थे, अली का बड़ा भाई और मां भी घर में मौजूद थे, लेकिन दोनों सो रहे थे। जांच में यह बातें सामने आने के बाद अब पुलिस दोनों के परिवारों की भूमिका की जांच कर ही है। पुलिस ने अली को निजामुद्दीन कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के घर छुपा था। अली को मिलाकर अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

● बृजेश साहू

पराली की आग से बांझ हो रही माटी

मप्र के किसान देश की 18.18 फीसदी आबादी को गेहूं की रोटी खिलाने का इंतजाम करते हैं। गेहूं उत्पादन के मामले में मप्र देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इससे अलग मप्र के किसान देश में सबसे ज्यादा गेहूं की फसल की कटाई के बाद खेतों में आग भी लगा रहे हैं। देश में पराली जलाने के मामले में मप्र में इस साल रिकॉर्ड टूटा है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक जल्दी खेत खाली करने का यह तरीका किसानों के लिए आने वाले सालों में बेहद नुकसानदायक साबित होगा। हम स्वयं के या गेहूं के जलने का नुकसान जानते हैं, मगर पराली जलाने से लग रही चपत का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे। कटे खेतों में बची पराली फूंककर खेत खाली करने की जल्दी सिर्फ जन-धन हानि का कारण ही नहीं बन रही, बल्कि यह माटी को भी बंजर कर रही है। कृषि और पर्यावरण के जानकार मानते हैं कि अगर इसे लेकर हम चेते नहीं तो बाद में बस पछताना ही हाथ आएगा। हाल के वर्षों में खेतों में गेहूं के डंठल यानी पराली जलाने की प्रवृत्ति तेजी से पनपी है। लोग कटाई और दवाई की टेंशन से बचते हुए कंबाइन मशीनों से गेहूं कटवा लेते हैं। इससे खेतों में पराली खड़ी रह जाती है। आमतौर पर किसान खेतों में आग लगाकर इससे छुटकारा पा लेते हैं। थोड़े से आराम के लिए किसानों में बढ़ती यही प्रवृत्ति खेतों को बांझ कर रही है।

मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पराली के साथ राख में बदलते जा रहे हैं। उपजाऊ ह्यूमस नष्ट हो जा रहा है। जीवांश कार्बन खोकर खेत क्षारीय होकर बंजर होते जा रहे हैं। कुछ लोगों में भ्रम है कि खेतों में आग लगाना लाभकारी है जबकि हकीकत इससे उलट है। खेतों में आग लगाना कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता। इससे मिट्टी में मौजूद ह्यूमस नष्ट हो जाता है। ह्यूमस प्रमुख जीवांश का काम करके मिट्टी को उर्वर बनाता है। जमीन में अकार्बनिक तत्वों से मिलकर उसे उपजाऊ बनाता है। इससे उसकी जलधारण और वायुधारण क्षमता बढ़ती है। इतना ही नहीं। इससे कई मित्र कीट और जंतु नष्ट होकर खेतों की उत्पादकता पर बुरा असर डाल रहे हैं। साथ ही इससे उठते धुएं के गुबार से वायु प्रदूषण अलग से हो रहा है। प्रशासन और कृषि विभाग इसे लेकर लोगों को जागरूक करने की बात तो कहता है, लेकिन वास्तव में इसे लेकर अपेक्षित गंभीरता से प्रयास होता नहीं दिखता है।

कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि पराली जलाने से उपजाऊ माटी बंजर हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोईकोसिस्टम मॉनीटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस (सीआरईएएमएस) के डैशबोर्ड के अनुसार, मप्र में इस साल अब तक 14,118 गेहूं की पराली में आग की घटनाएं हुई हैं। प्रदेश के जिन जिलों में गेहूं की पराली में आग की अधिक घटनाएं दर्ज हो रही हैं, वहां जायद फसल के रूप में मूंग की खेती का चलन बढ़ा है। इनमें नर्मदापुरम, रायसेन, देवास, विदिशा, हरदा और सीहोर जिले प्रमुख हैं। आईआईएसएस भोपाल के कृषि वैज्ञानिक डॉ. आशा साहू के अनुसार पराली जलाने से खेत की उर्वरता घटती है। मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। क्योंकि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और पोटैशियम, वाष्पित हो जाते हैं। काली मिट्टी की पौष्टिकता कमजोर हो जाती है। साथ ही मिट्टी में पाए जाने वाले लाभदायक जीवाणु और मित्र कीट जैसे केंचुए नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें फैलती हैं। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और सांस संबंधी बीमारियां होती हैं।

मप्र में पराली जलाने के बढ़ते मामलों के बीच सरकार किसानों के लिए एक नई स्कीम लेकर आ रही है। इसके तहत जो किसान सरकार की पांच शर्तों को पूरा करेंगे उन्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इन पांच शर्तों में पराली जलाने से मुक्त खेती को अपनाने के साथ कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करने की भी शर्त शामिल है। एक एकड़ खेत वाले किसान को 1500 रुपए से लेकर 3 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। सरकार ने इस नई स्कीम को अन्नदाता मिशन (कृषक कल्याण मिशन) नाम दिया है। इसके जरिए किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें जलवायु अनुकूल खेती और फसलों के सही दाम दिलाना है। बता दें कि 15 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस मिशन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने मिशन के लिए 2028 तक का टारगेट भी तय किया है। इसमें 2.69 लाख वनाधिकार (एफआरए) पट्टाधारी किसानों को 100 फीसदी फायदा देना है। मप्र में लघु और सीमांत किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, मगर उन तक तकनीक और संसाधनों की सीमित पहुंच है। मानसून पर निर्भरता की वजह से ये किसान फसल का सही उत्पादन भी नहीं कर पाते। जिसकी वजह से उन्हें फसल के उचित दाम नहीं मिलते।

● विकास दुबे

तीन साल में पराली जलाने की 32 हजार से ज्यादा घटनाएं

कृषि विभाग के अधिकारी बताते हैं कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के बाद पराली जलाने की घटना मप्र में बढ़ती जा रही है। पिछले तीन साल के आंकड़े देखें तो रबी और खरीफ सीजन मिलाकर 32 हजार से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। इनमें भोपाल संभाग अव्वल है। दूसरे नंबर पर चंबल संभाग है। अधिकारी के मुताबिक किसान अगली फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए आसान रास्ता अपनाते हैं। नर्मदापुरम और हरदा के बेल्ट में गेहूं की फसल काटने के बाद मूंग की फसल लेने के लिए खेत में आग लगा दी जाती है। इससे खेत तो साफ हो जाता है, लेकिन उसकी मृदा शक्ति पर विपरीत असर पड़ता है। पराली जलाना किसानों की मजबूरी है। राजगढ़ जिले के किसान मुकेश नागर कहते हैं कि फसल कटाई के बाद जो अवशेष बचते हैं उसे हटाने के लिए बक्खर चलाना पड़ता है। मजदूर एक एकड़ का 4 से 5 हजार रुपए लेते हैं। अब किसी किसान का दो से तीन एकड़ का खेत है तो उसे कम से कम 10 से 15 हजार रुपए खेत की सफाई के लिए लिए देना पड़ते हैं। नागर कहते हैं कि इससे अच्छा तो जुर्माना देकर पराली जलाना है। पांच एकड़ खेत में पराली जलाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना है। किसान की अगली फसल की लागत भी नहीं बढ़ती है। यदि सरकार किसानों को पराली न जलाने पर कोई आर्थिक सहायता देगी तो किसान पराली नहीं जलाएगा।

कागजी योजनाएं...कैसे बुझेगी प्यास?

मप्र के 5 हजार से ज्यादा गांवों में जल संकट

मप्र के 5 हजार से ज्यादा गांवों में जल संकट है। सिंचाई, कृषि कार्य समेत पेयजल का भी संकट है। इसे लेकर आरएसएस के आनुषांगिक संगठन किसान संघ ने चिंता जाहिर की है। किसान संघ ने शासन-प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि जल संरक्षण, संवर्धन और सिंचाई से जुड़ी योजनाओं में कई खामियां रही। अब किसान संघ सर्वे कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। किसान संघ के प्रांत प्रचार-प्रसार प्रमुख राहुल धूत ने कहा कि प्रदेश के 5 हजार से अधिक गांवों में भीषण जल संकट है। कृषि का पूरा काम जल पर ही आधारित है, यह बड़ी समस्या और चिंता का विषय है। ग्रामीण संरचना या पूरे प्रदेश की संरचना सिंचाई पर निर्भर होती है। मवेशी से लेकर खेती और सभी को पानी चाहिए, स्थिति गंभीर होती जा रही है। भारतीय किसान संघ ने भी विषय को काफी गंभीरता से लिया है। हम अपने स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसान संघ से जुड़े किसानों, कार्यकर्ताओं और सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि रिपोर्ट तैयार करें। किसान संघ अपने स्तर पर भी सभी प्रकार की जन संरचनाओं की गंभीर स्थिति को लेकर कार्ययोजना तैयार कर रहा है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल भीषण गर्मी की भविष्यवाणी की है। उधर, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, मप्र सहित भारत के प्रमुख जलाशयों का जल स्तर उनकी कुल क्षमता के 45 फीसदी तक गिर गया है। इस बीच मप्र में अभी से जल संकट पैर पसारने लगा है। कुएं सूखने और जल जीवन मिशन की विफलता से लोग कुएं में उतरकर पानी निकालने को मजबूर हैं। दरअसल, मप्र में हर साल गर्मियां शुरू होते ही जल संकट शुरू हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई योजनाएं कागजों पर ही हैं, ऐसे में लोगों की प्यास कैसे बुझेगी? सीहोर में पेयजल संकट की आशंका के मद्देनजर, कृषि और औद्योगिक कार्यों के लिए जल उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही निजी नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

अप्रैल का महीना अभी शुरू ही हुआ है और मप्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट के हालात बनने लगे हैं। भूमिगत जलस्तर में गिरावट के चलते कई गांवों में जलसंकट की स्थिति के चलते ग्रामीणों को कुएं में उतरकर प्यास बुझाना पड़ रही है। जबकि पीएचई विभाग जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा कर रहा है लेकिन स्थिति यह है कि कई गांवों में योजनाओं का काम अधूरा है। जिसकी वजह से ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रदेश के बालाघाट जिले में पानी की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। खेतों में फसलें सूखने की कगार पर हैं और जल स्रोतों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी होती जा रही हैं। अब कलेक्टर ने इस बड़े संकट को देखते हुए जिले को सूखा ग्रस्त घोषित कर दिया है।

नदियों जलाशयों और वनों के मामले में अपेक्षाकृत समृद्ध मप्र और भोपाल अंचल में बैठकर हम भले ही खुद को जल के मामले में सुरक्षित महसूस करें लेकिन यहां भी जिस तेजी से जलस्रोतों का सिकुड़ना व भूजल स्तर का गिरना जारी है वह कम डरावना नहीं है। अंचल कई जिलों में भी जलसंकट की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। विशेषज्ञों ने वर्ष 2050 तक भारत के 55 शहरों में पानी के लिए शून्य दिवस आ जाने की कुछ दिन पूर्व आशंका व्यक्त की है। अभी से ही कुछ जिलों के कई जगहों पर हैंडपंप सूख चुके हैं और तालाबों में नाममात्र का पानी बचा है। इस बार गर्मी अधिक पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे जल संकट और गहरा सकता है। खेतों में खड़ी रबी सीजन की फसलों की सिंचाई शुरू होने से यह स्थिति बन रही है। नदी और तालाबों का पानी तेजी से कम हो रहा है। गांवों में महीनेभर में जलस्तर गिरकर 15 से 20 फीट तक नीचे चला गया है। ऐसे में हैंडपंप साथ छोड़ने लगे हैं। हैंडपंप व ट्यूबवेल सूखने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कुल 1,11,79,047 घरों में से 76,90,870 (68.80 प्रतिशत) घरों में जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंच गया है, लेकिन हजारों गांव ऐसे हैं जहां अभी पाइप लाइन ही बिछी हुई है। ताजा मामला बैतूल के भीमपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत डोक्या के ग्राम मेंढा का है, जहां ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए जान जोखिम में डालकर कुएं के नीचे उतरना पड़ रहा है। भीमपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत डोक्या के 700 आबादी वाले ग्राम मेंढा में जल जीवन मिशन के तहत घर-घर पेयजल पहुंचाने के लिए पाइप लाइन बिछाने के साथ नल कनेक्शन किए गए हैं। दो साल हो गए हैं, लेकिन ग्रामीणों के घर पानी नहीं पहुंचा। गांव में मौजूद हैंडपंप पहले ही दम तोड़ चुके हैं। भैंसदेही विकासखंड के ग्राम पंचायत केरपानी में जलस्तर गिरने से ट्यूबवेल बंद हो गया है। ग्रामीण खेत में मौजूद ट्यूबवेलों पर निर्भर हैं। सरपंच संतराम बारस्कर ने बताया कि ट्यूबवेल सूख जाने के कारण योजना पिछले दो महीने से बंद पड़ी है। प्रदेश में सैकड़ों गांवों में पीने के पानी के लिए कई किमी दूर पंचायती कुएं पर निर्भर होना पड़ रहा है। डीपी हैंडओवर नहीं होने से थ्री फेस मोटर नहीं डाली गई है। ग्रामीणों की मानें तो बिजली कनेक्शन नहीं हुआ है जिससे परेशानी आ रही है। वहीं ग्रामीणों ने ट्यूबवेल में घरेलू कनेक्शन से सिंगल फेस मोटर डाली है, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है। गांव के पंचायती कुएं में भी जल स्तर पाताल में चला गया है। आमला विकासखंड के ग्राम मालेगांव में भी पानी का संकट था, जहां भूमिगत जलस्तर गिरने से नलजल योजना बंद हो गई थी। महिलाओं ने खाली कुप्पी लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, जिसके बाद कलेक्टर ने ट्यूबवेल खनन के निर्देश दिए।

● **प्रवीण सक्सेना**

> स्वास्थ्य विभाग जिलेभर में करीब 2 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करने, टीबी जांच, एक्स-रे करने का दावा करता है। लेकिन टीबी वैक्सीनेशन कार्यक्रम के असफल होने के बाद आरोप लग रहा है कि ये अभियान सिर्फ कागजों में चलाए जा रहे हैं।

काल बन मप्र की तरफ बढ़ रहा टीबी!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मार्च 2018 को टीबी हारेगा देश जीतेगा का नारा दिया और देश से टीबी जैसी गंभीर बीमारी के खात्मे का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री ने इसके लिए 2025 तक की डेडलाइन रखी थी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए देशभर में टीबी (ट्यूबरक्लोसिस) उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 6 अलग-अलग श्रेणियों में चिन्हित वयस्क व्यक्ति को टीबी की वैक्सीन लगाई जा रही है। मप्र का सीहोर जिला इस अभियान से कोसों दूर नजर आ रहा है। इतने दिनों में हेल्थ डिपार्टमेंट ने जिले में सिर्फ 10 फीसदी ही वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि इस तरह कैसे टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूरा किया जा सकता है।

टीबी उन्मूलन अभियान के प्रदेश में फ्लॉप होने के कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो अभियान का उतना जोर-शोर से प्रचार नहीं किया गया, जितना अन्य कई सारी स्कीमों या अभियानों का किया जाता है। प्रशासनिक स्तर पर भी इस अभियान को समर्थन नहीं मिला। अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुद टीके नहीं लगवाए जो दूसरों के सामने उदाहरण पेश कर सकते थे। इसका एक बड़ा कारण और माना जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की प्रचारित खबरों ने लोगों के मन में इस वैक्सीन को लेकर भी आशंका पैदा कर दी। वहीं, कई लोगों का कहना है कि आंगनबाड़ी या फिर हेल्थ वर्कर ने टीके के संबंध में किसी को कोई जानकारी ही नहीं दी।

टीकाकरण अभियान के इतर जिले में 100 दिन में टीबी मुक्त सीहोर की कार्ययोजना तैयार की गई थी। जनवरी 2025 से यह अभियान शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग जिलेभर में करीब 2 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करने, टीबी जांच, एक्स-रे करने का दावा करता है। लेकिन टीबी वैक्सीनेशन कार्यक्रम के असफल होने के बाद आरोप लग रहा है कि ये अभियान सिर्फ कागजों में चलाए जा रहे हैं। इसको कह सकते हैं कि विभागीय कर्मचारियों की उदासीनता, प्रचार-प्रसार की कमी के चलते अभियान की सार्थकता नहीं दिखाई दे रही है। जिस वजह से टीबी जैसी जानलेवा बीमारी का जोखिम आज भी बना हुआ है।

बता दें कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों को बीसीजी टीके लगाए जाते हैं। इसमें 6 श्रेणी के लोगों को शामिल किया गया है। पहला चरण होता है पता लगाना, जिसके तहत बीमारी का सटीक रूप से पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग और परीक्षण किया जाता है। दूसरी श्रेणी है उपचार। इसके तहत मरीज को इलाज के लिए दवाएं उपलब्ध कराना। तीसरी श्रेणी रोकथाम होती है, जिसके तहत टीबी के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय किए जाते हैं, जैसे की टीबी मरीज के संपर्क में रहने वाले लोगों के लिए दवाइयां। चौथी श्रेणी होती है निर्माण। इसमें टीबी के बारे में जानकारी देना, टीबी से संबंधित कलंक को कम करना, और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है। 5वीं श्रेणी में टीबी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उचित रणनितियां बनाना और उसके लिए इलाज करने जैसे हर जरूरी उपाय करना शामिल है। छठवीं और आखिरी श्रेणी होती है समर्थन। इसमें टीबी रोगियों को बीमारी के दौरान उनकी देखभाल की जाती है। इसके अलावा उन्हें पोषण, वित्तीय और अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

347 जिलों में चलाया गया 100 दिवसीय अभियान

देश के 347 जिलों में 100 दिवसीय नि-क्षय अभियान चलाया गया। इसमें से मप्र के भी 23 जिले शामिल थे। 7 दिसंबर 2024 को नर्मदापुरम में इस अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि प्रदेश में नि-क्षय मित्र पहल के तहत हम टीबी मरीजों को पोषण सहायता प्रदान कर हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। इसमें हम टीबी के मरीजों को प्रतिमाह पूरक खाद्य बास्केट प्रदान करते हैं, जिससे उनके शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी ताकत मिल सके। बता दें कि भारत में 2015 से 2023 तक टीबी के मरीजों में 17.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह दर वैश्विक गिरावट 8.3 प्रतिशत से दोगुना से भी अधिक है। 2015 में टीबी से होने वाली मृत्यु दर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 28 थी, जो वर्ष 2023 में घटकर 22 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए वर्ष 2030 का लक्ष्य रखा है।

पिछले 1 साल में प्रदेश के 10 जिलों में टीबी के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसमें राजधानी भोपाल भी शामिल है। जहां 2023 के मुकाबले 2024 में करीब 2 हजार टीबी के मरीज बढ़े हैं। इसके अलावा इंदौर, आगर-मालवा, बड़वानी, भिंड, बुरहानपुर, दमोह, दतिया, देवास और धार जिले में 2023 के मुकाबले 2024 में टीबी के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं, पूरे प्रदेश की बात करें तो मरीजों की संख्या में कमी आई है। साल 2024 में मप्र में टीबी मरीजों की कुल संख्या 1 लाख 80 हजार 290 दर्ज की गई, जबकि 2023 में ये 1 लाख 82 हजार 290 थी। वहीं, 2022 में मप्र में टीबी के मरीजों की संख्या 1 लाख 85 हजार 904 दर्ज की गई थी। टीबी से होने वाली मौतों के मामले में मप्र देश में तीसरे स्थान पर है। पिछले साल के अक्टूबर महीने तक प्रदेश में टीबी से 5,152 मरीजों की मौत हुई थी।

● **कुमार विनोद**

4 लाख कर्मचारियों को डबल प्रमोशन

मप्र में 9 साल बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की है। अभी इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। इससे मप्र शासन के 4 लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिले 8 साल से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में वो डबल प्रमोशन के हकदार हैं। इस पर भी सरकार ने विचार किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से प्रमोशन के साथ आरक्षित वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों पर डिमोशन का खतरा भी मंडरा रहा है। अब देखना ये है कि सरकार इस मामले का किस प्रकार पटाक्षेप करती है।

जिन कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नति मिले 8 साल से अधिक का समय बीत चुका है, या फिर जिन्होंने साल 2014-15 के बाद ज्वाइन किया और उनकी समयावधि 8 साल पूरी हो चुकी है। ऐसे कर्मचारियों-अधिकारियों को डबल प्रमोशन का लाभ सरकार देगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कर्मचारियों को डबल प्रमोशन का लाभ तो मिलेगा, लेकिन एक साथ नहीं। बल्कि सरकार की मंशा है कि इस वर्ष एक प्रमोशन देने के बाद दूसरा प्रमोशन उनको अगले वर्ष दिया जाए। जिससे कर्मचारियों की कमी न हो। सपाक्स संगठन के प्रदेश अध्यक्ष केएस तोमर ने बताया कि साल 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सरकार ने एससी-एसटी वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का नियम बनाया था। इस नियम के तहत साल 2016 तक प्रदेश में आरक्षित वर्ग के कई अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन हुए। इससे आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को काफी फायदा हुआ, लेकिन ओबीसी समेत वो कर्मचारी-अधिकारी जो अनारक्षित वर्ग में थे, वो प्रमोशन में पीछे छूटते गए और उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसमें कोर्ट ने तथ्यों पर विचार करने के बाद इस पदोन्नति प्रक्रिया को रद्द कर दिया। लेकिन इस बीच आरक्षित वर्ग के जिन अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है, ऐसे लोगों को डिमोशन का खतरा भी बना हुआ है। केएस तोमर ने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण नियम 2002 लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश के 60 हजार से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिल चुका है, लेकिन जब इसे हाईकोर्ट 2016 में रद्द कर चुका है, तो ऐसे में इसकी वैधता कितनी है। तोमर ने बताया कि अभी मप्र में प्रमोशन का कोई नियम नहीं है, इसलिए ठीक है, लेकिन जैसे ही सरकार नए नियम बनाएगी, जो कर्मचारी गलत तरीके से प्रमोशन का लाभ ले रहे हैं, उनका डिमोशन करना होगा। हाईकोर्ट ने भी 31 मार्च 2024 के आदेश में कहा है कि 2002 के नियम के आधार पर जिन एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिला है। उन सभी का डिमोशन किया जाएगा। हालांकि सरकार ऐसा करने से बचना चाहती है, इसलिए नए नियमों को ऐसा बना रही है। जिससे सबको समान रूप से पदोन्नति का लाभ मिल सके।

इस आधार पर देना होगी जानकारी

विभाग ने तृतीय श्रेणी कैडर के जिन पदों की जानकारी मांगी है उसमें हॉस्टल मैनेजर, मुख्य लिपिक, मुख्य लिपिक कम लेखापाल और इससे नीचे के पद के कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही इनके वेतनमान की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में प्रयोगशाला परिचारक, फर्राश, बुक लिफ्टर और इससे नीचे की श्रेणी के पदों का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। प्राचार्यों से कहा गया है कि वे पदों की जानकारी आईएफएमएस में उपलब्ध पदों की जानकारी के आधार पर परीक्षण के बाद रिपोर्ट भेजेंगे। अतिरिक्त संचालक संभाग स्तर पर जानकारी बुलवाने के बाद इसका सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उधर जल संसाधन विभाग ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ विभाग के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के रिक्त पदों और स्वीकृत व वर्तमान पदों पर कार्यरत अफसरों की भी जानकारी मांगी है।

उच्च न्यायालय ने पदोन्नति को लेकर अपने आदेश में कहा है कि जब तक स्टेटस की यथा स्थिति है, तब तक ना डिमोट होंगे और ना ही प्रमोट किया जाएगा, लेकिन जिस दिन स्टेटस बैकेंड हो जाएगा, यथा स्थिति खत्म हो जाएगी। उसी दिन डिमोट करना पड़ेगा। उप्र और उत्तराखंड में भी बाद में गलत पदोन्नति नियम के कारण आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को डिमोट किया गया। केएस तोमर ने बताया कि सपाक्स ने अपनी याचिका में कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण के नियम में क्रीमीलेयर को शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मामले में पंजाब और हरियाणा में पदोन्नति के दौरान क्रीमीलेयर को आरक्षण का लाभ देने से वंचित किया गया है। अजाक्स के प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर श्रवण ने मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की जा रही प्रमोशन प्रकिया को लेकर साधुवाद जताया है। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार वंचित समूह के अधिकारियों और कर्मचारियों के पक्ष में है। इसीलिए हाईकोर्ट में पदोन्नत में आरक्षण नियम रद्द होने के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। शंकर श्रवण ने बताया कि गोरकेला कमेटी ने पदोन्नति को लेकर साल 2017 में प्रस्ताव तैयार किया था। वह अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग सभी के हितों को समाहित करके तैयार किया गया था। गोरकेला कमेटी द्वारा बनाया गया नियम, स्थाई राहत देने वाला दस्तावेज है। इसे वैधानिक चेतावनी नहीं दी जा सकती है।

प्रदेश सरकार ने 9 साल से पेंडिंग कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन के लिए रास्ता निकालने के बाद पदोन्नति के कारण रिक्त होने वाले पदों और पहले से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते उच्च शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग समेत कई विभागों ने संभागीय अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मांगी है। यह जानकारी अप्रैल माह में ही देने के लिए कहा गया है। इसी तारतम्य में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से एक हफ्ते में ही कर्मचारियों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है ताकि आने वाले समय में इसकी समीक्षा कर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की जा सके। उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों के तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बारे में यह जानकारी क्षेत्री अतिरिक्त संचालकों के माध्यम से मांगी है। उच्च शिक्षा आयुक्त ने इसको लेकर सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को पत्र लिखकर कहा है कि सभी शासकीय कॉलेज में रिक्त पदों की संभागवार पूरी जानकारी मंगाकर शासन को भेजें। इसमें कॉलेजों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत, नियमित, आकस्मिक निधि और आउटसोर्स में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी शामिल है।

● हर्ष सक्सेना

पिछड़े क्षेत्रों में गिने जाने वाला बुंदेलखंड बदल रहा है। मप्र और उप्र की सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा रही हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गत दिनों सतना-चित्रकूट 4-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है। यह हाईवे मप्र-उप्र के बीच बीच सेतु का कार्य करेगा। करीब 80 किलोमीटर लंबे इस हाईवे से न सिर्फ आवागमन सुगम होगा, बल्कि दोनों राज्यों के बीच व्यापार-व्यवसाय भी सुदृढ़ होगा। दरअसल, सतना और चित्रकूट के बीच प्रस्तावित 4-लेन हाईवे मप्र को उप्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से कनेक्ट करेगा। जो चित्रकूट को इटावा के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से जोड़ता है। यानी इस सड़क के जरिए सतना उप्र के आगरा, लखनऊ और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से सीधे कनेक्ट हो जाएगा। इससे औद्योगिक विकास भी बढ़ेगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी धार जिले में बदनावर में सड़क परियोजनाओं का शिलाल्यास करने आए थे। इस दौरान प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उनके समक्ष चित्रकूट धाम के विकास के लिए सतना-चित्रकूट 4-लेन सड़क निर्माण की मांग उठाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंच से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। सतना-चित्रकूट 4-लेन ग्रीनफील्ड सड़क भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनाई जानी है। सतना से मैहर के बीच इसका एक हिस्सा लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो सतना को रीवा-जबलपुर फोरलेन (एनएच-30) से जोड़ता है। इस सड़क पर लोगों ने आवागमन भी शुरू कर दिया। हालांकि, सतना नदी पर ब्रिज और बायपास निर्माण अधूरा होने के कारण औपचारिक लोकार्पण अटका हुआ है।

पिछले कुछ सालों से बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर **तेजी से बदलती** नजर आ रही है। आने वाले समय में मप्र और उप्र में फैला बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका होगा, जो दोनों बड़े राज्यों के औद्योगिक शहरों को जोड़ने का काम करेगा। बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने में 2 नेशनल हाईवे अहम भूमिका निभाने वाले हैं। एक नेशनल हाईवे सागर-कानपुर और दूसरा नेशनल हाईवे बुंदेलखंड विकास पथ होगा। इन दोनों नेशनल हाईवे के जरिए उप्र और मप्र के बुंदेलखंड क्षेत्र मप्र के इंदौर, भोपाल, देवास और उप्र के कानपुर, वाराणसी और लखनऊ जैसे बड़े शहरों से जुड़ जाएंगे। बताया जा रहा है कि फिलहाल इन शहरों के आवागमन में जो समय लगता है, नेशनल हाईवे कंप्लीट होने के बाद उसका आधा समय भी नहीं लगेगा। बुंदेलखंड के विकास की उम्मीदों को पंख लगेंगे और पर्यटन, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने मिलेगा।

सागर से कानपुर के सफर के लिए सड़क या रेल मार्ग से फिलहाल 7 से 8 घंटे का समय लगता है। लेकिन सागर-कानपुर हाईवे बन जाने के बाद महज 3 घंटे में ये सफर आसानी से पूरा किया जा सकेगा। मप्र के बुंदेलखंड के संभागीय मुख्यालय सागर से 112 किलोमीटर का कानपुर-सागर नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2026 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल, फिलहाल ये नेशनल हाईवे टू लाइन है, लेकिन इस पर ट्रैफिक व्यवस्था की बहुत समस्या है। खासकर उप्र के कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद जैसे शहरों से जोड़ने वाले इस हाईवे पर वाहनों का भारी दबाव रहता है। आए दिन इन रूटों पर जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। बता दें कि कानपुर-सागर नेशनल हाईवे पर कुल 10 छोटे बड़े पुल बनाए जाएंगे। जिनमें 4 बड़े और 6 छोटे पुल होंगे। इसके अलावा 4 फ्लाईओवर, 21 अंडरपास और 1 आरओबी बनाया जाएगा। इस हाईवे के जरिए उप्र के बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, बांदा जैसे शहर और मप्र के बुंदेलखंड के छतरपुर और सागर शहर सीधे जुड़ जाएंगे।

मप्र में सड़कों का जाल बनाने के लिए भाजपा ने 6 एक्सप्रेस-वे बनाने का वादा अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया था। जिसके तहत मप्र और उप्र के बुंदेलखंड को जोड़ने वाले बुंदेलखंड विकास पथ को बनाया जा रहा है। बुंदेलखंड विकास पथ उन हिस्सों को जोड़ेगा जो सागर-कानपुर हाईवे से सीधे नहीं जुड़ पाएंगे। जिसमें झांसी, ललितपुर, इंदौर और राजधानी भोपाल का नाम शामिल है। बुंदेलखंड विकास पथ झांसी, ललितपुर से होते हुए सागर, भोपाल और देवास तक बनेगा। इसकी लंबाई करीब 330 किमी होगी और आवागमन में लगने वाले समय के साथ ट्रैफिक समस्या को कम करेगा। मप्र-उप्र के बुंदेलखंड को इन दोनों नेशनल हाईवे से बड़ा फायदा होने वाला है। सबसे बड़ा फायदा बुंदेलखंड की खनिज संपदा के लिए होगा। खनिज व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और बुंदेलखंड के पर्यटन व्यवसाय को पंख लगेंगे। मप्र के बुंदेलखंड में खजुराहो, ओरछा, पन्ना के पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उप्र के बुंदेलखंड के झांसी, चित्रकूट और महोबा के पर्यटन स्थल नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा नेशनल हाईवे के किनारे लॉजिस्टिक हब, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, कृषि और दूसरे व्यवसाय बड़े शहरों के बाजार से आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। युवाओं को रोजगार के लिए अब इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक गलियारा बनने जा रहा है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

अब तक 90 प्रतिशत जमीन अधिग्रहित हो चुकी

जनवरी 2025 से लेकर अब तक 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण हो गया है। रोजाना किसानों की जमीन का बेनामा कराया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शासन की तरफ से एक साल पहले 369 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसमें जमीन खरीदने से लेकर गलियारा स्थापित किया जाएगा। इसमें मिहौली व निगड़ा गांव के किसानों की जमीन खरीदी जा रही है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि औद्योगिक गलियारा को लेकर 90 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण का काम हो गया है। जल्द ही बाकी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यूपीडा के डिप्टी कलेक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि जब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो फिर ले-आउट बनाया जाएगा। जिसके बाद जो भी कंपनी अपना उद्योग लगाने की इच्छुक होगी वह प्लाट लेगी। प्लाट आवंटन होने के बाद वह उद्योग लगा सकती है। अधिकतर वह कंपनियां आएगी जो बी-ग्रेड की हैं यानी प्रदूषण कम फैलाती है।

22 अप्रैल को जिस कायराना तरीके से पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछ-पूछकर 26 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया, उससे यह साबित हो गया कि आतंकिस्तान (पाकिस्तान) सुधरने वाला नहीं है। भारत आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। भारत संभावित विकल्पों जैसे राफेल विमानों से एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, मिसाइल हमले और समुद्री नाकेबंदी पर विचार कर रहा है।

● राजेंद्र आगाल

पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकियों की ओर से जिस तरह पर्यटकों से उनका मजहब पूछकर हत्या की गई, वह मानवता को कलंकित करने वाली ऐसी बर्बर घटना है, जिसकी मिसाल मुश्किल से मिलती है। जिहादी आतंकियों ने पहले भी तमाम घटनाओं को अंजाम दिया है, पर कम से कम भारत में यह पहली बार है, जब लोगों का मजहब पता कर हत्या की गई हो। साफ है कि आतंकी मजहबी उन्माद से प्रेरित थे। आतंकियों की ओर से इस तरह हत्या करने का एक मकसद भारत में हिंदू-मुस्लिम खाई पैदा करना भी था। यह अच्छा है कि उनके और पाकिस्तान के इस मकसद को पूरा न होने देने के लिए भारत के लोगों ने कमर कस ली है। मुस्लिम समाज ने पहलगाम की घटना का जिस तरह विरोध किया, काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी और कहा कि इस घटना ने इस्लाम को बदनाम किया है, वह स्वागतयोग्य है। देश में आगे भी सद्भाव बना रहे, यह देखना सभी समुदायों की जिम्मेदारी है।

जबसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, तभी से पाकिस्तान के शासकों की कुदृष्टि भारत पर रही है। लेकिन भारत उनके नापाक इरादों को बार-बार असफल कर देता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान लगातार षड्यंत्र रचता रहा है। इस कड़ी में पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित कर रहा है और भारत के खिलाफ उनका उपयोग कर रहा है। 1972 से लेकर अभी तक भारत पर करीब 12,017 आतंकी हमले किए गए हैं, जिसमें आमजन, पुलिस और सेना के जवान हताहत हुए हैं। पाकिस्तान पोषित आतंक से अब तक 20,044 भारतीय कालकवलित हुए हैं। लेकिन पहलगाम में जिस तरह कायराना अंदाज से पाकिस्तान ने आतंकियों से हत्याएं कराई हैं, उससे भारत ही नहीं, पूरा विश्व उसके खिलाफ है।

सेनाओं को खुली छूट

पाकिस्तान समर्थित आतंकी भारत में खासकर जम्मू-कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियां चलाते रहते हैं। लेकिन पहलगाम हमले ने भारत को इस कदर झकझोर दिया है कि अब देश आर-पार के मूड में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के बादे से पूरे एक्शन मोड में हैं। वे पूरी दुनिया को साफतौर पर संदेश दे चुके हैं कि भारत पहलगाम आतंकी हमले के आतंकवादियों और पर्दे के पीछे साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देगा। साथ ही इससे पहले पुलवामा और उरी के बाद भारत के जवाबी स्ट्राइक से साफ है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को कुछ बड़ा भुगतना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम आतंकी हमले पर लगातार हाईलेवल मीटिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान के साथ एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। साथ ही उन्होंने सेनाओं को खुली छूट दे दी है। तीनों सेनाएं जैसे चाहें, वैसे देश के दुश्मनों को जवाब दे सकती हैं। उन्हें इसके तरीके, लक्ष्य और समय के बारे में फैसला लेने की पूरी अभियानगत छूट है। वहीं, सरकार के कड़े रुख के कारण भारत की ओर से करारी जवाबी कार्रवाई की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर देखें तो पहलगाम हमले के बाद से भारत सरकार एक्शन में है। लगातार हो रही बैठकों में सुरक्षा स्थिति, आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशनों और भविष्य की रणनीति पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इससे पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर पर खौफ है।

पहलगाम की घटना उन चुनिंदा आतंकी घटनाओं जैसी है, जिसने दुनिया की आतंक के प्रति सोच बदली। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने स्थानीय आतंकियों से मिलकर इस घटना को अंजाम इसलिए भी दिया, ताकि यह दिखा सकें कि कश्मीर का माहौल बदला नहीं और वहां शांति नहीं लौट रही है। पाकिस्तान को कश्मीर में सामान्य होती स्थितियां रास नहीं आईं और उसने पहलगाम हमले की साजिश रची। पाकिस्तान से आतंकी कश्मीर में घुसने की कोशिश करते ही रहते हैं। कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं और कुछ कश्मीर के आतंकियों से मिलकर आतंक को बढ़ावा देते हैं। यह सिलसिला इसलिए रुक नहीं रहा, क्योंकि कश्मीर में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो जिहादी मानसिकता से ग्रस्त हैं और इस मुगालते में हैं कि वे पाकिस्तान की मदद से आतंक के सहारे कश्मीर को मजहब के नाम पर आजाद करा लेंगे। इसीलिए वे आतंक की राह पर चलते रहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान उन्हें उकसाता ही नहीं है, हथियार और प्रशिक्षण देने के साथ हर तरह की मदद भी देता है। इन मुट्ठीभर लोगों की पहचान तब संभव है, जब कश्मीर की जनता उनके खिलाफ खुलकर खड़ी हो। पहलगाम की घटना के बाद अनेक लोग खड़े हुए, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि पर्यटकों पर कहर बरपाने वाले आतंकी छिपने में सफल रहे। आखिर किसी ने तो उनकी मदद की होगी। भारत में हुए आतंकी हमले के बाद बदले की कार्रवाई की तैयारी है, जिससे पाकिस्तान में दहशत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा। भारत राफेल विमानों से एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, मिसाइल अटैक और समुद्री नाकेबंदी जैसे कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। राफेल और सुखोई विमानों के साथ थल सेना ने युद्धाभ्यास किया है और अरब सागर में आईएनएस सूरत से मिसाइल दागी गई है। वैश्विक नेताओं ने हमले की निंदा करते हुए भारत का समर्थन किया है।

पहलगाम आतंकी हमले में 15 कश्मीरी चिन्हित

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के आधार पर 15 स्थानीय कश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकी सहयोगियों की पहचान मुख्य संदिग्धों के रूप में की गई है, जिन पर शक है कि उन्होंने पहलगाम नरसंहार में पाकिस्तानी हमलावरों की मदद की थी। माना जा रहा है कि उन्होंने संसाधनों की व्यवस्था करने के साथ-साथ पाकिस्तान से हथियारों की खेप भी प्राप्त की थी। सूत्रों ने कहा कि बहु-एजेंसी जांच ने 5 प्रमुख संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनमें से तीन को पकड़ लिया गया है और अंततः उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस दो अन्य ओजीडब्ल्यू की तलाश कर रही है। हमले के दिन और उससे पहले सभी 5 लोग आसपास के क्षेत्र में थे। उनके फोन इलाके में सक्रिय थे। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी ने एक चैट को सामने लाया, जिसमें हिरासत में लिए गए 3 प्रमुख संदिग्ध पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों और उनकी मदद करने के तरीके के बारे में एक-दूसरे से बात कर रहे थे। इस बीच, सूत्रों ने कहा कि हमले की संभावित घटनाओं का पता लगाने के लिए 200 से अधिक ओवरग्राउंड वर्कर्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हमलावर अभी भी घने पहलगाम जंगलों में छिपे हो सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि पहलगाम हमले में सभी पांचों की भूमिका की ओर इशारा करने वाले पर्याप्त साक्ष्य हैं। एनआईए, जम्मू-कश्मीर पुलिस, खुफिया ब्यूरो और रॉ के जांचकर्ताओं वाली एक संयुक्त पूछताछ टीम द्वारा 10 अन्य ओजीडब्ल्यू से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उन्हें अतीत में कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करने के लिए जाना जाता है और वे 22 अप्रैल को हमले की जगह के आसपास के क्षेत्र में थे।

आर्टिकल 370 हटने के बाद पत्थरबाजी-0, हड़ताल-0...

पहलगाम अटैक के बाद एक बार कश्मीर की स्थिति की चर्चा होने लगी है। पिछले कुछ सालों में कश्मीर में काफी बदलाव हुए हैं, उन पर भी फिर से बहस होने लगी है, जिसमें आर्टिकल-370 आदि शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जिस कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी की घटनाएं होती रहती थीं, उसका आंकड़ा अब जीरो हो गया है। हड़ताल की घटनाएं भी अब कश्मीर में लगभग खत्म हो चुकी हैं। वहीं, आम आदमियों के मौत के आंकड़े में भी काफी कमी आई है। बता दें कि अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा लिया गया था। ऐसे में 2018 और 2023 के आंकड़ों से समझते हैं कि कश्मीर में कितना बदलाव हुआ। अगर पत्थरबाजी की घटनाओं की बात करें तो साल 2018 में पत्थरबाजी की 1328 घटनाएं हुई थीं, लेकिन 2023 में ये आंकड़ा 00 में तब्दील हो गया था। वहीं, 2024 (21 जुलाई तक) में भी एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई। इसके अलावा हड़ताल की बात करें तो साल 2018 में 52 घटनाएं हुई थीं, लेकिन 2023 और 2024 (21 जुलाई तक) में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। अगर आतंकवादी घटनाओं की बात करें तो साल 2018 में 228 आतंकी घटनाएं हुई थीं और 2023 में ये आंकड़ा 46 पहुंच गया। वहीं, 2024 (21 जुलाई तक) 11 आतंकी घटनाएं रिकॉर्ड की गई। घाटी में साल 2018 में 189 एनकाउंटर हुए थे और साल 2023 में ये घटकर 48 रह गए और 2024 (21 जुलाई तक) में 24 एनकाउंटर की घटनाएं हुईं। लोकसभा में दिए गए जवाब में बताया गया है कि साल 2018 में 91, 2023 में 30 जवान शहीद हुए थे। जबकि 2024 (21 जुलाई तक) में 14 जवानों की जान गई। सरकारी डेटा के हिसाब से साल 2018 में आतंकवाद की वजह से 55 आम लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2023 में ये आंकड़ा घटकर 14 हो गया। साल 2024 (21 जुलाई तक) में 14 लोगों की जान गई है। कश्मीर में 2018 से आतंक की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं और सेना, आम लोगों को भी कम नुकसान हुआ है।

22 घंटे जंगलों में चलकर बैसरन पहुंचे थे 3 पाकिस्तानी आतंकी

पहलगाम आतंकी हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं ने की थी। कश्मीर के बैरसन घाटी में खून-खराबे के लिए उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। जांच से पता चला है कि आतंकवादी कोकरनाग के जंगलों से 20-22 घंटे पैदल चलकर आए थे। आतंकियों ने एक लोकल कश्मीरी और एक टूरिस्ट से मोबाइल फोन छीने थे। हमले में 4 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें 3 पाकिस्तानी और 1 स्थानीय आदिल ठोकर हुसैन था। एनआईए के अधिकारी फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से पूरे बैसरन घाटी में सुराग ढूंढ रहे हैं। आदिल ठोकर हुसैन 2018 में महजबी तौर से कट्टरपंथी बनने के बाद हिज्बुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। वह वैध दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान गया, जहां उसने लश्कर-ए-तैयबा के साथ कड़ी ट्रेनिंग ली। 2024 में वह कश्मीर घाटी लौट आया और कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों का मददगार बन गया। उसने पाकिस्तान से आए आतंकियों को पनाह दी। उसने लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया। इसके अलावा वह आतंकियों के लिए गाइड का काम करता रहा। उसकी मदद से ही पाकिस्तानी आतंकियों ने कोकरनाग के जंगलों में 22 घंटे की ट्रैकिंग की। जांच में यह भी सामने आया है कि आदिल ने अपना नेटवर्क भी बना रखा था। टूरिस्टों के बीच रोजी-रोटी कमाने वाले भी उसके मुखबिर थे।

उबल रहा हिंदुस्तान का खून

भारत के निर्दोष नागरिक पर जिस तरीके से आतंकी प्रहार हुआ है। उसके बाद समूचे हिंदुस्तान का खून उबल रहा है। भारत बदले की कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान को हमेशा के लिए एक बड़ा सबक सिखाएगा। भारत और पाकिस्तान युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। पीओके, वैसे भी दस्तावेजों के अनुसार भारत का ही है। जनरल असीम मुनीर बौखला गए हैं। मुनीर ने फिर से दोहराया है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग-अलग कौम हैं और साथ नहीं रह सकते हैं। पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा है तो अब भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। भारत के लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया र से संवेदनाएं आ रही हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सभी ने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है।

भारत के आक्रामक संकेत

भारत के शौर्य को जल, थल, नभ तीनों क्षेत्रों में देखकर पाकिस्तान में दहशत है। उसकी बातों से झलक रहा है कि न जाने किस पल भारत का गुस्सा टूट पड़ेगा और तबाह कर देगा उसकी आतंकी नर्सरी को, जिसे उसने दशकों से पाल-पोस कर बड़ा किया है। संकेत बता रहे हैं कि भारत इस बार आर-पार के मूड में है। **संकेत नंबर एक-** राफेल, सुखोई ने किया युद्ध अभ्यास। **संकेत नंबर दो-** हेलिकॉप्टर सवार सैनिकों के साथ थल सेना का युद्ध अभ्यास। **संकेत नंबर तीन-** अरब सागर में आईएनएस सूरत से दागी मिसाइल। **संकेत नंबर चार-** 27 से अधिक देशों के राजनयिकों से बातचीत। **संकेत नंबर पांच-** राष्ट्रपति से मिले गृहमंत्री और विदेश मंत्री। **संकेत नंबर छह-** रूसी मीडिया की कुछ बहुत बड़ा होने की चेतावनी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि भारत संकेतों से आगे निकलकर माकूल जवाब जरूर देगा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि उससे क्या और कितना असर पड़ेगा, क्योंकि भारत ने जवाब देने के कई चरणों को

चुना है। भारत ने फौरी तौर पर सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया है और सार्क वीजा की सुविधा भी बंद कर दी है। लेकिन ये बस ट्रेलर है। पूरी पिक्चर क्या होगी, ये पाकिस्तान सोचने से भी कांप रहा है। भारत जो सबक पाकिस्तान को सिखाएगा वो क्या और किस तरीके से हो सकता है? क्योंकि सशक्त, मजबूत भारत के पास विकल्प तमाम हैं। मिसाइल से हमला, सागर में नाकाबंदी, ड्रोन अटैक, राफेल एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक सबकुछ संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर भाषा में कोई प्रॉब्लम थी तो उन्होंने अंग्रेजी में भी स्पष्ट कर दिया है।

पाकिस्तान बड़े हमले की सूरत में भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है, तो भारत उसके लिए तैयार है। ये सच है कि अगर पाकिस्तान ने परमाणु बम चलाया तो भारत को भारी नुकसान होगा, लेकिन ये भी सच है कि अगर भारत ने जवाब दिया तो पूरा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल विमान होते तो पाकिस्तान की सीमा में दाखिल किए बिना ही भारत आतंक का समूल विनाश कर चुका होता। अब भारत के पास राफेल विमान हैं। क्या भारत अपनी वायु शक्ति के जरिए पाकिस्तान को फिर जवाब दे सकता है? अब वक्त आ गया है कि आसमान का सीना चीरकर भारत की वायुसेना पाकिस्तान के उन अड्डों को तबाह करे जहां से भारत के खिलाफ साजिशें होती हैं। अब वक्त आ गया है भारत के सबसे ताकतवर हथियारों को निकालने का। अब वक्त आ गया है राफेल के इम्तिहान का।

पाक डरेगा, फिर वही करेगा

यदि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की जाती है तो वह कुछ डरेगा, लेकिन फिर वही करेगा, जो उसने मुंबई, उरी, पठानकोट, पुलवामा और पहलगाम में किया। वह नए-नए तरीकों से हमले करेगा। जैसे उसने पहलगाम में किया। आम धारणा थी कि आतंकी सेना, पुलिस, कश्मीरी पंडितों, गैर कश्मीरियों और हिंदू तीर्थयात्रियों को ही निशाना बनाते हैं, लेकिन पर्यटकों को नहीं। इस बार उन्होंने पर्यटकों में हिंदू चुनकर मारे। एक मुस्लिम और एक ईसाई भी उनके हाथों मारे गए। शायद इसलिए, क्योंकि जिहादी अपने दुश्मनों के साथ वालों के बारे में यही मानते हैं कि वे भी उन्हीं में से हैं। इसीलिए अतीत में तमाम कश्मीरी मुस्लिम भी उनके निशाने पर आए। चूंकि यह मान लिया गया था कि आतंकी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते, इसलिए उनकी सुरक्षा पर जरूरी ध्यान नहीं दिया गया। सुरक्षा में चूक के जो सवाल उठ रहे हैं, वे जायज हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं, जैसे सरकार ने पूरी चौकसी न बरतकर आतंकियों को पर्यटकों को मारने का लाइसेंस दे दिया। हर आतंकी हमले के पीछे कहीं न कहीं सतर्कता में कमी होती है।

9/11 के समय भी थी, 26/11 के वक्त भी थी और 22 अप्रैल को पहलगाम में भी थी। कश्मीर में चौकसी बढ़ाने से हमले कम तो हो सकते हैं, पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। यह एक तथ्य है कि जम्मू-कश्मीर में रह-रहकर आतंकी हमले हो ही रहे थे। पाकिस्तानी सेना जब तक हिंदू भारत से घृणा पर पलती रहेगी, तब तक वह जिहादी भेजती रहेगी। लश्कर, जैश के जिहादी पाकिस्तानी सेना के बिना वर्दी वाले सैनिक ही हैं। पहलगाम हमले के बाद देश गुस्से में उबल रहा है, लेकिन पाकिस्तान का ठंडे दिमाग से शर्तिया इलाज करना होगा, ताकि फिर कभी मुंबई, उरी, पुलवामा, पहलगाम जैसा हमला न हो। कोई भी दल या सरकार हो, उसे यह सोच बदलनी होगी कि पाकिस्तान बिना होश ठिकाने आए सुधर जाएगा। सोच समूचे सरकारी तंत्र को भी बदलना होगा, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पता चला कि कई पाकिस्तानी वीजा अवधि पूरी होने के बाद भी रह रहे थे। यदि हम सचेत होते और शत्रु के शैतानी-जिहादी इरादों को भांप रहे होते तो आज स्थिति दूसरी होती। स्थिति केवल सरकार, सेना और पुलिस आदि को ही नहीं बदलनी, हमें भी बदलनी है। निसंदेह इतने बड़े देश में सबकुछ आदर्श स्थिति में नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने जो गहन संकट खड़ा किया है, उसके कारणों और उससे निपटने के तरीकों को लेकर असहमतियां-विवाद के साथ सरकार की आलोचना-निंदा भी होगी, लेकिन आखिर यह समझने में क्या कठिनाई है कि निशाने पर हम सब हैं? भारत के प्रति घृणा में डूबे पाकिस्तान ने पहलगाम में भीषण आतंकी हमला कराकर यही साबित किया कि वह न तो

अमेरिका इधर भी, उधर भी

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहा है। उधर, पाकिस्तान खुद को पाक साफ बता रहा है। वो कह रहा है कि हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर गुहार लगा रहा है। दोनों देशों में जारी तनाव के बीच अमेरिका का रुख भी अहम हो जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश किसका साथ देता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। वैसे तो अमेरिका और भारत के बीच अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री जगजाहिर है। लेकिन मौजूदा स्थिति में अमेरिका का अप्रोच बैलेंस रहा है। वो दोनों देशों (भारत और पाकिस्तान) से बातचीत की बात कह रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि हम दोनों देशों से बात कर रहे हैं, लगातार बातचीत चल रही है और मल्टीलेवल पर हो रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात करेगा। उन्होंने कहा कि हम वहां होने वाले सभी घटनाक्रमों पर भी नजर रख रहे हैं। ब्रूस ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ कई स्तरों पर संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ये संपर्क सिर्फ विदेश मंत्री स्तर पर ही नहीं, बल्कि कई स्तरों पर है। टैमी ब्रूस ने कहा कि हम निश्चित रूप से सभी पक्षों को एक जिम्मेदार समाधान के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दुनिया इस पर नजर रख रही है, लेकिन मेरे पास इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है। भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, क्योंकि वाशिंगटन चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना चाहता है। वहीं, पाकिस्तान भी वाशिंगटन का सहयोगी बना हुआ है, भले ही पड़ोसी अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद उसका महत्व कम हो गया हो।

खुद चैन से रहेगा और न हमें रहने देगा। पहलगाम के पहले 2013 में नैरोबी के एक माल और 2016 में ढाका के एक कैफे में जिहादियों ने लोगों से कलमा (मुस्लिम होने की जरूरी निशानी) सुनाने की मांग कर हत्या की थी। क्या आतंक का मजहब होता है? इस पर बहस होती रहेगी, लेकिन इस पर बहस की गुंजाइश नहीं कि इन हमलों को अंजाम देने वाले मजहबी प्रेरणा से लैस थे। इसीलिए तो कई मुस्लिम नेताओं ने कहा कि पहलगाम हमले ने हमें शर्मिंदा किया, पर कुछ लोग यह साबित करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाए हैं कि आतंकियों ने लोगों का मजहब नहीं पूछा। यह आतंकियों को क्लीनचिट देना है। यह काम पश्चिमी मीडिया भी बेशर्मी से कर रहा है। पश्चिम में शायद ही अधिकांश लोग इस सच से अवगत हों कि पहलगाम में लोगों को उनका मजहब पूछकर मारा गया। पश्चिमी मीडिया की जिहादियों का बचाव करने वाली इस करतूत की कीमत एक दिन पूरा पश्चिम चुकाएगा।

पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त

पहलगाम में हिंदू पर्यटकों का संहार भारत में एक बार फिर हिंदू-मुस्लिम विभाजन कराने की पाकिस्तानी सेना की साजिश का हिस्सा है। इसका संकेत पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर ने 16 अप्रैल को एक भाषण में हिंदुओं और मुसलमानों को हर पहलू से दो अलग कौमें बताकर दिया था। यही बात उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य अकादमी की परेड में दोहराई। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इमारत इसी विचार की नींव पर खड़ी की गई थी। यदि इस आतंकी हमले को पाकिस्तानी सेना की विभाजनकारी साजिश मान भी लिया जाए तो भी उसकी सबसे बड़ी नाकामी तो उसी जगह पर हो गई, जिसे उसने लॉन्च पैड बनाया। कश्मीर की घाटी में पिछले 35 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ कि हिंदुओं पर जिहादी हमले की मस्जिदों से भर्त्सना हुई हो, शांति मार्च निकाले गए हों और घाटी में बंद रहा हो। जनरल मुनीर का दो देशों वाला सिद्धांत कोई नया नहीं है। कश्मीर पर पाकिस्तानी दावे का प्रमुख आधार यही रहा है।

अनुच्छेद-370 के हटने और विश्व जनमत तथा मुस्लिम जनमत को उसके खिलाफ लामबंद करने में पूरी तरह विफल हो जाने के बाद पाकिस्तान हताशा की स्थिति में है। इसलिए संभव यह भी है कि कश्मीर के मुद्दे को विश्वमंच पर उछालने के लिए जनरल मुनीर के दिमाग में जनरल मुशर्रफ वाला दुस्साहस रहा हो। मुशर्रफ ने राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा के समय छत्तीसिंहपुरा का आतंकी हमला कराया था। पहलगाम आतंकी हमले लिए भी ऐसा समय चुना गया, जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा पर थे, लेकिन यहां भी जनरल मुनीर के मंसूबे पूरे नहीं हुए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दोनों ने हमले को आतंकी बताते हुए उसकी कड़ी निंदा की और भारत को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया।

जम्मू-कश्मीर के जिहादी आतंकी संगठन प्रतिरोध मोर्चा या टीआरएफ ने पहले तो हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन बढ़ते दबाव के बाद वह मुकर गया। अब पाकिस्तान चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत को चरितार्थ करते हुए किसी बाहरी संस्था से इसकी तटस्थ जांच कराने में मदद करने की पेशकश कर रहा है। भारत को इस पेशकश के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान यह मांग करके दुनिया को दिखाना चाहता है कि हमले में उसका कोई हाथ नहीं है।

भारत के लोग वास्तव में यह जानना चाहेंगे कि पर्यटकों के लिए जून में खोली जाने वाली दुर्गम बैसरन घाटी अप्रैल में किसकी अनुमति से खोली गई और घाटी की दुर्गमता को देखते हुए वहां पुलिस और सेना की सुरक्षा क्यों नहीं थी? एक बड़ा सवाल यह भी है कि दो हजार पर्यटकों को लेकर गए घुड़सवारों और माल बेचने वालों में से किसी ने भी अपने फोन से आतंकियों के वीडियो क्यों नहीं बनाए? इतना सुनियोजित हमला स्थानीय लोगों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता था तो फिर खुफिया तंत्र को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसकी चूक से हुआ, इसकी गहन जांच और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन पहले पाकिस्तान की हरकत का प्रतिकार करने के बाद। हर काम का वक्त होता है। अभी पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त है। ऐसा कहीं नहीं होता कि हमले का प्रतिकार करने से पहले लोग सेना और सरकार से इस्तीफा मांगने लगें। ऐसा न इजरायल में हमास के हमले के बाद हुआ और न अमेरिका में अलकायदा के हमलों के बाद। न ब्रिटेन में हुआ और न फ्रांस में। पूरा देश एकजुट होकर पहले प्रतिकार का समर्थन करता है। कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद जांच होती है और जिम्मेदारियां तय होती हैं।

वॉटर स्ट्राइक से टूटेगी कमर, तीन तरफा होगा पाकिस्तान पर असर

पहलगाम आंतकी हमले से पूरा देश गम और गुस्से में है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आंतकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई और इनमें दो विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं, जबकि कई गंभीर घायल हुए हैं। इसके बात एक्शन में आते हुए भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है और सबसे बड़े फैसलों में सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल है। इस वॉटर स्ट्राइक से न केवल पड़ोसी देश को चावल खाने और पानी पीने के लाले पड़ सकते हैं, बल्कि कई राज्य अंधेरे में डूब सकते हैं। इसका सीधा असर पाकिस्तान की डीजीपी पर देखने को मिल सकता है। कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत के बाद भारत सरकार ने कई कड़े फैसले किए हैं। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करना पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसकी रणनीति में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। संधि की बाध्यताएं खत्म होने से पाकिस्तान की कृषि, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था तीनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सिंधु नदी पड़ोसी देश की लाइफलाइन मानी जाती है।

तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा की गई आलोचना ने न्यायपालिका और विधायिका के बीच फिर एक बार टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। तमिलनाडु सरकार की ओर से विधानसभा में पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल की सहमति रोके रखने का मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। अपने अनूठे निर्णय में न्यायालय ने न सिर्फ इन लंबित विधेयकों को राज्यपाल की सहमति के बिना ही मंजूर घोषित किया, बल्कि राज्यपाल के लिए तीन माह के भीतर ऐसे बिलों को वापस विधानसभा भेजने अथवा राष्ट्रपति के समक्ष विचार हेतु प्रेषित करने की समयसीमा भी निश्चित कर दी। इतना ही नहीं, न्यायालय ने अपने फैसले में राष्ट्रपति को भी निर्देश दिया कि उन्हें राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर तीन माह के भीतर निर्णय लेना होगा। जस्टिस जेबी पार्डीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति की निष्क्रियता के खिलाफ राज्य अदालत जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने राज्यपाल की शक्तियों का अधिग्रहण कर विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप तो किया ही, संघीय ढांचे में केंद्र की ओर शक्ति के झुकाव को भी कुंद किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इसी पर आपत्ति जताई। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के जज यशवंत वर्मा के घर मिले अधजले नोटों के मामले में कोई एफआईआर न दर्ज किए जाने पर भी प्रश्न खड़े किए। समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर केंद्रीय कानूनों की सर्वोच्चता, सातवीं अनुसूची में शामिल होने से रह गए अवशिष्ट विषयों पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार, अनुच्छेद-356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार ऐसे कुछ प्रविधान हैं, जो केंद्र की सर्वोच्चता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं। अनुच्छेद-355 एक ऐसी शासकीय व्यवस्था की कल्पना करता है, जिसमें केंद्र पर यह सुनिश्चित करने का भार होता है कि राज्य सरकारें अपने दायित्व का पालन संवैधानिक प्रविधानों के अनुरूप करें। इसीलिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति की अपेक्षा राज्यपाल के पास कहीं अधिक और वास्तविक शक्तियां होती हैं।

कानून एवं व्यवस्था बिगड़ने या फिर असंवैधानिक कार्यकलापों का मामला संज्ञान में आने पर वह विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकता है। अनुच्छेद-200 के अंतर्गत स्वीकृति हेतु राज्यपाल के समक्ष आए विधेयकों को अनुमति देने या राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए आरक्षित रखने की कोई सीमा नहीं है। जिन 10 विधेयकों को लेकर राज्य सरकार ने याचिका दायर की, उनमें एक विश्वविद्यालयों में कुलपति के चयन का अधिकार राज्यपाल से हटाकर मंत्री परिषद को देने की बात करता है। ऐसे में याचिका का दायरा सीमित कर विषय केंद्रित किया जा सकता था, परंतु राज्यपाल और राष्ट्रपति, दोनों के लिए प्रत्येक विधेयक को अनुमति की समयसीमा में बांधे जाने ने न केवल राज्यपाल के पद को कमजोर किया, बल्कि राज्य को एक तरह से केंद्रीय पर्यवेक्षी अधीनता से मुक्त कर दिया।

न्यायपालिका बनाम विधायिका

क्या देश में गृह युद्ध का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट?

पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद से उभरी चिंगारी की ओर ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इशारा कर कहते हैं कि देश में गृह युद्ध का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। संयोग से, 21 अप्रैल को उसी हिंसा के मामले में राज्य में केंद्रीय पुलिस बल भेजने और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वकील विष्णु शंकर जैन पर न्यायाधीश बीआर गवई और एजी मसीह की खंडपीठ की टिप्पणी से न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका के ज्वलंत मुद्दे में तनाव नए ठौर पर पहुंचता दिखा।

ऐसी व्यवस्था के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। नागरिकता संशोधन और वक्फ कानून के विरोध में पारित प्रस्तावों के जरिये विभिन्न विधानसभाएं कई बार अपने भयावह मंतव्यों को प्रकट कर चुकी हैं। तमिलनाडु विधानसभा तो कोयंबटूर बम धमाकों में निरुद्ध विचाराधीन कैदी अब्दुल नसीर मदनी की रिहाई का प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राष्ट्र की एकता और अखंडता को दुविधाजनक स्थिति में डाल सकता है। हाल में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी प्रस्तावित विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा है। मजहबी आधार पर आरक्षण की व्यवस्था तय करने वाला यह विधेयक पूरी तरह गैर संवैधानिक है, पर शीर्ष अदालत का हालिया निर्णय राष्ट्रपति को यह विधेयक पास करने के लिए बाध्य करेगा।

ऐसी सूरत में इसके निस्तारण का एकमात्र उपाय फिर सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे के रूप में ही होगा। यह संकट उस बढ़ती प्रवृत्ति का द्योतक है, जिसमें न्यायपालिका विधायिका के ऊपर एक सुपर वीटो के रूप में उभरती दिखाई दे रही है। चाहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को रद्द करना हो या कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक, विधायिका के क्षेत्र में न्यायपालिका का अतिक्रमण जारी है। पिछले कुछ समय से संसद द्वारा पारित करीब-करीब हर विधेयक का न्यायपालिका द्वारा तुरंत संज्ञान लेना भी एक परिपाटी बन गई है। इसी कारण राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दिए जाने के एक सप्ताह बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ कानून पर सुनवाई शुरू हो गई। लंबे समय तक संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को उपयोग में लाने के बाद अब अनुच्छेद-142 न्यायिक अतिक्रमण का आधार बन गया है। तमिलनाडु के मामले में भी न्यायालय ने इसी का सहारा लिया है। अनुच्छेद-142 वह असाधारण प्रविधान है, जो सर्वोच्च न्यायालय को उन मामलों में पूर्ण न्याय प्रदान करने की गुंजाइश देता है, जहां कोई प्रत्यक्ष कानूनी उपाय मौजूद न हो। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संघीय कार्यपालिका को किसी विधेयक की वैधता निर्धारित करने में न्यायालयों की भूमिका नहीं निभानी चाहिए तथा उसे अनुच्छेद-143 के अंतर्गत ऐसे प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय भेजना चाहिए।

● रजनीकांत पारे

आने वाले दिनों के लिए कांग्रेस का फ्यूचर प्लान क्या है, ये राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस का फ्यूचर राहुल गांधी के फ्यूचर प्लान पर ही टिका है। कांग्रेस 2014 से सत्ता से बाहर है और अभी उसे 2029 तक सत्ता से बाहर ही रहना है। सत्तारुढ़ होने के लिए उसे अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर ऐसा फ्यूचर प्लान बनाना होगा जो उसकी सत्ता में वापसी करा सके। कांग्रेस की जैसी तैयारी अभी दिखाई देती है उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस के लिए सत्ता अभी भी आकाश-कुसुम जैसी ही है।

राहुल के फॉर्मूला पर चलेगी कांग्रेस

कांग्रेस आगे किस राह पर चलेगी, इसका फॉर्मूला राहुल गांधी ने तय कर दिया है। पूरे देश के 862 जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में राहुल गांधी ने बता दिया कि कांग्रेस का फ्यूचर प्लान क्या है। बैठक के बाद जो एजेंडा सामने आया, उससे लग रहा है कि कांग्रेस भी अब भाजपा की राह पर चलने की तैयारी कर रही है। सबकुछ बदलने का प्लान है। कांग्रेस की अहमदाबाद में हुई दो दिन के चिंतन और मंथन बैठक से जो निचोड़ सामने आया, उसे पार्टी ने न्याय पथ का नाम दिया है। देशभर से आए अपने लगभग 2000 आईसीसी डेलिगेट्स के बीच कांग्रेस ने जब प्रस्तावना के रूप में अपना आगामी संकल्प सामने रखा, तो वहां मौजूद तमाम प्रतिनिधियों ने अपने दोनों हाथ उठाकर इनका अनुमोदन किया। राजस्थान के युवा नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वह पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जहां न्याय पाठ की संकल्पना सामने रखी तो वही पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद शशि थरूर ने उसका अनुमोदन किया। उल्लेखनीय है कि साबरमती के तट से कांग्रेस ने दो संकल्पनाओं के प्रस्ताव को पारित किया, जिसमें से पहला प्रस्ताव देश के लिए था, जबकि दूसरा प्रस्ताव गुजरात पर केंद्रित था।

अपने अनुमोदन में कांग्रेस के थरूर ने कहा कि उनकी पार्टी को रोष, अतीत और नकारात्मक आलोचना की नहीं, बल्कि आशा, भविष्य और सकारात्मक विमर्श वाला दल होना चाहिए। साथ ही, पार्टी को उन मतदाताओं का समर्थन फिर से हासिल करने की कोशिश करनी होगी, जो 2009 में पार्टी के साथ थे। कांग्रेस को भविष्य की पार्टी होना चाहिए, सिर्फ अतीत की नहीं। सकारात्मक विमर्श वाली पार्टी होनी चाहिए, न कि केवल नकारात्मक आलोचना की। लगभग सात पेज के प्रस्ताव में कांग्रेस ने सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक बिंदुओं के साथ-साथ राष्ट्रवाद, विदेश नीति, सर्वधर्म, किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं से जुड़े बिंदु और संगठन की मजबूती से जुड़े तमाम बिंदुओं पर बात की। उल्लेखनीय है कि जिस तरह से भाजपा व संघ द्वारा देश में आपके विचार को आगे बढ़ाया जा रहा है और अपनी विरोधी विचारधाराओं के राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसके मद्देनजर पार्टी ने राष्ट्रवाद पर अपना पक्ष रखने की कोशिश की। कांग्रेस ने राष्ट्रवाद की अपनी अवधारणा को सामने रखते हुए कहा कि हमारे लिए राष्ट्रवाद का मतलब देश की भू-भागीय अखंडता के साथ-साथ यहां रहने वाले लोगों का सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सशक्तिकरण है। राष्ट्रवाद का मतलब सभी देशवासियों के लिए समान न्याय की अवधारणा और वंचित पीड़ितों शोषितों के अधिकारों की रक्षा और उत्थान के साथ-साथ भारत के बहुलतावादी स्वरूप का सम्मान है। पार्टी ने भाजपा के राष्ट्रवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का समाज राष्ट्रवाद को जोड़ने का है तो भाजपा व संघ का समाज को तोड़ने का। प्रस्तावना में कांग्रेस ने भाजपा और संघ पर भारत की अनेकता को खत्म करने का आरोप लगाते हुए कहा का राष्ट्रवाद पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कांग्रेस ने तंज करते हुए कहा कि जिस संघ ने देश की आजादी, खासकर के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, वही राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने का ठेका लिए हुए हैं। पार्टी ने भाजपा और संघ के राष्ट्रवाद को छद्म और अवसरवादी करार देते हुए निशाना साधा कि भाजपा के राष्ट्रवाद की प्राथमिकता देश नहीं, बल्कि सत्ताप्रियता है।

गौरतलब है कि भाजपा की तरफ से लगातार राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठाया जाता रहा है, ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा व संघ के राष्ट्रवाद का जवाब देने के लिए बाकायदा रणनीति के तहत एक सच सामने रखने की कोशिश की। इतना ही नहीं अपनी संकल्पना में कांग्रेस ने देश के सामने प्रजातंत्र का प्रहरी और संविधान का रक्षक बताने

शुरुआत गुजरात से ही करनी होगी

कांग्रेस समझ चुकी है कि अगर देश में भाजपा को सत्ता से उतारना है तो उसकी शुरुआत गुजरात से ही करनी होगी। इसलिए वह देश की आजादी की लड़ाई में गुजरात के योगदान को रेखांकित करते हुए मौजूदा हाल में भी गुजरात से भाजपा की सत्ता को चुनौती की योजना बना रही है। कांग्रेस समझ रही है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के गृह राज्य में भाजपा हारती है तो फिर देश के बाकी राज्यों में इन दोनों के अजेय होने का तिलस्म टूट जाएगा। इसमें जहां एक ओर कांग्रेस ने इतिहास में गुजरात और कांग्रेस के रिश्तों को सामने रखने की कोशिश की, वहीं उसने अपने शासन में गुजरात में हुए विकास की गाथाओं का भी जिक्र किया, फिर चाहे आनंद में हुई दूध क्रांति हो या नर्मदा सिंचाई योजना और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का अस्तित्व में आना, कांग्रेस ने बताने की कोशिश की कि आजादी के बाद गुजरात के विकास में कांग्रेस की कैसी अहम भूमिका रही।

की कोशिश भी की। इस कोशिश में कांग्रेस ने ऐसी तमाम घटनाओं और उदाहरण का जिक्र किया जहां भाजपा द्वारा संविधान या निशान लगाने की कोशिश की गई। फिर चाहे साल 2000 में समीक्षा संविधान की समीक्षा आयोग बनाने की बात हो या फिर 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा देकर संविधान बदलने का दावा करना। दरअसल कांग्रेस राष्ट्रवाद और संविधान की रक्षा के मुद्दे को लेकर देश के सामने इन दोनों बिंदुओं पर दोनों प्रमुख प्रिय दलों की सोच के अंतर को सामने रखने की कोशिश करती दिखी।

प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं पर पाइलट का कहना था कि देश में जो हालात बने हैं, वो सबके सामने हैं। पिछले दस साल में महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और धार्मिक ध्रुवीकरण ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। इसलिए कांग्रेस अब नफरत, नकारात्मकता और निराशा के वातावरण को बदलकर न्याय और संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्ताव में कहा गया कि मणिपुर में भाजपा की सत्ता ने प्रायोजित हिंसा कराई, कानून-व्यवस्था तहस-नहस हो गई, गृहयुद्ध जैसे हालात बने रहे, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाकर भाजपा नीत सत्ता को लंबे समय तक बनाए रखा गया। प्रधानमंत्री के पास मणिपुर के लोगों का दुख-दर्द जानने के लिए न समय है, न इच्छा। कांग्रेस ने प्रस्ताव में दावा किया कि सत्ताधारी ताकतों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग अथवा अनुचित दबाव द्वारा हर संस्था पर किए जा रहे हमले से अब न्यायपालिका भी अछूती नहीं रही है। सामाजिक न्याय पर कांग्रेस का कहना था कि पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि हम केंद्रीय कानून बनाकर एससी-एसटी सबप्लान को कानूनी आकार देंगे और इन समुदायों को आबादी के हिसाब से बजट में हिस्सेदारी देंगे। साथ ही, कांग्रेस ने एससी, एसटी व ओबीसी के लिए आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को बढ़ाने को लेकर भी अपना इरादा जताया।

वहीं कांग्रेस ने पिछले तीन दशकों में भाजपा शासनकाल में राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के गिरते स्तर, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की स्थित, छोटे उद्योगों की हालत को लेकर निशाना साधा। इसी के साथ कांग्रेस ने एक रोडमैप देने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस यहां सत्ता में आती है कि तो युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। अपनी प्रस्तावना में कांग्रेस ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से एक आधुनिक और विकसित गुजरात सहित भारत का निर्माण करने के लक्ष्य के साथ कृषि, औद्योगिक सेवा क्षेत्र, महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे और महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करेंगे।

सभी नेताओं को बोलने का मौका मिला

कांग्रेस के अधिवेशन में अच्छी बात ये रही कि स्लीपर सेल समझे जाने वाले नेताओं को भी बोलने दिया गया। असंतुष्ट नेताओं का प्रतिनिधित्व शशि थरूर जैसे नेताओं ने किया। अब कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं की संख्या पहले के मुकाबले कुछ कम हुई है। कांग्रेस अब राहुल गांधी के नियंत्रण वाली कांग्रेस है। कांग्रेस को परिवारवाद से मुक्त करना-कराना एक अलग मुद्दा है जो शायद इस अधिवेशन में बहस के लिए नहीं आया। आ भी नहीं सकता था। यही परिवारवाद कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है और सबसे बड़ी ताकत भी। कांग्रेस के लिए ये अंतिम अवसर है, 2029 के बाद कांग्रेस मुमकिन है कि किसी कालपात्र में पड़ी दिखाई दे, वामपंथी दलों की तरह या समाजवादी दलों की तरह। राहुल गांधी जिस दिन अपना फ्यूचर प्लान सार्वजनिक करेंगे उस दिन हम भी बता सकेंगे कि कांग्रेस का फ्यूचर क्या है? कांग्रेस ने टाइगर मोदीजी की मांद में घुसकर उन्हें चुनौती दी है, देखिए आगे-आगे होता है क्या?

राजनीतिक पार्टियां अपने अधिवेशन के मंथन से वर्तमान तथा भविष्य की जरूरतों-चुनौतियों का कुछ न कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करती हैं। अधिकांश राज्यों में सियासी वनवास झेल रही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस साबरमती तट पर इस हफ्ते हुए अपने अधिवेशन में यही कोशिश करती दिखी। इस मंथन से निकला सियासी अमृत पार्टी को कितनी संजीवनी देगा यह तो वक्त बताएगा मगर गुजरात में लंबे अर्से से प्रभावी नेता रणनीतिकार की उसकी खोज शक्ति सिंह गोहिल के रूप में पूरी होती दिखी। भाजपा के इस सबसे मजबूत गढ़ में तीन दशक से सत्ता से कांग्रेस के बाहर होने के बावजूद अधिवेशन का प्रभावी तरीके से आयोजन करने के गोहिल के प्रबंधन ने हाईकमान को भी हैरान कर दिया। शायद तभी शिकायत रहित इस आयोजन की खुली प्रशंसा में हाईकमान ने भी कंजूसी नहीं दिखाई। लगातार छह विधानसभा चुनाव की पराजय की पृष्ठभूमि के बावजूद अधिवेशन में गुजरात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसलों की उड़ान तथा लड़ने के जज्बे ने उप्र, बिहार, दिल्ली तथा मप्र जैसे राज्यों के नेता भी हतप्रभ नजर आए। ऐसे कुछ नेता यह कहते सुने गए कि दो चुनावों की हार ने ही हमारे उत्साह को छीन लिया मगर इतनी शिकस्तों के बाद भी गुजरात में कार्यकर्ताओं का ऐसा हौसला दूसरे राज्यों के कांग्रेसियों के लिए नजीर है।

बहरहाल इस नजीर से गुजरात में कांग्रेस की तकदीर गोहिल बदल पाएंगे या नहीं यह तो 2027 में ही पता चलेगा। बिहार की राजनीति में भाजपा नेता अश्विनी चौबे अपने उल्टे-पुल्टे बयानों के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार की लाइन से अलग चलने वाले बाबा ने जब भी मुंह खोला है-हलचल ही मचाई है। इस बार उन्होंने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग की है, जिसके बाद से बिहार में बवाल मचा हुआ है। लोग इसका सीधा अर्थ लगा रहे हैं कि बाबा ने नीतीश की तारीफ की है, लेकिन खबर है कि भाजपा के लोग परेशान हैं कि बाबा के ऐसा बोलने से नीतीश के समर्थक भड़क सकते हैं। इसलिए बाबा के बयान को तुरंत निजी विचार बताने में देर नहीं की गई। नीतीश के समर्थकों को साधे रखने का इसे सीधा प्रयास माना जा रहा है, लेकिन अंदर की खबर है कि भाजपा के एक गुट का मानना है कि लोकसभा चुनाव में बेटिकट होने से बाबा बेहद खफा हैं। इसकी भरपाई वह विधानसभा चुनाव में अपने पुत्र को भाजपा से टिकट दिलाकर करना चाहते हैं। किंतु दिक्कत यह है कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बाबा का रिश्ता छत्तीस का है। इसलिए बाबा सारे विकल्पों को खुला रखना चाहते हैं।

● विपिन कंधारी

लोकतंत्र की गिरती सौदेबाजी

जो रेवड़ियां पहले बांटने वालों और पाने वालों, दोनों को मीठी लगती थीं, वे अब कसैली लगने लगी हैं। मसला राजनीतिक और आर्थिक है। जो रेवड़ी पाते थे, उन्हें लग रहा है कि बांटने का वायदा करने वाले अब अपनी बात से मुकरने के लिए तरह-तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करने लगे हैं। उन्हें ठगे जाने का एहसास हो रहा है। वायदे के बदले वोट तो ले लिए गए लेकिन बांटने का नंबर आने पर छांटा-बीनी, कटौती और देर-दार की जा रही है। रेवड़ियां बांटने वालों की समस्या और भी विकट है। वे इस सवाल का सामना कर रहे हैं कि कहीं उन्हें दोहरे घाटे का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? यह कि बदले में वोट भी पूरे न मिलें, और अर्थव्यवस्था का दिवाला भी निकल जाए।

भारतीय लोकतंत्र में चुनावों के दौरान जनता को लुभाने के लिए की जाने वाली घोषणाएं अब एक परंपरा सी बन गई हैं। हर चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने-अपने घोषणापत्र में मुफ्त योजनाओं की झड़ी लगा देते हैं- कोई कहता है कि हम महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देंगे, कोई युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करता है, तो कोई फ्री बिजली, पानी, बस यात्रा, राशन, गैस सिलेंडर या स्कूटी देने की बात करता है। इन सबका एकमात्र उद्देश्य होता है मतदाताओं को प्रभावित करना और वोट बटोरना। लोकतंत्र में वादों का महत्व है, लेकिन जब ये वादे मुफ्तखोरी की संस्कृति को जन्म दें और सरकार की आर्थिक स्थिति पर बोझ बनें, तब यह चिंता का विषय बन जाता है। देश में लोक-लुभावन वादों का चलन कोई नया नहीं है, लेकिन 2011 के बाद से जब चुनावी राजनीति में मुफ्त योजनाओं का असर स्पष्ट दिखाई देने लगा, तब से इसे रेवड़ियों की राजनीति कहा जाने लगा। इस पर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह देश की आर्थिक रीढ़ को कमजोर करने वाला चलन है, जिससे बचा जाना चाहिए।

तमिलनाडु वह राज्य रहा जहां इस संस्कृति की नींव पड़ी। 2006 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने चुनाव जीतने के बाद मतदाताओं को रंगीन टीवी बांटे। इसके बाद अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) ने अपने शासन में मिक्सी, ग्राइंडर और फ्री लैपटॉप बांटने का अभियान चलाया। धीरे-धीरे यह चलन उत्तर भारत की राजनीति में भी प्रवेश कर गया। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने बिजली-पानी मुफ्त करने, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा देने, मोहल्ला क्लीनिक जैसी योजनाओं को मुख्य मुद्दा बनाया और बहुमत से सत्ता में लौट आई। इसके बाद पंजाब में भी आप ने यही रणनीति अपनाई और सफल रही। उप्र, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी अब मुफ्त योजनाएं किसी भी चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। गुजरात में 2022 के चुनावों में कांग्रेस और आप, दोनों ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया। सवाल यह है कि क्या इससे सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है या केवल मतदाता को लुभाया जाता है? मतदाताओं के लिए यह तय करना कठिन हो गया है कि कौन-सी योजना कल्याणकारी है और कौन-सी केवल राजनीतिक लालच।

अगर इन योजनाओं के असर को जनता के जीवन पर देखें तो यह बहस दो हिस्सों में बंट जाती है। एक पक्ष कहता है कि गरीबों और वंचितों के लिए ये योजनाएं आवश्यक हैं, क्योंकि वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें राहत दे। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली सरकार द्वारा बिजली

वादे किए पर पूरे नहीं हुए

पंजाब में तो आप सरकार ने चुनाव में इस प्रकार का जो वादा किया था, वह आज तक पूरा करने की शुरुआत भी नहीं की गई है। मप्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना, सरकार किसी भी पार्टी की क्यों न हो, हर प्रदेश में कमोबेश ऐसी ही स्थितियां हैं। खास बात यह है कि चुनाव-विश्लेषकों के मुताबिक दिल्ली की महिलाओं के वोट जीतने वाली भाजपा के बजाय हारने वाली आप को अपेक्षाकृत ज्यादा मिले हैं। यानी, वोट तो पूरे मिले नहीं, लेकिन रेवड़ियां किसी न किसी प्रकार पूरी ही बांटनी होंगी। रेवड़ियों के बदले वोटों की गारंटी न होने की बात पार्टियों और नेताओं को 2022 में ही समझ आ गई थी। उप्र भाजपा ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी अपनी चुनाव-समीक्षा रपट में स्वीकार कर लिया था कि रेवड़ी बांटने की स्कीमों के लाभार्थियों ने सरकार की जुबानी तारीफें तो खूब कीं, लेकिन वोट उतने नहीं मिले, जितनी उम्मीद थी। पर उप्र सरकार भी वादे के मुताबिक रेवड़ियां बांटने के लिए मजबूर है। लाभार्थियों की ऐसी दुनिया बनाने का यह विचार किसी भारतीय नेता या पार्टी की देन न होकर अमेरिका में बैठे उन बाजारवादी अर्थशास्त्रियों के दिमाग की उपज है, जिन्होंने नई सदी के शुरुआती सालों में ही यह सोचना शुरू कर दिया था कि नव-उदारवादी सरकारों को लोगों की नाराजगी से कैसे बचाया जा सकता है।

और पानी पर दी गई सब्सिडी से लगभग 80 प्रतिशत उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है। इसी तरह केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले। लेकिन दूसरी तरफ यह भी तर्क दिया जाता है कि यदि हर चुनाव में केवल मुफ्त की वस्तुएं देकर वोट बटोरे जाएंगे, तो जनता अपनी समस्याओं की गंभीरता को समझना छोड़ देगी और एक उपभोक्ता भर बनकर रह जाएगी। साथ ही यह आदत आत्मनिर्भरता की भावना को भी कमजोर करती है। जब हर चीज सरकार से मुफ्त मिलने लगे, तो मेहनत, उद्यम और स्वयं प्रयास की भावना समाज में घटने लगती है। यह स्थिति लोकतंत्र के स्वस्थ विकास के लिए खतरनाक मानी जाती है।

मुफ्त योजनाओं का असर केवल समाज पर ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा पड़ता है। किसी भी योजना के लिए बजट की आवश्यकता होती है, और अगर राज्य सरकारें अपने राजस्व से अधिक मुफ्त योजनाओं में खर्च करेंगी, तो उन्हें कर्ज लेना पड़ेगा। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उप्र और बिहार जैसे राज्यों का कुल ऋण जीएसडीपी (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद) के 40 प्रतिशत से भी अधिक हो चुका है, जो चिंताजनक है। पंजाब में 2023 तक राज्य सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था, जबकि राज्य की आमदनी उसका आधा भी नहीं थी। यह स्थिति केवल जनता को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी आर्थिक बोझ में धकेल देती है। जब सरकारें मुफ्त की घोषणाएं कर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च कर देती हैं, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश कम हो जाता है। भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने भी इस पर चिंता जताई है कि कुछ राज्य अपने बजट का 40 प्रतिशत तक मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं। यह राजकोषीय अनुशासन के विरुद्ध है और दीर्घकालिक विकास के लिए खतरनाक संकेत है।

इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करते हुए 2022 में कहा था कि मुफ्त रेवड़ियों की संस्कृति लोकतंत्र को क्षति पहुंचा सकती है और इसके लिए स्पष्ट नीति की आवश्यकता है। अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को इस पर दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए ताकि मतदाताओं को भ्रमित करने वाली घोषणाओं पर लगाम लग सके। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। आयोग का तर्क है कि वह केवल आदर्श आचार संहिता को देख सकता है, और वादों पर रोक लगाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके चलते राजनीतिक दलों को पूरी छूट मिल जाती है कि वे जो चाहें, वादा कर सकते हैं। चुनाव आयोग की इस निष्क्रियता को लेकर जनहित याचिकाएं भी दाखिल हुईं, परंतु अब तक कोई सख्त नीति सामने नहीं आई है। इसके साथ ही, मुख्यधारा की मीडिया भी इस विषय पर बहुत अधिक सवाल नहीं उठाती, क्योंकि मुफ्त योजनाएं जनता के बीच लोकप्रिय होती हैं और विरोध करने वाले राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहते।

इस पूरी बहस का निष्कर्ष यही है कि जनता को मुफ्त चीजों की नहीं, बल्कि सस्ती, टिकाऊ और न्यायोचित योजनाओं की आवश्यकता है। कल्याणकारी योजनाओं में और लोकलुभावन वादों में फर्क किया जाना चाहिए। अगर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवेलपमेंट और रोजगार पर निवेश करे तो जनता खुद सक्षम बन सकती है। लंबे समय तक मुफ्त बांटना न तो विकास की गारंटी है और न ही गरीबी मिटाने का तरीका।

● इन्द्र कुमार

राज्यों में फ्रीबीज स्कीम

दिल्ली

- हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली
- 20 हजार लीटर पानी हर महीने फ्री
- सीनियर सिटीजन को मुफ्त तीर्थयात्रा
- महिलाओं के लिए फ्री बस सफर
- फ्री वाई-फाई की सुविधा

महाराष्ट्र

- महिलाओं को 2100 रुपए महीने नकद
- 2027 तक 50 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
- किसानों का कर्ज माफ
- किसान सम्मान योजना में सालाना 15000 रुपए

मध्य प्रदेश

- लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए महीने
- फ्री स्कूटी योजना
- हर महीने 100 यूनिट तक बिजली सिर्फ 100 रुपए में
- 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना

हिमाचल

- महिलाओं को 1500 रुपए महीने
- 125 यूनिट मुफ्त बिजली
- पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा

पंजाब

- 300 यूनिट मुफ्त बिजली

राजस्थान

- किसान सम्मान निधि 12,000 करने का वादा
- 12वीं पास मेधावी लड़कियों को स्कूटी

छत्तीसगढ़

- महतारी वंदन स्कीम के तहत सालाना 12,000
- किसानों को सालभर में 10,000 रुपए मिलेंगे
- गरीब परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर

कर्नाटक

- शक्ति गारंटी योजना सरकारी स्वामित्व वाली गैर-लक्जरी बसों में महिलाएं मुफ्त बस यात्रा
- गृह लक्ष्मी योजना के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए

तमिलनाडु

- महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा
- परिवार की महिला मुखिया को हर माह 1,000 रुपए नकद

सिमटते आधार से घबराए माओवादी

हाल में माओवादियों की उच्च स्तरीय केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय (छद्म नाम) ने एक प्रेस नोट जारी कर सरकार को शांतिवार्ता के लिए अनुरोध किया। अभय ने वार्ता के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के साथ-साथ नए सुरक्षा कैंप स्थापित न करने और सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान बंद करने की शर्तें रखी हैं। इसके जवाब में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार माओवादियों से बातचीत कर सकती है, परंतु कोई शर्त मान्य नहीं होगी।

वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि माओवादी हथियार छोड़ दें, क्योंकि जब कोई भी माओवादी मारा जाता है तो किसी को खुशी नहीं होती। माओवादियों ने शांति-वार्ता की पेशकश अवश्य की है, परंतु हथियार छोड़ने के संबंध में कुछ नहीं कहा है। दरअसल माओवादी सुरक्षा बलों के हाथों लगातार मात खाने के बाद और नुकसान नहीं होना देना चाहते। माओवादियों ने हाल में अपने सदस्यों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए थे ताकि वे पुलिस के चंगुल में न फंसें। जहां तक पूर्व में शांति के पक्ष में किए गए प्रयासों का प्रश्न है, तो सरकारों का अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा। वर्ष 2002 में भी नक्सलियों ने आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के समक्ष एक माह के लिए हिंसा छोड़ने और शांति-वार्ता का प्रस्ताव रखा तो वह आगे इसलिए नहीं बढ़ सका, क्योंकि तब नक्सली हथियार छोड़ने को तैयार नहीं थे। वार्ता की आड़ में नक्सल विचारधारा की मुख्य दो पार्टियां सीपीआई (एमएल) पीपुल्स वार और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया मिलकर सीपीआई (माओवादी) पार्टी बनाने में व्यस्त थीं। 2004 में इन दो पार्टियों का विलय हो गया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि बातचीत का समय नक्सलियों ने अपने राजनीतिक एजेंडे को प्रसारित करने के लिए उपयोग किया था। शांति-वार्ता का अगला प्रयास तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम द्वारा मई 2010 में किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश के माध्यम से माओवादियों के नाम गृहमंत्री ने एक पत्र लिखकर माओवादियों को 72 घंटे के लिए हिंसा रोकने के लिए अनुरोध किया, ताकि वार्ता के लिए माहौल तैयार किया जा सके, परंतु उसी दौरान एक जुलाई, 2010 को माओवादियों की केंद्रीय कमेटी के सदस्य आजाद की आंध्र प्रदेश पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो जाने के बाद बातचीत के प्रयास वहीं रुक गए।

वर्ष 2011 के बाद से माओवादी खुद यह मानते आए हैं कि उनका जन-आधार लगातार घट रहा है। सुरक्षाबल नए-नए कैंप और पुलिस थाने स्थापित कर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। माओवादियों की पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी की कई कंपनियां कमजोर होकर प्लाटून के आकार में बदल गई हैं। दिसंबर 2020 में जब माओवादियों की केंद्रीय कमेटी ने अपने संगठन की समीक्षा की तो पाया कि पूरे देश में वे पीछे-हटने की स्थिति में हैं। अपनी तथाकथित क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए माओवादियों की केंद्रीय कमेटी ने तब कुछ निर्णय लिए, परंतु वे अपना नुकसान होना नहीं रोक पाए और लगातार कमजोर होते गए। वर्ष 2024-25 में अब तक 330 से अधिक माओवादी मारे जा चुके हैं जिसमें कई बड़े लीडर भी हैं। वर्ष 2024 में केंद्र सरकार ने जब राज्य सरकारों से मिलकर मार्च 2026 तक माओवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा, नए कैंप स्थापित करके माओवादियों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया तो ऐसी स्थिति में माओवादियों ने अब फिर शांति-वार्ता का प्रस्ताव रखा है। माओवादी स्थायी समाधान के लिए हथियार छोड़ने को तैयार हैं अथवा नहीं, यह स्पष्ट नहीं किया है। पुराने अनुभवों से तो केवल यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि बिना हथियार छोड़ने की शर्त पर बातचीत का रास्ता अपनाया जाता है तो माओवादी इस अवधि में केवल अपने आप को संगठित करने और अपने नेतृत्व को बचाने का प्रयास करेंगे। हजारों सुरक्षाकर्मियों ने इस लड़ाई में अपने प्राण न्योछावर किए हैं। माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण भी लगातार बढ़ रहा है। निचले स्तर के माओवादी यह समझ चुके हैं कि वे सरकार के खिलाफ यह लड़ाई नहीं जीत सकते। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर विकास की कई योजनाएं लागू कर रही हैं ताकि आदिवासियों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल में नियद-नेल्लानार (आपका अपना सुंदर गांव) योजना लागू की है जिसके अंतर्गत सुरक्षा कैंप के चारों ओर के गांव में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान किया जाना है।

दूरगामी इलाकों में सड़कें बन रही हैं, मोबाइल टावर लग रहे हैं, बैंक एवं पोस्ट ऑफिस की शाखाएं खुल रही हैं। सरकार ने माओवाद-मुक्त पंचायत में एक करोड़ रुपए के विकास कार्य करने की घोषणा की है। इसलिए अब जरूरी है कि माओवादी यह स्पष्ट करें कि क्या वे स्थायी समाधान के लिए हथियार छोड़ने को तैयार हैं? अर्थात् क्या वे सशस्त्र क्रांति का रास्ता त्यागने के लिए तैयार हैं? यदि माओवादी हथियार छोड़ने को तैयार नहीं होते तो उनकी मंशा स्पष्ट हो जाएगी कि वे केवल कुछ समय की मोहलत चाहते हैं, ताकि निचले स्तर के माओवादी पार्टी छोड़कर न जाएं, बड़े लीडर सुरक्षित किए जा सकें और उनको पुन: संगठित होने का कुछ समय मिल सके। यदि माओवादियों की मंशा ऐसी है तो सरकार को बातचीत का रास्ता अपनाने से बचना चाहिए।

● रायपुर से टीपी सिंह

बदले गए हालात, अब नहीं जारी होता है फरमान

गत वर्षों में छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के इलाकों में माओवादियों के खिलाफ रणनीति के तहत काम हुआ है। माओवादियों के प्रभाव वाले इलाकों में पुलिस कैंप बनाए गए हैं, जिससे ग्रामीण अब अपनी समस्याएं लेकर पुलिस के पास पहुंचने लगे हैं। पुलिस और सुरक्षाबलों के आने के बाद माओवादियों को इलाका छोड़ना पड़ा और अब वे अपनी अदालत भी नहीं लगा पा रहे हैं। पहले माओवादी सबसे ज्यादा जन अदालत लगाते थे। अब इन इलाकों में 70 से ज्यादा पुलिस कैंप लग चुके हैं। जिन जगहों पर माओवादी जन अदालत लगाते थे, वहां अब पुलिस कैंप मौजूद हैं। पलामू के डगरा, पथरा, बूढ़ापहाड़ के झालूडेरा, मंडल, कुल्ही, बहेराटोली, नावाटोली, नावाडीह जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा जन अदालतें लगती थीं। जिन जगहों पर पहले जन अदालत लगती थीं, वहां अब पुलिस कैंप हैं। हालात बदल गए हैं। पिछले एक दशक में नक्सलियों के खिलाफ कई कार्रवाईयां हुई हैं। ग्रामीणों का पूरे सिस्टम पर भरोसा बढ़ा है और अब जन अदालत जैसी कोई चीज नहीं है। पुलिस हर चीज पर नजर रख रही है और अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पहले जन अदालत लगती थी, लेकिन अब विकास कार्य हो रहे हैं और इलाके में बड़े बदलाव हुए हैं। अब ग्रामीण इलाकों में बाजार लगने लगे हैं और प्रशासनिक अधिकारी आम ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं।

तैयार हो रही नई चुनावी पिच

शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की उंगली पकड़कर राज ठाकरे राजनीति में आए थे। राज ठाकरे को एक समय बालासाहेब के सियासी वारिस के तौर पर भी देखा जा रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे के सक्रिय होने के बाद राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नाम से अपनी पार्टी बनाने के बाद राज ठाकरे को मिली सियासी सफलता पानी के बुलबुले जैसी रही। मनसे 2014 और 2019 के चुनाव में सिर्फ एक सीट पर जीत सकी और 2024 में तो खाता भी नहीं खुल सका। महाराष्ट्र की सियासत में पूरी तरह से फेल हो चुके राज ठाकरे अपनी पार्टी के सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। इसके बाद भी जब-जब राज ठाकरे की मुलाकात किसी अन्य पार्टी के नेता से होती है तो महाराष्ट्र की सियासी तपिश बढ़ा देती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे से मिलना हो या फिर एकनाथ शिंदे से हुई मुलाकात। आखिर राज ठाकरे से होने वाली सियासी मुलाकात महाराष्ट्र की राजनीति में क्यों अहम बन जाती है? उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से दादर स्थित उनके आवास शिवतीर्थ पर मुलाकात की। 2024 विधानसभा चुनाव के बाद शिंदे की राज ठाकरे से पहली मुलाकात थी। शिंदे ने कहा कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के निमंत्रण पर उनके निवास पर भोजन किया और अनौपचारिक चर्चा की। इस दौरान दोनों ही पार्टियों के नेता मौजूद रहे। राज ठाकरे से मुलाकात को शिंदे ने शिष्टाचार भेंट बताते हुए कहा कि हम दोनों बालासाहेब ठाकरे के समय से एक साथ मिलकर काम करते रहे हैं। हम कुछ वजहों से नहीं मिल सके थे। आप इसका कारण जानते हैं। मगर अब हम कभी भी मिलकर बात कर सकते हैं।

एकनाथ शिंदे भले ही राज ठाकरे से अपनी मुलाकात को औपचारिक बता रहे हैं और सियासी मायने ना निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में जब भी जो नेता मिलते हैं तो उसका सियासी मकसद होता है। राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मुलाकात अहम इसीलिए भी है, क्योंकि इस साल बीएमसी चुनाव होने हैं। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ शिंदे ने अपने नेता सदा सर्वणकर को चुनाव मैदान में उतारा दिया था और उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी महेश सांवत जीतने में कामयाब रहे और अमित ठाकरे को शिकस्त मिली। अमित ठाकरे की चुनावी हार ने राज ठाकरे की राजनीति के लिए बड़ा झटका दिया था। इसीलिए चुनाव नतीजों के बाद सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच अनबन हो गई है। ऐसा कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे की तरफ से माहिम सीट पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार वापस नहीं लिए जाने से राज ठाकरे नाराज हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे से मुलाकात को सारे-गिले शिकवे को दूर करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। राज ठाकरे और शिंदे की मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच गठबंधन की बात भी कही जाने लगी है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच करीब चार बार मुलाकात हुई है। हालांकि, ये मुलाकातें परिवारिक कार्यक्रम या फिर किसी प्राइवेट माहौल में हुई है, लेकिन उसके सियासी मायने निकाले जाने लगे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से सूबे की सियासत बदल गई है। विधानसभा चुनाव के बाद से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की सियासत पर संकट मंडराने लगा है। शिवसेना की असली बनाम नकली की लड़ाई को एकनाथ शिंदे जीतने में सफल रहे हैं, जिसके चलते उद्धव ठाकरे के लिए अपनी राजनीति को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अपनी सीट नहीं बचा सके, तो मनसे अपना खाता तक नहीं खोल सकी है। इस तरह बालासाहेब ठाकरे के सियासी वारिस माने जाने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की राजनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ठाकरे बंधुओं की मुलाकात को सियासी नजरिए से भी देखा गया और दोनों के साथ आने के भी कयास लगाए जाने लगे। वहीं, महाराष्ट्र की सत्ता की कमान संभालने के बाद से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच कई मुलाकातें हो चुकी हैं। फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात उस समय की थी, जब एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन फडणवीस ने कहा था कि यह मुलाकात सिर्फ मैत्रिपूर्ण थी। राज ठाकरे करीबी दोस्त हैं, इसलिए उनके घर ब्रेकफास्ट और अच्छी बाते हुईं। इसका सियासी अर्थ ना निकाला जाए। राज ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात को बीएमसी चुनाव में भाजपा और मनसे के गठबंधन से जोड़कर देखा गया।

● **बिन्दु माथुर**

असल लड़ाई बीएमसी के कब्जे की है

विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें मुंबई के बीएमसी के चुनाव पर है। भाजपा ने महाराष्ट्र की सत्ता अपने नाम करने के बाद अब मुंबई में अपना राजनीतिक दबदबे को बनाने की कवायद है। बीएमसी पर फिलहाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) का प्रभाव है, जिसे सिर्फ कमजोर करने की नहीं बल्कि उसे अपने नाम करने की कवायद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। बदले हुए सियासी समीकरण के बीच उद्धव ठाकरे के लिए अपने आखिरी किले बीएमसी को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना राज ठाकरे की मनसे के साथ हाथ मिलाकर बीएमसी पर अपना दबदबा बनाए रखने का दांव माना जा रहा है। वहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना फिलहाल भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल है। पिछली महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे जबकि चुनाव बाद बनी नई सरकार में उन्हें उपमुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा है। भाजपा के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। ऐसे में शिंदे अपनी शिवसेना को बीएमसी की सत्ता में लाना चाहते हैं, ताकि मुख्यमंत्री नहीं बनाने की निराशा को कम कर सकें। ऐसे में राज ठाकरे के साथ शिंदे की मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में देखना है कि राज ठाकरे क्या सियासी दांव चलते हैं?

पानी नहीं तो दुल्हन नहीं

राजस्थान के गांवों में कुंवारे बैठे हैं लड़के

पानी की समस्या की वजह से जाट बाहुल्य वाले इन गांवों में कुंवारे लड़कों की शादी नहीं हो रही है। कोई भी इन इलाकों में अपनी बेटी ब्याहने को तैयार नहीं है। शादी न होने और पानी की कमी से परेशान जाट युवकों ने प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। अलवर जिले के भरतपुर और ढोलपुर गांवों में पानी की दिक्कत की वजह से लड़कों की शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि कोई भी इन गांवों में अपनी बेटी नहीं भेजना चाहता। ऐसे हालात से परेशान होकर इलाके के जाट नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखकर इलाके के 30 से 40 गांवों में पास की नदियों और गुड़गांव नहर से पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा है। पानी की समस्या से जूझ रहे 40 गांवों के करीब 3,500 से 4,500 युवा कुंवारे बैठे हैं क्योंकि कोई उन इलाकों में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता जहां पानी की कमी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास के लगभग सभी पानी के स्रोत सूख चुके हैं। भरतपुर जिला परिषद के सदस्य नेम सिंह फौजदार ने बताया कि पानी की कमी से न केवल खेती पर असर हुआ है, बल्कि इसके चलते कई लोग अपनी बेटियों की शादी इन जिलों के बाहर और कई तो अन्य राज्यों में करना चाहते हैं। ऐसे में लड़के कुंवारे बैठे हैं।

जल ही जीवन है यह स्लोगन बताता है कि जीवन जीने के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है। इसी जीवन को पाने के लिए राजस्थान का एक गांव तरस रहा है।

पहाड़ी पर बसे गांव के लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए पैदल 2 किलोमीटर नीचे तक आना पड़ता है। गांव की महिलाओं की उम्र पानी का इंतजाम करने में गुजरती जा रही है। अब आलम यह है कि गांव के युवाओं को दुल्हन मिलना दूभर हो रहा है। कोई भी अपनी बेटी को इस गांव में ब्याहना नहीं चाहता। यह अभागा गांव राजस्थान के चेरापूंजी और सो टापुओं के शहर के नाम से मशहूर बांसवाड़ा में है। गांव का नाम है कुंडल और दुर्भाग्य की बात यह है कि माही नदी की अथाह जलराशि के बावजूद छोटी सरवन उपखंड में पानी की भयंकर किल्लत है, जिससे गांववालों की जिंदगी नरक बन गई है। तपती गर्मी में गांव की 300 की आबादी पानी की दो बूंद के लिए 1-2 किलोमीटर का सफर तय करती है।

पानी की इस कमी ने गांव में सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया है, जहां लोग अपनी बेटियों की शादी कुंडल गांव में करने से कतराते हैं। गांव के पढ़े-लिखे युवाओं का कहना है कि पानी की किल्लत के कारण उनकी शादी तक अटक गई है। एक ग्रेजुएट युवक ने बताया जब कोई रिश्ता लेकर आता है, तो पानी की समस्या देखकर लोग बेटी की शादी से इनकार कर देते हैं। 70 घरों वाले इस गांव में सिर्फ एक हैंडपंप है, जहां पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। यह हैंडपंप न केवल 300 लोगों की प्यास बुझाता है, बल्कि सैकड़ों मवेशी भी इसी पर निर्भर हैं। ऊंची पहाड़ी पर बसे इस गांव में गर्मी शुरू होते ही जलाशय सूख जाते हैं। कुएं और नदियां तो पूरी तरह सूख चुकी हैं और अधिकांश हैंडपंप खराब पड़े हैं। हर घर नल योजना केवल कागजों तक सिमट कर रह गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर पीएचईडी विभाग को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। पानी की तलाश में पहाड़ी से उतरकर 1-2 किलोमीटर का सफर करने वाली महिलाओं ने नेताओं और सरकारी सिस्टम की पोल खोल दी है।

ग्रामीणों का कहना है कि नेता सिर्फ वोट लेने चुनाव में आते हैं, बाद में हमारी सुध लेने कोई नहीं आता। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि पंचायती राज चुनाव में नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे। गर्मी के दिनों में जलाशयों के सूख जाने के बाद ग्रामीण दूर-दराज से पानी लाकर ड्रम में भरते हैं और उसे ताला लगाकर रखते हैं। महिलाएं ड्रम में इकट्ठा किए इस पानी को पीने, खाना बनाने और नहाने के लिए कई दिनों तक इस्तेमाल में लेती हैं। गांव की महिलाओं और युवाओं ने सरकार से तत्काल शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की मांग की है। गांव में देखा गया कि पानी के लिए तपती गर्मी में घंटों इंतजार करती महिलाओं का गुस्सा साफ झलक रहा था। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार को हमारी सुध लेनी चाहिए और पानी की समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए।

राजस्थान में पेयजल की दरों में वृद्धि का अतिरिक्त भार जनता पर नहीं डालने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पेयजल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। अब पेयजल उपभोक्ताओं से वर्तमान लागू दरों पर ही पानी के बिलों एवं अन्य सेवाओं की राशि वसूल की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में शेष राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है इससे सरकार पर लगभग 2100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त भार आएगा। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने बताया कि विभाग के माध्यम से आम जनता को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साल 2017 से लागू पानी की दरों में राज्य सरकार द्वारा वृद्धि नहीं की गई है। वर्ष 2017 से अब तक पेयजल संरचनात्मक ढांचे तथा पेयजल वितरण प्रणाली, संचालन, संधारण एवं रखरखाव लागत में लगभग चार से पांच गुणा वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में प्रचलित दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय किया था परंतु वर्ष 2017 के बाद एकबार भी दरों को बढ़ाया नहीं गया, परिणामस्वरूप टैरिफ से प्राप्त होने वाला राजस्व, रखरखाव व संधारण के खर्चों का बहुत कम हिस्सा ही है। इसके कारण जल वितरण संबंधी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में कमी आकर, उसके कार्यशीलता पर भी कुप्रभाव पड़ता है। जलदाय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पेयजल की दरों को वास्तविक लागत के आधार पर तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। इस कारण पानी की वर्तमान दरों को चार गुणा करने की सहमति वित्त विभाग से प्राप्त होने पर दरों में वृद्धि की जा रही है। उसके बावजूद भी राज्य की जनता पर अतिरिक्त भार नहीं डालने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जनहित में निर्णय लिया गया है कि पेयजल उपभोक्ताओं से वर्तमान लागू दरों पर ही पानी के बिलों एवं अन्य सेवाओं की राशि वसूल की जाएगी।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

सपा की दलित पॉलिटिक्स से बहनजी बेचैन?

उप्र में दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी गोटियां सेट की जाने लगी है। बसपा प्रमुख मायावती अपने सियासी वजूद और अपने वोटों को बचाए रखने की चुनौती से जूझ रही हैं। बसपा के बिखरते दलित वोटबैंक को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव साधकर अपनी सियासी नैया पार लगाना चाहते हैं। रामजीलाल के साथ खड़े होने का मामला हो या फिर इंद्रजीत सरोज के बयान, इसे सपा के दलित वोट जोड़ने के नजरिए से देखा जा रहा है। सपा की दलित पॉलिटिक्स से मायावती बेचैन नजर आ रही हैं। ऐसे में मायावती दलित समाज के साथ मुस्लिमों को भी सपा से दूर रहने की नसीहत दे रही हैं। सपा के सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर सियासत गरमा गई है। करणी सेना ने रामजीलाल सुमन के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना रखा है और आगरा में ठाकुर समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सीधे चुनौती दे दी है। सपा ने रामजीलाल के पक्ष में खड़े होकर पूरे मामले को दलित बनाम ठाकुर का रंग देने की कोशिश की है। अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा पहुंचे, जहां रामजीलाल सुमन के आवास पर जाकर मुलाकात की और दलित समाज को सियासी संदेश दिया। अखिलेश के आगरा दौरे से पहले मायावती ने सपा की दलित राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए थे।

बसपा प्रमुख मायावती ने गत दिनों ट्वीट कर सपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह सपा भी अपने दलित नेताओं को आगे करके तनाव और हिंसा का माहौल पैदा करने वाले बयान दिलवा रही है, जिस पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ये संक्रीण और स्वार्थ की राजनीति है। सपा भी दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है। दलितों के साथ-साथ ओबीसी और मुस्लिम समाज आदि को इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर, इन्हें इस पार्टी की राजनीतिक हथकंडों के बचना चाहिए। मायावती ने आगे कहा कि ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलित नेताओं को दूसरों के इतिहास पर टीका-टिप्पणी करने की बजाय यदि वे अपने समाज के संतों, गुरुओं और महापुरुषों की अच्छाईयों एवं उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो यह उचित होगा, जिनके कारण ये लोग किसी लायक बने हैं। इस तरह से मायावती दलित समाज को सपा के दलित नेताओं के बहकावे में आने से बचने की नसीहत दे रही हैं। साथ ही मुस्लिम और ओबीसी को भी सपा से दूर रहने की अपील कर रही हैं।

2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश अपने पीडीए के दांव से 37 सीटें जीतने में कामयाब रहे। सपा ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाली राजनीति से ही 2027 का चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। अखिलेश की नजर पीडीए राजनीति को और मजबूत करने की है, जिसके लिए उनकी नजर मायावती के वोटरों पर है। अखिलेश यादव दो तरह से इस मिशन में जुटे हैं। सपा में दलित समाज के नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। अखिलेश अपने आसपास अब यादव और मुस्लिम नेताओं को रखने के बजाय दलित नेताओं को साथ लेकर चलते हैं। इसी कड़ी में सपा ने बसपा के पुराने नेता दद्दू प्रसाद को अपने साथ मिलाया है। राणा सांगा पर बयान के बाद सपा के दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर करणी सेना ने हमला किया तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने सुमन के समर्थन में आसमान सिर पर उठा लिया। रामजीलाल सुमन के खिलाफ करणी सेना ने आगरा में एकजुट होकर अपनी ताकत की हुंकार भरी तो अखिलेश ने भी आगरा जाकर रामजीलाल सुमन से मुलाकात करने का प्लान बना लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव राणा सांगा को गद्दार कहने वाले रामजीलाल सुमन से मिलने आगरा पहुंचे। उन्होंने सपा सांसद का हाल-चाल जाना। इसके बाद कहा- मैं दलित सांसद रामजीलाल सुमन के साथ खड़ा हूं। मुझे धमकी मिल रही है कि जैसे फूलन देवी को मारा वैसे तुम्हें मारेंगे, आखिरकार इनके पीछे कौन हैं? सपा प्रमुख ने कहा- आगरा में जो तथाकथित शक्ति प्रदर्शन हुआ, उसमें तलवारें लहराई गईं। आरोपियों को कार्रवाई का डर नहीं है। रामजीलाल सुमन के घर तोड़फोड़ की गई। यह हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि साजिश के तहत किया गया।

वहीं रामजीलाल सुमन ने करणी सेना को चेतावनी ही दे दी है कि मैदान तैयार है, दो-दो हाथ हो जाएं। सपा के दलित विधायक इंद्रजीत सरोज ने मंदिर और देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया था। इंद्रजीत सरोज के बयान का अखिलेश ने समर्थन नहीं किया, लेकिन रामजीलाल सुमन के साथ मजबूती से खड़े है। दलित वोटों के लिहाज से सपा रामजीलाल के साथ खड़े होना अपने लिए मुफीद मान रही है।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

अखिलेश की पीडीए रणनीति पर वार

अखिलेश यादव का फोकस अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को और भी मजबूत करने पर है। सपा की इस रणनीति को मायावती बखूबी समझती हैं और उन्हें लग रहा है कि दलित वोट अगर खिसक गया तो 2027 के चुनाव में 2022 और 2024 वाला हश्र न हो जाए। इतना ही नहीं दलितों के बीच चंद्रशेखर आजाद तेजी से अपने सियासी पैर पसारते जा रहे हैं, जिससे दलित युवाओं का झुकाव भी तेजी से हो रहा है। कांग्रेस की नजर भी दलित समुदाय के वोट बैंक पर है। कांग्रेस ने गुजरात के अहमदाबाद अधिवेशन में दलित-आदिवासी और पिछड़ों को लेकर अपने प्रस्ताव पारित किए हैं और सामाजिक न्याय के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। सपा से लेकर कांग्रेस तक के दलित वोट बैंक पर फोकस किए जाने के चलते मायावती असहज महसूस कर रही हैं। मायावती जानती हैं कि अगर सपा की आक्रामक राजनीति से जाटव वोट भी उनके हाथों से निकल गया तो फिर 2027 में बसपा के सियासी वजूद को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। सपा की आक्रामक सियासत को काउंटर करने के लिए मायावती को फ्रंटफुट पर आना पड़ा है। इसी के मद्देनजर आकाश आनंद की बसपा में पहले वापसी की स्क्रिप्ट लिखी गई है ताकि युवा दलितों को साधकर रखा जा सके। अब मायावती खुद दलित के साथ-साथ ओबीसी और मुस्लिमों को सपा से दूर रहने की नसीहत दे रही हैं। इतना ही नहीं सपा के दलित नेताओं को भी सियासी पाठ पढ़ा रही हैं।

फॉर्मूला 70... कौन देगा कुर्बानी?

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सबसे बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव विपक्ष को एकजुट करने में जुट गए हैं। इसके लिए पहले दिल्ली और पटना में बैठक हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक का वीडियो पोस्ट कर कहा कि तेजस्वी यादव से मुलाकात कर महागठबंधन की मजबूती पर चर्चा की। बिहार की जनता को हम एक सशक्त, सकारात्मक, न्यायप्रिय और कल्याणकारी विकल्प देंगे। दो पुराने सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं की ये बैठक ऐसे समय हुई है, जब रिश्ते उतने सहज नहीं दिख रहे।

बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ने के साथ-साथ राजनीतिक दलों के बीच शह-मात का खेल शुरू हो गया है। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की एक के बाद एक बैठक हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ है। दिल्ली के बाद पटना में हुई बैठक में महागठबंधन को पशुपति पारस के रूप में नया साथ मिल गया है, तो मुकेश सहनी मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एकता और स्पष्टता के साथ चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बिहार की जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि, मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर अल्लावरु गोल-मोल जवाब देते नजर आए और तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगाई। हां एक बात जरूर कही कि तेजस्वी यादव के अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। वहीं, मुख्यमंत्री फेस पर सहमति नहीं बनने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में कोई चिंता नहीं है। चिंता एनडीए गठबंधन के लोगों को होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर उन्होंने कहा कि एक ही दिन में सब कुछ घोषणा नहीं होगी, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया कि महागठबंधन के सभी दल एक साथ हैं और जो भी होगा, सब मिलकर साझा करेंगे।

बिहार में नैसर्गिक रूप से लालू यादव की अगुवाई वाले आरजेडी को कांग्रेस का बड़ा भाई माना जाता है। 1999 से अब तक विधानसभा चुनाव देखें तो ऐसा ही है भी, लेकिन कांग्रेस नेताओं के हालिया बयान सहज संबंधों की असहजता बयान करते हैं। बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद कृष्णा अल्लावरु यह साफ कह चुके हैं कि पार्टी यहां अब किसी की बी टीम बनकर नहीं रहेगी। वह प्रभारी बनाए जाने के बाद कई बार पटना पहुंचे, लेकिन लालू यादव से औपचारिक मुलाकात से भी परहेज किया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी बुलाया गया तो वहीं कन्हैया कुमार की पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा में खुद राहुल गांधी शामिल हुए। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, इन दोनों ही नेताओं को लेकर ये कहा जाता है कि इन्हें लालू यादव पसंद नहीं करते। कन्हैया की यात्रा के समापन के मौके पर पटना पहुंचे कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने यह कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यह महागठबंधन को जनादेश मिलने पर घटक दलों के नेता बैठकर तय करेंगे।

आरजेडी पहले ही यह साफ कर चुकी है कि उसका मुख्यमंत्री फेस तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनानी है। ऐसे में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की बढ़ी सक्रियता, अल्लावरु और सचिन पायलट के बयान से बड़े भाई का सवाल और गहरा हो गया है। कांग्रेस की कोशिश अब यह संदेश देने की है कि लालू यादव की पार्टी महागठबंधन की इकलौती ड्राइविंग फोर्स नहीं है। दोनों दलों के नेताओं के बीच चल रही परसेप्शन की लड़ाई के बीच शीर्ष नेताओं की बैठक में बात चुनावी रणनीति को लेकर भी हुई। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग महागठबंधन के लिए सिरदर्द बनता दिख रहा है। हर दल अपने मन की मुराद पूरी करने पर अडिग रह सहयोगियों से कुर्बानी चाह रहा है। कांग्रेस की कोशिश है कि सीटों की संख्या अधिक नहीं तो 2020 के विधानसभा चुनाव से कम भी न हो। कांग्रेस का फोकस इस बार अधिक से अधिक ऐसी सीटें हासिल करने पर है जहां पार्टी मजबूत स्थिति में है या जीतने की संभावनाएं भी हैं। कांग्रेस पिछली बार की तरह महज संख्या गिनाने के लिए ऐसी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती जो भाजपा और उसके सहयोगी दलों का गढ़ मानी जाती हैं।

2020 में कांग्रेस को मिली 70 में से 45 सीटें ऐसी थीं जिन्हें भाजपा या जेडीयू का गढ़ माना जाता है। इन सीटों पर हाथ का पंजा चुनाव निशान वाली पार्टी तीन या इससे अधिक चुनावों से नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस इस बार इस तरह की परिस्थितियों से बचने, अपनी जीत की मजबूत संभावना वाली सीटें चाहती है। वहीं, आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस और अन्य सहयोगियों को कम से कम सीटों पर सहमत कर अधिक से अधिक सीटों पर लालटेन निशान वाले उम्मीदवार उतारें।

● विनोद बक्सरी

पिछले चुनाव में क्या था फॉर्मूला

हर चुनाव में सीट शेयरिंग के लिए सियासी दल पिछले चुनाव को आधार के तौर पर लेते हैं। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग की बात करें तो साल 2020 के चुनाव में आरजेडी ने महागठबंधन में सबसे अधिक 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के हिस्से 70 सीटें आई थीं। लेफ्ट को 29 सीटें मिली थीं। इस बार के चुनाव में अगर पशुपति पारस की पार्टी भी महागठबंधन के साथ आती है तो आरजेडी के सामने वीआईपी के साथ आरएलजेपी को भी एडजस्ट करने की चुनौती होगी। विपक्षी आरजेडी भी यह समझ रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मिथिला में एनडीए को पटखनी देना जरूरी है। जेडीयू का खेल बिगाड़ने के लिए विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने मिथिलांचल राज्य का दांव चल दिया है। विधान परिषद में राबड़ी ने अलग मिथिलांचल राज्य की मांग की थी। 100 साल से भी अधिक पुरानी इस मांग को स्वर देकर राबड़ी देवी ने मिथिलांचल की भावनात्मक रग पर हाथ रख दिया है। आरजेडी को चुनाव में इसका कितना लाभ मिलेगा, किसकी सियासी गोटी सेट होगी? ये देखने वाली बात होगी।

चालबाज निकले यूनुस...

भारत और पाकिस्तान में लगातार बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश ने ऐसा कदम उठाया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान की यात्रा से फिलहाल बचना चाहिए। हालांकि औपचारिक तौर पर कोई यात्रा चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन सलाह दी गई है कि बेहद जरूरी न हो तो इन देशों की यात्रा से परहेज किया जाए। तौहीद हुसैन का यह बयान ऐसे समय आया है जब कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच भारी गोलाबारी चल रही है और दोनों देशों के रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं।

कुछ दिन ही पहले यूनुस चीन में जाकर भारत के खिलाफ बोल रहे थे। शेख हसीना के भारत में होने से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से उसके अच्छे रिश्ते नहीं बन सके। वहीं, यूनुस पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। इस दौरान यूनुस पाकिस्तान की केमिस्ट्री की भी चर्चा होने लगी थी। लेकिन पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए। ऐसे में जब यूनुस को अपने दोस्त के साथ खड़ा होना चाहिए, तो उन्होंने उसे भी भारत की तरह ट्रीट किया। यानी अपने नागरिकों को दोनों देशों में न जाने की सलाह दी है। इतना ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि इस युद्ध में किसी देश का पक्षकार नहीं बनेगा। विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से बात करते हुए तौहीद ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का बांग्लादेश पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। उनका कहना था कि वैश्विक जुड़ाव के इस दौर में कोई भी देश पूरी तरह अलग-थलग नहीं रह सकता। तौहीद ने साफ किया कि बांग्लादेश इस संघर्ष में किसी पक्ष का हिस्सा नहीं है, लेकिन व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर संभावित असर को लेकर सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने बताया कि भारत द्वारा बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांजिट सुविधा पहले ही समाप्त कर दी गई है, जिससे नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।

भारत में बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के सवाल पर तौहीद ने कहा कि अभी तक सरकार को इस संबंध में कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल बांग्ला भाषा बोलने से किसी की बांग्लादेशी पहचान साबित नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में बांग्लादेशी साबित होता है, तो सरकार उसकी वापसी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद पर बांग्लादेश की नीति के बारे में तौहीद ने कहा कि देश हमेशा से दक्षिण एशिया में शांति का समर्थक रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश बातचीत के जरिये अपने विवाद सुलझाएंगे। तौहीद ने कहा कि बांग्लादेश किसी भी तरह की मध्यस्थता की पहल फिलहाल नहीं करेगा, लेकिन यदि भारत या पाकिस्तान औपचारिक तौर पर मदद मांगते हैं, तो उस पर विचार किया जा सकता है। भारत-पाकिस्तान के संभावित टकराव में ज्यादातर बड़े मुस्लिम देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और इंडोनेशिया भारत के रुख को जायज मानते हैं और आतंकवाद के मुद्दे पर उसके साथ हैं। वहीं, तुर्की और कतर जैसे देश न्यूट्रल भूमिका में रहना चाहेंगे ताकि अपने कूटनीतिक और आर्थिक हित संतुलित रख सकें। अफगानिस्तान खुलकर पाकिस्तान विरोधी रुख अपना सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि का निलंबन, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना और राजनयिक संबंधों में कटौती शामिल है। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी दी है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इस स्थिति में मुस्लिम देशों का रुख किधर होगा। क्योंकि कहीं न कहीं उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे देश भारत के आतंकवाद के खिलाफ रुख को न केवल जायज मानते हैं बल्कि इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए जरूरी भी मानते हैं। इन देशों का समर्थन केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक हितों से भी जुड़ा है। सऊदी अरब और भारत के बीच ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। भारत, सऊदी अरब का प्रमुख कच्चा तेल आयातक है, वहीं सऊदी अरब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश कर रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की विजन 2030 में भारत एक अहम साझेदार है। यही कारण है कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी गतिविधि को खुलकर नकारता है। यूएई और भारत के संबंध पिछले एक दशक में ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 85 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा। इसके अलावा, यूएई में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार हैं, जिनके रेमिटेंस से दोनों देशों को फायदा होता आया है। ऐसे में यूएई किसी भी ऐसे पक्ष के साथ खड़ा नहीं हो सकता जो भारत की सुरक्षा के खिलाफ हो। इंडोनेशिया और इजिप्ट भी भारत के साथ कई क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडोनेशिया के साथ भारत समुद्री सुरक्षा, पर्यटन और फूड प्रोसेसिंग में सहयोग कर रहा है। वहीं मिस्र के साथ हाल ही में रक्षा और शिक्षा में नए समझौते हुए हैं। इन देशों के लिए भारत न केवल एक बड़ा बाजार है, बल्कि एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार भी है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

तुर्की और कतर न्यूट्रल रहने की कोशिश में

तुर्की जैसे देश न्यूट्रल रहने की कोशिश में हो सकते हैं। हालांकि, तुर्की पारंपरिक रूप से पाकिस्तान का समर्थक रहा है, लेकिन हाल के सालों में भारत के साथ व्यापार और पर्यटन में बढ़त के कारण वह सीधे टकराव से बचना चाहेगा। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है और किसी पक्ष विशेष के साथ खुलकर खड़ा होना उसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर असहज कर सकता है। कतर की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। भारत में बड़ी संख्या में कतर में काम करने वाले प्रवासी भारतीय हैं और दोनों देशों के बीच गैस और ऊर्जा के क्षेत्र में अहम समझौते हैं। इसके अलावा, कतर अपनी वैश्विक मध्यस्थ की भूमिका को बनाए रखना चाहता है, ऐसे में किसी एक पक्ष को खुलकर समर्थन देना उसकी कूटनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकता है।

विश्व अर्थव्यवस्था को अस्थिर करते ट्रंप

भारत सरकार को भी आगे बढ़कर अमेरिका से कोई ऐसा व्यापार समझौता कर लेना चाहिए जिससे भारत उस अस्थिरता से बचा रहे जो ट्रंप की टैरिफ नीति के चलते देखने को मिल रही है। अमेरिका से व्यापार समझौते को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयान तो आए हैं लेकिन यह कहना कठिन है कि ऐसा कोई समझौता 90 दिनों के अंदर हो जाएगा। अमेरिका में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली थी, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि वह राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएंगे, जो विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। पहले उन्होंने तमाम सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, फिर यूएसएड के तहत दी जाने वाली सहायता रोकी। इससे अमेरिका में चल रही फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार का पता चला। इसके बाद उन्होंने विभिन्न देशों पर टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाना शुरू किया। पहले उन्होंने कनाडा, मैक्सिको, चीन पर टैरिफ बढाया, फिर भारत समेत बाकी सब देशों पर। बढ़ी हुई टैरिफ दरें नौ अप्रैल से लागू करने की घोषणा कर उन्होंने विश्व अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मचा दी। उन्होंने किसी देश पर 10 तो किसी पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया। उनके इस मनमाने फैसले के जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ बढ़ा दिया। इस पर ट्रंप ने चीन पर टैरिफ और बढ़ा दिया। इसी के साथ बाकी देशों पर लगाए टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्थगित करते हुए सभी को 10 प्रतिशत टैरिफ के दायरे में ले आए। टैरिफ को लेकर अमेरिका-चीन के बीच वार-पलटवार का बचकाना और हास्यास्पद सिलसिला अब भी कायम है।

टैरिफ पर 90 दिनों की राहत के ट्रंप के फैसले के पहले ही दुनिया भर के शेयर बाजार लडखड़ा चुके थे। ट्रंप की मानें तो तमाम देशों ने टैरिफ पर उनसे बात करने की गुहार लगाई है। वह जहां अन्य देशों से टैरिफ पर बात करने को तैयार दिख रहे हैं, वहीं चीन को सबक सिखाने पर आमादा हैं, लेकिन अब चीन एक बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। उसका सामान अमेरिका समेत दुनिया भर में निर्यात होता है। इसीलिए उसे विश्व का कारखाना कहा जाता है। यह हैरानी की बात है कि ट्रंप एक कारोबारी हैं और फिर भी यह समझने को तैयार नहीं कि यदि पिछले वर्षों में अमेरिका के कारखाने अन्यत्र स्थानांतरित हो गए तो उसका कारण अमेरिका में श्रम का महंगा होना था?

खुद अमेरिकी कारोबारी ज्यादा मुनाफे के लिए अपने कारखाने अन्य देशों में ले गए। इससे अमेरिका के लोगों को सस्ता सामान मिलने लगा। भले ही ट्रंप यह मानकर चल रहे हों कि अब वे सब कारखाने अमेरिका आ आएंगे, जो बाहर चले गए थे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कारखाने रातोंरात नहीं लगते और यदि कुछ छोटे कारखाने लग भी जाएं तो महंगे श्रम के कारण उनमें तैयार वस्तुएं अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं के मुकाबले मंहगी होंगी। आखिर जो सामान विश्व के अन्य देशों में सस्ते में बन सकता है, उसे अमेरिका में महंगा बनाकर वहां के कारोबारी क्या हासिल कर लेंगे? पता नहीं किस अर्थशास्त्री ने ट्रंप को यह समझाया कि वह टैरिफ बढ़ाकर राजकोषीय घाटा कम कर लेंगे? राजकोषीय घाटा इस तरह कम नहीं होता और न ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक-दूसरे पर सामान टैरिफ के आधार पर होता है। कारखानों में तैयार वस्तुओं की लागत के पीछे अनेक कारण होते हैं। ये अलग-अलग देशों में भिन्न-भिन्न होते हैं। इनमें कच्चे माल और श्रम की उपलब्धता भी शामिल है और आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति भी। अमेरिकी समाज की तुलना विकासशील देशों के समाज से नहीं हो सकती। लगता है ट्रंप और उनके सलाहकार यह सब समझने को तैयार नहीं।

चूंकि ट्रंप के सनक भरे फैसलों का ठिकाना नहीं, इसलिए उनका असर स्टॉक मार्केट के साथ औद्योगिक गतिविधियों पर भी पड़ेगा। इससे उथल-पुथल का दौर लंबा खिंच सकता है। स्पष्ट है कि स्टॉक मार्केट के निवेशकों को संयम बरतना होगा। ट्रंप ने जिस तरह टैरिफ दरों को बार-बार बढ़ाया-घटाया, उससे उनकी जगहंसाई ही हुई। उन पर भरोसा करना कठिन हो रहा है। कोई नहीं जानता कि वह 90 दिनों तक राहत देने के अपने फैसले से कब पलट जाएं? उनके फैसलों से यह साफ है कि वह चीन से खासे नाराज हैं, लेकिन यह कहना कठिन है कि टैरिफ वार से अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा या फिर चीन को? कहीं ऐसा न हो कि उनकी मनमानी टैरिफ नीति का खामियाजा अमेरिका को ही अधिक भुगतना पड़े? ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बताते हैं, लेकिन वह भारत को टैरिफ किंग कहकर कोसते भी हैं। वह न जाने कितनी बार यह शिकायत कर चुके हैं कि भारत ने अमेरिकी मोटरसाइकिलों और विशेष रूप से हार्ले डेविडसन पर बहुत अधिक टैरिफ लगाया हुआ है।

● सुश्री नित्या

विश्वस्तरीय उत्पाद बनाने में सक्षम भारतीय कारोबारी

यदि भारतीय निर्यातक अमेरिका और अन्य देशों के बाजारों में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं तो उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता विश्वस्तरीय बनाने के साथ उनकी लागत भी कम करनी होगी, क्योंकि तभी उनके उत्पाद अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें शोध और अनुसंधान पर अधिक खर्च करना होगा। भारत सरकार को भी इसके लिए प्रयास करने होंगे कि भारतीय कारोबारी विश्वस्तरीय उत्पाद बनाने में सक्षम हों। इसके लिए श्रम कानूनों में सुधार आवश्यक हैं। हमारे देश में जो छोटे-बड़े मैन्यूफैक्चर्स हैं, उन्हें यह समझना होगा कि चीन और अमेरिका की लड़ाई उनके लिए एक अवसर है। इसका लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्रिय हो जाना चाहिए। भारत सरकार को भी आगे बढ़कर अमेरिका से कोई ऐसा व्यापार समझौता कर लेना चाहिए, जिससे भारत उस अस्थिरता से बचा रहे, जो ट्रंप की टैरिफ नीति के चलते देखने को मिल रही है। अमेरिका से व्यापार समझौते को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयान तो आए हैं, लेकिन यह कहना कठिन है कि ऐसा कोई समझौता 90 दिनों के अंदर हो जाएगा।

आर्थिकी का केंद्र बने आधी आबादी

अर्थव्यवस्था में ज्यादा महिलाओं का योगदान

कार्यबल में महिलाओं की उपस्थिति आर्थिक विकास का एक शक्तिशाली चालक सिद्ध हो रही है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की उत्पादकता बढ़ाने, नवाचारों को बढ़ावा देने और अधिक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था में ज्यादा महिलाओं का योगदान आंकड़ों से कहीं अधिक एक मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत देता है। इसके साथ ही यह सतत् आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में महिलाओं की परिवर्तनकारी भूमिका का प्रतीक भी है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश को विकसित बनाने में ही सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि लैंगिक समानता के लक्ष्य को पाने में भी सहायता मिलेगी। कामकाजी महिलाएं महिला सशक्तीकरण का पर्याय हैं। इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जो देश विकसित हैं, उनमें कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी भी अधिक है।

विश्व बैंक की हाल में आई रिपोर्ट बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनमी इन ए जेनरेशन बताती है कि 2047 तक भारत को उच्च आय वाला देश बनने के लिए औसतन 7.8 प्रतिशत की दर से विकास करना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वित्तीय क्षेत्र के साथ-साथ भूमि और श्रम सुधार भी करने होंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 से अब तक भारतीय आर्थिकी लगभग चार गुना बढ़ी है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन करीब तीन गुना हो गया है। इसी दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 2000 में 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 3.4 प्रतिशत हो गई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट इस पहलू पर जोर देती है कि 2047 तक भारत को महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को 35.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करके जनसांख्यिकीय लाभ उठाना चाहिए।

पिछले छह वर्षों में महिला रोजगार से संबंधित आंकड़े आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, बेरोजगारी दर में कमी, कार्यबल में शिक्षित महिलाओं की बढ़ती संख्या और आय में लगातार वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। दुनियाभर के आंकड़े यह बता रहे हैं कि महिलाओं द्वारा संचालित उद्यम निरंतर बढ़ रहे हैं और महिलाएं घरेलू आय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आर्थिक विकास को गति देने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यम (एमएसएमई) वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुताबिक एमएसएमई वैश्विक अर्थव्यवस्था में 90 प्रतिशत से अधिक व्यवसायों का **प्रतिनिधित्व** करते हैं, जो 70 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देते हैं। भारत की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान वित्त वर्ष 2017-18 में 29.7 प्रतिशत था, जो 2022-23 में बढ़कर 30.01 प्रतिशत हो गया।

पुरुषों के एकाधिकार वाले उद्यमों में भी महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है। इसका प्रमाण यह है कि सात मार्च, 2025 तक कुल एमएसएमई पंजीकरण में जहां पुरुषों का प्रतिशत 59.52 था, वहीं महिलाओं का 40.10 प्रतिशत। ये आंकड़े मिसाल हैं कि महिलाएं आर्थिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए तत्पर हैं। देश में लगभग 15 प्रतिशत यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संस्थापक कम से कम एक महिला है। महिलाओं के नेतृत्व वाले इन यूनिकॉर्न का संयुक्त मूल्य 4,000 करोड़ रुपए से अधिक है। विश्व बैंक के शोध पत्र फोस्टरिंग फीमेल ग्रोथ आंत्रप्रेन्योरशिप इन रूरल इंडिया के अनुसार महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने से ग्रामीण भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर और आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा मिल सकता है। उसके अनुसार अगर इस क्षेत्र में प्रयासों में तीव्रता लाई जाए तो 2030 तक महिलाओं के स्वामित्व वाले 3.95 करोड़ उद्यम हो सकते हैं। बैन एंड कंपनी और गूगल की एक संयुक्त रिपोर्ट-वुमन आंत्रप्रेन्योरशिप इन इंडिया-पावरिंग द इकोनमी विद हर के अनुसार भारत में महिला उद्यमी 2030 तक 15-17 करोड़ नौकरियां पैदा कर सकती हैं, जो पूरी कामकाजी आबादी के लिए जरूरी नई नौकरियों के 24 प्रतिशत से अधिक हैं। भारत के आर्थिक विकास में ग्रामीण आर्थिकी वह आधार स्तंभ है, जिसकी मजबूती से विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार वाले श्रमिकों-नियोक्ताओं की हिस्सेदारी 2017-18 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 31.02 प्रतिशत हो गई है, जो स्वतंत्र कार्य और उद्यमिता की ओर महत्वपूर्ण कदम है।

नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार उन सभी क्षेत्रों में हुआ है, जहां सरकारी सहायता प्रमुख रही है। राष्ट्रीय स्तर पर 15 मंत्रालयों के तहत 70 केंद्रीय योजनाएं उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता में सुधार लाने में योगदान देने वाली विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है, जिसमें सबसे आशाजनक है प्रधानमंत्री कौशल भारत योजना। लगभग नौ करोड़ महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। ऐसी योजनाएं राज्य सरकारें भी संचालित करें। इसके साथ ही उन्हें कानून एवं व्यवस्था पर भी अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने समक्ष उपस्थित संभावनाओं को भुनाने के लिए प्रेरित होती हैं। महिला श्रमबल भागीदारी 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गई है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार, इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कृषि रोजगार 2017-18 में 73.02 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 76.9 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार यह कार्य बल के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रवेश की एक शक्तिशाली लहर को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त महिला बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट नौकरी की उपलब्धता में वृद्धि का संकेत देती है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

रामचरितमानस का नैतिक और सामाजिक प्रभाव

गोस्वामी तुलसीदास, जिन्हें कवि कुलगुरु के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1554 (1532 ईस्वी) में हुआ माना जाता है। उनका जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था, जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है परंतु उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सोरों शूकरक्षेत्र (वर्तमान कासगंज) या चित्रकूट के निकट राजापुर नामक स्थान में हुआ माना जाता है। हालांकि, राजापुर को तुलसीदास का प्रमुख जन्मस्थान माना जाता है।

बाबा तुलसीदास की कृतियों ने न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया बल्कि सामाजिक जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तुलसीदास के समय में समाज अनेक प्रकार की बुराइयों, सामाजिक विषमताओं और धार्मिक कट्टरता से ग्रसित था। इन समस्याओं से उबरने और समाज में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए तुलसीदास ने अपनी कृतियों के माध्यम से एक अद्वितीय योगदान दिया।

धर्म और नैतिकता का प्रचार

धर्म हेतु अवतरेउं प्रभु
शेष महेश धरैं जासु फल।
लोक बेद हितु तेहि समय,
सब कीन्ह कृपानिधि करि कल्याण।

इस चौपाई में तुलसीदास ने भगवान राम के अवतार के धर्मस्थापन हेतु होने का वर्णन किया है। इससे समाज में धर्म और नैतिकता की स्थापना का संदेश मिलता है। तुलसीदास की काव्य रचनाओं में मुख्य रूप से धर्म और नैतिकता के प्रति जागरूकता का संदेश है। रामचरितमानस में उन्होंने भगवान राम के आदर्श जीवन का वर्णन किया है, जो एक आदर्श राजा, पुत्र, पति, और भाई के रूप में स्थापित हैं। राम के चरित्र के माध्यम से उन्होंने सत्य, धर्म और मर्यादा की शिक्षा दी। यह समाज को एक आदर्श और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है।

सामाजिक समरसता का संदेश

तुम्ह समान रघुबीर सहाई।
अतर पुनीत प्रभु निषाद घर आयी।।
देखि राम सुदामा कर पाती।
हरष बिकल हृदयं अकुलाती।।

इस चौपाई में तुलसीदास ने भगवान राम द्वारा निषादराज के प्रति दिखाए गए प्रेम और सम्मान का वर्णन किया है, जो जातिगत भेदभाव को खत्म करने का संदेश देता है। तुलसीदास ने अपने समय में समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने रामचरितमानस में स्पष्ट किया कि भगवान राम ने शबरी और निषादराज जैसे निम्न जाति के व्यक्तियों से प्रेम और सम्मान किया। यह संदेश समाज में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का था। तुलसीदास ने यह दिखाया कि ईश्वर के लिए सभी समान हैं, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या धर्म के हों।

अंधविश्वासों, धार्मिक कट्टरता का खंडन-

काहू न कोउ सुख दुःख कर दाता।
निज कृत करम भोग सब भ्राता।।

तुलसीदास यहां कर्म और उसके फल की बात करते हैं। यह दोहा अंधविश्वासों और भाग्यवाद को खंडित करते हुए कर्म की प्रधानता को दर्शाता है। तुलसीदास ने समाज में फैले अंधविश्वासों और धार्मिक कट्टरता का खंडन किया। उन्होंने भक्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया और कहा कि केवल भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उन्होंने कर्मकांड और दिखावे की पूजा के बजाय सत्य, प्रेम, और समर्पण को महत्व दिया। उनकी भक्ति आंदोलन ने समाज को एक नई दिशा दी और धार्मिक चेतना को नया आयाम दिया।

भाषा का विकास और प्रसार

संस्कृत भाष्य बिनु कछु नाहीं।
बांचत न अधिक जिन ग्यान साधी।
तुलसी की निज भाषा कछु नहीं,
हरि यश गावहिं सुनि सुख लाहीं।।

इस चौपाई में तुलसीदास ने संस्कृत के साथ-साथ आमजन की भाषा को महत्व दिया और इसे साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। इसने न केवल साहित्यिक वर्गों में बल्कि सामान्य जनजीवन में भी गहरा प्रभाव डाला। उनकी भाषा सरल, सुगम और हृदयग्राही थी, जिससे उनका संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचा। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और इसे जनमानस की भाषा बनाया।

राष्ट्रभक्ति और सामाजिक न्याय का संदेश

रामराज्य का एक चरित्र न्यारा।
जहाँ न काम क्रोध न विषमता बारा।।
सब नर करहिं परस्पर प्रीती।
चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीति।।

इस चौपाई में तुलसीदास ने रामराज्य का आदर्श प्रस्तुत किया है, जहां न्याय, समानता, और सामाजिक सद्भाव की स्थापना होती है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति और सामाजिक न्याय का संदेश भी दिया। रामराज्य का उनका आदर्श समाज में न्याय, शांति और समृद्धि की स्थापना का प्रतीक है। उन्होंने यह दिखाया कि जब शासक धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, तब समाज में सुख और समृद्धि आती है। यह संदेश आज भी प्रासंगिक है और सामाजिक जागरूकता के लिए प्रेरणा स्रोत है।

विश्ववंद्य संत गोस्वामी तुलसीदास भारतीय काव्य साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय कवि हैं। उनके द्वारा सृजित रामचरितमानस भारतीय साहित्य ही नहीं विश्व साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। संपूर्ण भारतीय साहित्य में जितनी लोकप्रियता व ख्याति रामचरितमानस को मिली, उतनी दूसरी किसी रचना को नहीं। मानस ने गोस्वामी जी को विश्व विश्रूत बनाया और तुलसी ने पूरे विश्व को शांति-सद्भाव का पाठ पढ़ाया। मानस की लोकप्रियता वैश्विक स्तर पर इतनी बढ़ी कि विश्व की तमाम समृद्ध भाषाओं में यह अनुदित हुआ। यह महाकाव्यात्मक कृति विश्व मानवता की सरस सलिला पूरे जगत में प्रवाहित कराने में सक्षम हुआ। रामचरितमानस हिंदी का सर्वोत्कृष्ट राम काव्य है। इस अमर काव्य की रचना चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार संवत् 1631 विक्रमी में हुई थी। यह तुलसी की साहित्यिक मर्मज्ञता, काव्य कुशलता एवं भाव गंभीरता का चरम निदर्शन है। मानस में राम-जन्म से लेकर राम-राज्यारोहण तक की कथा सरस शैली में वर्णित है। संपूर्ण काव्य सात सोपानों में विभाजित है, जो प्रसंगों के शृंखलाबंधन के साथ राम कथा को गतिशील बनाता है। इसके राम-जन्म से लेकर राम-राज्यारोहण तक की कथा को आदि भाग, वन गमन से लेकर सीता हरण तक को मध्य भाग तथा सीता हरण से लेकर रावण वध और राम राज्य की स्थापना को अंतिम भाग में रखा जा सकता है। इस चरित काव्य में क्षत्रिय कुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानवीय चारित्रिक विशेषताओं के साथ प्रतिष्ठित हैं।

● **ओम**

अजनबी की मुस्कान

काव्या हमेशा से अपने ऑफिस के काम में डूबी रहती थी। उसकी दिनचर्या बेहद व्यस्त और बोरियत भरी थी। एक दिन, जब वह अपने रोजाना के रूटीन से थकी हुई थी, उसने सोचा कि वह कुछ देर के लिए पार्क में जाकर बैठ जाए।

पार्क में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और लोग अपने-अपने कामों में मसरूफ थे। काव्या एक बेंच पर बैठकर अपने विचारों में खो गई। तभी, उसके पास एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसे मुस्कुराते हुए एक गुलाब का फूल थमा दिया। काव्या चौंकी और उसकी तरफ देखने लगी। बच्चे की मुस्कान में इतनी मासूमियत थी कि काव्या का मन हल्का हो गया। उसने बच्चे से पूछा, ये फूल क्यों दिया?

बच्चा हंसते हुए बोला, मां कहती है, मुस्कान सबसे अच्छा तोहफा होती है। और वह फिर से खेलते हुए चला गया। काव्या को समझ में आ गया कि कितनी छोटी चीजें जीवन में बड़ा फर्क ला सकती हैं। उस एक अजनबी की मुस्कान ने उसकी जिंदगी की थकान मिटा दी थी।

- अज्ञात

दीया की लौ

गांव के एक छोटे से घर में रोशनी नाम की एक लड़की रहती थी। उसके नाम की तरह ही उसका दिल भी हमेशा दूसरों के लिए रोशनी फैलाता था। हर साल दीपावली पर वह अपने घर के आंगन में एक दीया जलाती थी, और उसकी लौ को बहुत ध्यान से देखती थी।

उसकी दादी ने उसे एक बार बताया था कि दीये की लौ में बहुत कुछ छिपा होता है। जब वह लौ तेज होती है, तो इसका मतलब होता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इस बार, जब रोशनी ने दीया जलाया, उसकी लौ बहुत ही तेज और स्थिर थी। रोशनी के दिल में आशा की किरण जागी।

कुछ दिनों बाद, उसके पिता को एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। रोशनी ने तब सोचा कि वह दीया सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, बल्कि उसमें सच्ची उम्मीद की शक्ति थी।

- अज्ञात

संगीत की माया

आकाश एक छोटे से शहर का साधारण लड़का था, लेकिन उसकी आवाज में जादू था। जब भी वह गाता, लोग उसकी आवाज में खो जाते थे। एक दिन, शहर में एक बड़ा संगीत मुकाबला होने वाला था, और आकाश को मौका मिला उसमें हिस्सा लेने का। लेकिन उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं थी, और आकाश असमंजस में था कि वह प्रतियोगिता में जाए या मां के पास रहे।

आखिरकार, उसकी मां ने उसे समझाया, संगीत तुम्हारी आत्मा है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे, तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। मां की बातों ने आकाश को प्रेरित किया, और वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया।

उसने मंच पर जाकर जैसे ही गाना शुरू किया, दर्शकों के दिलों को छू लिया। उसकी मां भी उसे सुनने आई थी, और उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। आकाश ने प्रतियोगिता जीत ली, और वह समझ गया कि संगीत ही उसकी मां की सच्ची दवा थी।

- अज्ञात

वंदना की विदाई

> वंदना ने देश के लिए 300 से ज्यादा मैच खेले हैं। उन्होंने टोक्यो ओलम्पिक 2020 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ गोल की हैट्रिक लगाई थी। ऐसा करने वाली वह पहली महिला खिलाड़ी बनीं।

हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 15 सालों तक भारत के लिए मैदान पर अपने अद्वितीय खेल का प्रदर्शन कर अंतरराष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया है। अपनी हिम्मत, समर्पण और उत्कृष्टता से कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनीं कटारिया ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वंदना ने अपने करियर में केवल हॉकी नहीं खेला, वे भारत सरकार के बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान से भी जुड़ी रहीं और सामाजिक सरोकरों के लिए भी भरपूर योगदान दिया। खेल विश्लेषकों का कहना है कि वंदना कटारिया की यात्रा न केवल एक खिलाड़ी के रूप में प्रेरणादायक रही हैं, बल्कि उनके योगदान से भारतीय महिला हॉकी को भी वैश्विक मंच पर एक नई पहचान मिली है।

भारतीय हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। वंदना ने देश के लिए 300 से ज्यादा मैच खेले हैं। उन्होंने टोक्यो ओलम्पिक 2020 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ गोल की हैट्रिक लगाई थी। ऐसा करने वाली वह पहली महिला खिलाड़ी बनीं। वंदना उत्तराखंड के हरिद्वार के रोशनाबाद की रहने वाली हैं। वह अपने खेल से तब चर्चा में आईं जब उन्होंने जूनियर विश्वकप 2013 में सबसे ज्यादा पांच गोल किए थे। इस विश्वकप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में खेलने का मौका मिला। भारत के लिए खेलते हुए उन्होंने 2014 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद 2018 एशियन गेम्स में सिल्वर और 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वंदना ने कप्तान के तौर पर भारत को एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2016 में गोल्ड मेडल जिताया। वहीं 2018 में सिल्वर मेडल जीतने के साथ उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी जीता था, तो 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और टोक्यो ओलम्पिक 2020 में चौथे स्थान पर फिनिश किया था जिसमें वंदना ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी।

वंदना द्वारा भारतीय हॉकी को दिए गए योगदानों और शानदार खेल के लिए उन्हें कई अवॉर्ड्स भी दिए गए हैं। जिसमें से उन्हें 2021 में अर्जुन अवॉर्ड, 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वंदना ने भारत के लिए खेलते हुए कुल 320 मैचों में 158 गोल अपने नाम किए हैं। इस तरह एक लंबी और शानदार यात्रा के बाद, 32 वर्षीय वंदना ने 15 सालों तक भारत के लिए मैदान पर अपने अद्वितीय खेल का प्रदर्शन कर अंतरराष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया है। अपनी हिम्मत, समर्पण और उत्कृष्टता से कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनीं वंदना ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वंदना ने अपने करियर में केवल हॉकी नहीं खेला, वे भारत सरकार के बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान से भी जुड़ी रहीं और सामाजिक सरोकारों के लिए भी भरपूर योगदान दिया।

खेल विश्लेषकों का कहना है कि वंदना का यह विदाई बयान उनके बेहतरीन करियर की समाप्ति नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाता है। उनकी यात्रा न केवल एक खिलाड़ी के रूप में प्रेरणादायक रही है, बल्कि उनके योगदान से भारतीय महिला हॉकी को भी वैश्विक मंच पर एक नई पहचान मिली है। गौरतलब है कि भारत को टैलेंट की खान कहा जाता है। छोटे घर से निकलने वाले बच्चे देश की शान बनते हैं। दुनियाभर में तिरंगे का मान रखते हैं। अब भारतीय महिला टीम की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया को ही देखें तो वह उत्तराखंड (तब उप्र) के हरिद्वार के रोशनाबाद में 15 अप्रैल 1992 को जन्मी इस खिलाड़ी ने दुनियाभर में अपनी हॉकी की जादूगरी दिखाई। टोक्यो ओलम्पिक 2020 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाजुक स्थिति में हैट्रिक लगाकर जीत दिलाई तो ओलम्पिक में पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी होने का सम्मान जुड़ा। 2021 में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख अभियान बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी बनीं और शून्य से शिखर तक का सफर तय कर अब हॉकी से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। भारत के लिए 320 मैच खेल चुकी स्ट्राइकर कटारिया ने भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेले हैं। वर्ष 2009 में सीनियर टीम में पदार्पण करने वाली वंदना कटारिया ने अपने करियर का आखिरी मुकाबला भुवनेश्वर में एफआईएच प्रो लीग में भारत के लिए खेला।

● आशीष नेमा

'मैं सर्वश्रेष्ठ स्तर पर हूं...'

वंदना ने रिटायरमेंट लेते हुए कहा, आज भारी लेकिन कृतज्ञ मन से मैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी से विदा ले रही हूं। यह फैसला सशक्त करने वाला और दुखी करने वाला दोनों है। मैं इसलिए नहीं हट रही हूं क्योंकि मेरे अंदर की आग मंद पड़ गई है या मेरे भीतर हॉकी नहीं बची है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपने करियर के शिखर पर संन्यास लेना चाहती हूं, जबकि मैं अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर हूं। उन्होंने आगे कहा, यह विदाई थकान की वजह से नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय मंच को अपनी शर्तों पर छोड़ने का एक विकल्प है, मेरा सिर ऊंचा रहेगा और मेरी स्टिक अभी भी आग उगल रही होगी। भीड़ की गर्जना, हर गोल का रोमांच और भारत की जर्सी पहनने का गर्व हमेशा मेरे मन में गूंजता रहेगा। अपनी साथी खिलाड़ियों, अपनी बहनों से मैं यही कहूंगी कि आपके लगाव और विश्वास ने मुझे बल दिया। मेरे कोचों और मेंटर्स ने अपनी सूझ-बूझ और मुझ पर भरोसे के सहारे मेरे करियर को तराशा।

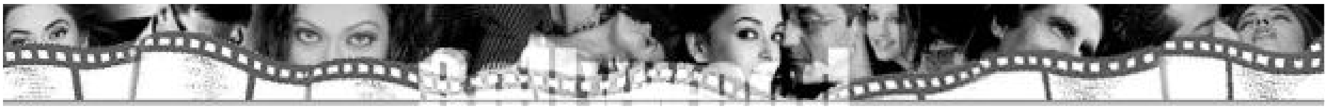

न अनिल कपूर, न सलमान खान, ये सुपरस्टार था माधुरी का लकी चार्म

ऋषि कपूर तो साबित हुए थे पनौती

माधुरी दीक्षित को देखते ही फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती हैं। खासतौर पर एक्ट्रेस का डांस देखकर तो लोग मर मिटने को तैयार हो जाते थे। आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी उनकी खूबसूरती कुछ कम नहीं हुई है। करियर में हर हीरो के साथ काम कर चुकीं माधुरी की जोड़ी सबसे ज्यादा एक ही सुपरस्टार के साथ हिट हुई थी।

अपने अब तक के करियर में माधुरी ने कई हीरो के साथ ऑनस्क्रीन जोड़ी बनाई है। जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ शामिल हैं। 90 के दशक में माधुरी हीरो से भी ज्यादा फीस लेने वाली हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में गिनी जाती थीं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। कई हीरो के साथ तो उनकी जोड़ी काफी पसंद की जाती थी। माधुरी दीक्षित ने खासतौर पर सलमान खान के साथ 4 फिल्मों में काम किया है। इनमें से उनकी 3 फिल्में हिट साबित हुई थी। इनमें से एक हम आपके हैं कौन तो बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। इसके अलावा अनिल कपूर के साथ भी माधुरी दीक्षित की जोड़ी काफी हिट मानी जाती थी। इतना ही नहीं अकेले ऋषि कपूर ऐसे थे, जिनके साथ माधुरी दीक्षित जब-जब नजर आई फिल्में फ्लॉप ही साबित हुईं। इतना ही नहीं ऋषि कपूर हिट की गारंटी थे और माधुरी ब्लॉकबस्टर की, फिर भी दोनों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुईं।

बॉक्स ऑफिस को रख दिया हिलाकर... *इकलौते संजय दत्त ऐसे सुपरस्टार थे, जिनके साथ माधुरी दीक्षित की जोड़ी ऐसी हिट थी, जब-जब दोनों साथ पर्दे पर नजर आए, हर बार बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया। संजय एक्ट्रेस के लिए लकी चार्म साबित हुए थे। दोनों ने साथ में 11 फिल्मों में काम किया है। इन 11 में से 5 हिट और 1 एवरेज और बाकी फ्लॉप फिल्में शामिल थीं। जैकी श्रॉफ के साथ भी उन्होंने 5 से 6 हिट फिल्मों में काम किया था।*

मीना कुमारी नहीं, 1 पाकिस्तानी थीं धर्मेंद्र का पहला प्यार... बंटवारे ने किया जुदा

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र दशकों से सिनेमा में सक्रिय हैं। शोले, सीता और गीता जैसी शानदार फिल्मों के अलावा धर्मेंद्र अपने लव अफेयर के लिए मशहूर रहे। हेमा मालिनी से शादी से पहले धर्मेंद्र का दिल मीना कुमारी जैसी अदाकारा पर आया था, हालांकि वे भी उनका पहला प्यार नहीं थीं।

धर्मेंद्र के इस सीक्रेट लव का खुलासा तब हुआ था, जब वे सलमान खान के शो दस का दम में पहुंचे थे। दिग्गज एक्टर ने तब बचपन के दिनों का जिक्र करते हुए अपनी पहली लव स्टोरी के बारे में बताया था। जिनका नाम हमीदा था। धर्मेंद्र के पहले प्यार की शुरुआत पंजाब की गलियों में हुई थी और 1947 में देश के बंटवारे के बाद इसका अंत हो गया था।

स्कूल टीचर की बेटी पर हुए फिदा... *हमीदा कोई फिल्म स्टार नहीं थीं। वे स्कूल में धर्मेंद्र की सीनियर थीं और उनकी स्कूल टीचर की बेटी थीं। धर्मेंद्र का उनसे पहला इंटरैक्शन बड़ा मासूम था। वे उन्हें पढ़ाई में मदद करती थीं। वे कांपते हाथों से उन्हें अपनी नोटबुक देती थीं। भारत-पाकिस्तान के बंटवारे ने धर्मेंद्र की लव स्टोरी को यादों में बदल दिया। हमीदा और उनका परिवार पाकिस्तान चला गया और अपने पीछे धर्मेंद्र को दुखी छोड़ गया। एक्टर ने दोबारा उन्हें नहीं देखा, लेकिन यादें दिल में हमेशा ताजा रहीं। 89 साल के धर्मेंद्र आगे चलकर बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए। उन्होंने टॉप एक्ट्रेस के साथ पर्दे पर रोमांस किया और अपने अफेयर के किस्सों की वजह से सुर्खियों में बने रहे।*

भारत का सबसे महंगा कॉमेडियन... राजेश खन्ना-अमिताभ बच्चन से ज्यादा थी फीस

आज इंडिया में हाईएस्ट पेड सुपरस्टार्स की भरमार है। लेकिन आज हम आपको ऐसे कॉमेडियन के बारे में बताते हैं, जो सिर्फ कैमियो रोल्स के लिए विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे बड़े सितारों से ज्यादा फीस लेते थे। हम जिनकी बात कर रहे हैं, उनका नाम है महमूद। महमूद ने 1940 के दशक में किस्मत फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। 1950 के दशक में सीआईडी और प्यासा जैसी फिल्मों में कॉमिक किरदारों से अपनी दमदार पहचान बनाई। वैसे शुरुआत से उनकी लीड रोल निभाने की इच्छा थी। 1960 के दशक में महमूद ने खुद को न केवल भारत के प्रमुख कॉमेडियन के रूप में स्थापित किया, बल्कि एक सफल स्टार भी बने।

सबसे ज्यादा फीस लेते थे महमूद... *60 के दशक के आखिर में महमूद देश के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, महमूद उस समय फिल्मों में सिर्फ दो हफ्ते के कैमियो के लिए 7.5 लाख रुपए फीस लेते थे। उस समय के टॉप एक्टर्स जैसे सुनील दत्त, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार पूरी फिल्म के लिए 5 लाख से कम फीस लेते थे। यहां तक कि सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन भी 70 के दशक के मध्य तक 7.5 लाख रुपए का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे। बताया जाता है कि 80 के दशक तक महमूद अपने कैमियो के लिए उतनी फीस लेते थे, जितनी सलमान खान और आमिर खान अपनी शुरुआती फिल्मों के लिए नहीं ले पाते थे।*

बड़ा होकर समझदार बनेगा

हम बचपन से काफी रचनात्मक थे और रचनात्मक अभिव्यक्ति में हमारा काफी विश्वास था क्योंकि सिर्फ रचनात्मक होना ही काफी नहीं होता। हमारी पहली रचना गूढ़ विचारों के रूप में तब सामने आई जब हमने उन्हें घर की सफेद दीवारों पर काफी दार्शनिक अंदाज में व्यक्त किया था। अलग व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव कुछ अलग ढंग से पड़ा था। मां हमारी रचनात्मकता से अभिभूत होकर भावविभोर हो गईं थीं, पिताजी ने मुस्कुराकर कहा था चिंता मत करो, बड़ा होकर जब समझदार बनेगा तब यह हम जैसों की तरह ही इस समाज में घुलमिल कर उसी का एक हिस्सा हो जाएगा। हमारे दादाजी, उन्हें तो काफी सदमा लगा था और तुरंत ही उन्होंने ज्योतिषी को बुलवा भेजा था।

ज्योतिषी के अनुसार हमारे जन्म के समय नक्षत्रों की स्थिति कुछ वैसी ही थी जैसी कि भक्त तुलसीदास के लिए, पर बच्चे की फितरत कबीरदास जैसी होगी, कुल मिलाकर परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे दादाजी को चैन कहां, उन्होंने तो घर पर अखंड रामायण बिठवा दी ताकि हमारे ऊपर से बुरे ग्रहों का साया उठ जाए। अगले ही दिन उस सफेद दीवार पर हमारी कलाकृति की जगह उन टोटकों ने ले ली थी जो हमारे भले के लिए डाले गए थे। कभी-कभी हम सोचते हैं कि गुफाओं में बने वो पाषाणकालीन चित्र कहीं टोटके ही तो नहीं जिसे हमारे तथाकथित सभ्य समाज ने कला का नाम दे दिया है और उनके छायाचित्र अपने ड्राइंगरूम में लटकाकर ड्राइंगरूम को एथनिक टच देने में लगे रहते हैं।

बात उस समय की है जब हमने करीब दो-ढाई सौ पन्ने जमा कर लिए थे अपनी कविताओं के, बस समस्या यही थी कि मूल्यांकन किससे करवाया जाए। एक दिन बातों-बातों में हमने अपनी इस समस्या का जिक्र मित्र हनुमान से किया तो वह फट से फूट पड़ा, एक बात मानो गुरू, तुम पंडित जी के पास चले जाओ।

कौन वो मांटेसरी वाले, हमने पूछा।

हां वही याद नहीं है पिछले साल रामलीला के टाइम खूब कविता बोले थे और खूब तालियां पाए थे, कविता वो लिखें और झेले सारा गांव।

हनुमान ने चुटकी ली और चलता बना पर हमें अवश्य सोच में डाल गया। वास्तव में क्या तालियां बजाई थी श्रोताओं ने उनके काव्यपाठ के दौरान। उनकी हर कविता के बाद पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता इस आशा से कि ये अंतिम होगी पर पंडित जी तालियों की गर्जना से प्रेरित हो सावन-भादों की झड़ी की तरह एक नई कविता शुरू कर देते। हद तो तब हो गई जब उनकी एक कविता के दौरान श्रोता सारे समय ताली ही बजाते रहे, यह धुन निकालते रहे और नहीं अब और नहीं और उस कविता को अंतिम बनाकर ही छोड़ा। पंडित जी को भी लगा कि तालियों की निरंतर गड़गड़ाहट ही उनकी कविताओं को सच्ची श्रद्धांजलि है, तभी जाकर वो रुके।

खैर अब कोई और चारा भी हमारे पास न था। पंडित जी के पास तो जाना ही था। काफी हिम्मत जुटाई, जुटानी क्या थी हनुमान ने दिलाई। पन्ने संभाले और एक दोपहर पहुंच गए पंडितजी के घर। सबसे पहले पंडितजी के पालतू कुत्ते ने सूंघकर, दुम हिलाकर और फिर अपने दो पैर हमारे ऊपर टिकाते हुए, हमारा मुंह चाटकर स्वागत किया ओर हमें बैठक की ओर ले गया। पंडितजी ध्यानमग्न होकर अपनी उंगलियों से नाक के बालों से खेल रहे थे।

कुत्ते की कूं-कूं से उनकी तंद्रा टूटी तो बोले अरे बेटा तुम! कहो कैसे आए? घर पर सब लोग मजे में हैं? ऐसा लगा कि उन्हें उत्तर में कोई रुचि नहीं है। प्रश्न पूछना था सो पूछ लिया। यह तो कुछ वैसा ही व्यवहार था जैसा कि विपक्ष का संसद में होता है। जी... वो जरा... आपको कुछ दिखाने लाया था। कुछ कविताएं लिखी हैं, हमने सोचा आपको दिखा लें।

दिखाओ, अचानक गंभीर हो गई उनकी मुखमुद्रा से गंभीर स्वर निकला। एक पल को तो हमें लगा कि कहीं कविताओं को लेकर हमने उनके कॉपीराइट को तो चुनौती नहीं दे दी। खैर हमने पन्ने उनके सामने सरका दिए। उन्होंने अपनी ऐनक नाक पर चढ़ाई और काफी देर तक अपनी थूक लगी उंगलियों से पन्ने पलट-पलट कर ध्यानमग्न होकर पढ़ने के बाद उन्होंने एक लंबी जम्हाई ली और उसी दौरान बोलते हुए कहा बाकी सब तो ठीक है पर तुम्हारी कविताओं में जीवंतता नहीं है।

जी..., हम बस इतना ही कह पाए थे कि पंडितजी बीच में ही टोकते हुए कहने लगे, अरे भाई कहां तुम नगरपालिका और समाज के चक्करों में उलझे हुए हो। अभी तुम लड़के हो कुछ रूमानियत पैदा करो अपनी कविता में। इतनी गंभीरता उस उम्र में अच्छी नहीं।

इस बार हमने प्रश्नवाचक मुद्रा बनाई और बोलना चाहा पर पंडित जी तो अपने आप ही में खोए हुए थे, भला हमारी तरफ क्यों देखते। उन्होंने बोलना जारी रखा, श्रृंगार रस के बारे में पढ़ा है? उनके प्रश्न में प्रश्न कम शायद आश्चर्य अधिक था। पंडित जी का बोलना फिर शुरू हो चुका था, यही तो समस्या है आजकल के छात्रों और शिक्षा की, कि जो सीखते हैं उसका उपयोग नहीं करते और जिसका उपयोग करते हैं पता नहीं कहां से सीखकर आते हैं। हम लोग तो अपने विद्यालयों में ऐसी शिक्षा देते नहीं।

कुछ सीखने की बात जब आई है तो हम आपको यह बात बता दें कि हमारे अध्यापक भी हैरान हो जाते थे हमारी परीक्षा पुस्तिकाओं को देखकर कि लड़कों ने जो कुछ भी लिखा है आखिर सीखा कहां से। उनकी समस्या का भी निदान हो ही जाता, यदि हर परीक्षा पुस्तिका में विद्यालय के नाम के साथ-साथ सीखने की जगह के बारे में भी लिखा जाता। कुछ भोंदू किस्म के लड़कों को छोड़कर बाकी के सारे उस जगह में कन्या पाठशाला ही लिखते।

● **अंशुमान अवस्थी**

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

M/S NIHAL SUNARE
Consultant

Nariman Point Colony, Indore